राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 282

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, बुधवार, 20 मार्च, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

नवजोत सिद्धू ने छोड़ा चुनावी रण, आइपीएल में करेंगे कमेंट्री >> 4

जागरण विशेष
नवाचारी अधिकारी

बढ़ाया हाथ तो महिलाओं को मिला रोजगार

मुजफ्फरपुर: घर के काम तक सिमटीं महिलाओं को बस दिशा व प्रोत्साहन की जरूरत थी। जैसे ही दिशा मिली तो छह लाख से अधिक जीविका दीदियां रोजगार से जुड़ गईं। जबकि कई उद्यमी बन गईं। ● पेज-7

संपादकीय

गोपनीयता के आवरण में चुनावी चंदा: समय के साथ देश में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन चुनावी चंदे में पारदर्शिता का अभाव जस का तस कायम है। **सुरेंद्र किशोर** का दृष्टिकोण।

नागरिकता कानून पर बेतुकी आपत्ति: तीन पड़ोसी देशों के सभी लोगों को सीएए के दायरे में लाने की मांग कुतर्क के अलावा और कुछ नहीं। **राजीव सचान** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: पिछले दिनों भारत को पहली एआइ शिक्षिका मिली। केरल के तिरुअनंतपुरम के एक स्कूल में पेश की गई इस रोबोट शिक्षिका का नाम 'आइरिस' है। शिशिर शुक्ला का विश्लेषण।

चेहरा बदलने की रणनीति: विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की भाजपा की रणनीति से अवगत करा रही है अनुराग अग्रवाल की हरियाणा डायरी। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का

सुरक्षा और सतर्कता भरी हो होली

सतर्कता ही टीबी से बचाव ● पेज-13

महासमर 2024

भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस, भूपेश के साथ फंसे कई नेता पेज>>3

अमेरिका में राजदूत रहे संधू भाजपा में शामिल पेज>>4

कांग्रेस ने 11 राज्यों की 80 सीटों पर तय किए प्रत्याशी पेज>>5

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को

नई दिल्ली, प्रेट्र: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित करने का मंगलवार को फैसला किया। परीक्षा अब 16 जून को होगी। चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। वोटों की गिनती चार जून को होगी। यूपीएससी ने कहा, आगामी आम चुनाव के कार्यक्रम के कारण आयोग ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा -2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 1,056 होने की उम्मीद है।

सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं विपक्षी नेता : मोदी

- कहा, अन्य धर्म से जुड़े प्रतीकों के विरुद्ध नहीं बोलते एक भी शब्द
- तमिलनाडु के सेलम में मंच पर 11 शक्ति अम्मा के साथ नजर आए पीएम
- जयललिता के अपमान को द्रमुक की नारी विरोधी मानसिकता से जोड़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शक्ति के विनाश के राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस समेत पूरे आइएनडीआइए पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव को शक्ति के विनाशक और शक्ति के उपासक के बीच बता रहे मोदी मंगलवार को तमिलनाडु के सेलम में मंच पर शक्ति स्वरूप में 11 महिलाओं (शक्ति अम्माओं) के बीच नजर आए। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उदयनिधि स्टालिन, ए. राजा से लेकर राहुल गांधी तक विपक्षी नेता जानबूझकर सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं, अन्य धर्म से जुड़े प्रतीकों के विरुद्ध वे एक शब्द भी नहीं बोलते। हिंदू धर्म के विरुद्ध विपक्षी नेता का हर बयान बहुत सोचा-समझा है। उन्होंने कहा कि शक्ति का विनाश करने के लिए निकली कांग्रेस, द्रमुक समेत अपने सहयोगियों के साथ खत्म हो जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सलेम में माताओं और बहनों को फिर शक्ति स्वरूपा बताते हुए तमिलनाडु में मदुरई से लेकर कन्याकुमारी तक देवी से जुड़े मंदिरों को गिनाया। याद दिलाया कि सुब्रह्मण्यम भारती ने अपनी कविताओं में भारत को मातृ देवी के रूप में प्रस्तुत किया था। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब है मातृ शक्ति, नारी शक्ति; लेकिन कांग्रेस और द्रमुक वाला आइएनडीआइए कहता है कि वे इसका विनाश कर देंगे। हमारे महाकाव्य इस बात के प्रमाण हैं कि जो लोग शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के महिला होने के कारण द्रमुक द्वारा किए अपमान का भी जिक्र किया। कहा कि यह कांग्रेस और द्रमुक की नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। रैली में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं की ओर इंगित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों को भी गिनाया।

तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के साथ समझौते के बाद उनके नेता भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे। राजग नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने भाषा के मुद्दे पर भाजपा और तमिलनाडु के बीच खाई को भी पाटने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने भारत की आजादी के प्रतीक बने सेंगोल का भी जिक्र किया। कहा कि तमिलनाडु के मठों से जुड़े सेंगोल को संसद में स्थापित करने का भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विरोध किया था। इसी तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल को यथोचित सम्मान दिए जाने की जरूरत बताई। ध्यान देने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा में बोलकर वैश्विक पटल पर उसकी पहचान बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस और द्रमुक को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए उन्होंने दोनों पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से दूर होने पर देश संचार के 5जी स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन द्रमुक के लिए 5जी की परिभाषा है, तमिलनाडु में एक ही परिवार की पांचवीं पीढ़ी का नियंत्रण। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री उस समय काफी भावुक हो गए जब वह 10 वर्ष पहले मारे गए भाजपा पदाधिकारी वी. रमेश का स्मरण कर रहे थे।

तमिलनाडु के सेलम में मंगलवार को जनसभा में शक्ति स्वरूप में पहुंचीं महिलाओं का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

पीएम ने केरल के पलक्कड़ में किया रोडशो

पथानमथिट्टा में 15 मार्च को रोडशो करने के बाद मोदी ने मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में भी एक रोडशो किया। लगभग एक किलोमीटर के इस रोडशो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री के वाहन पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन, पलक्कड़ से राजग प्रत्याशी सी. कृष्णकुमार और पोन्नानी सीट से प्रत्याशी निवेदिता सुब्रमण्यन मौजूद थे।

सीएए पर फिलहाल रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने का नहीं दिया आदेश

- याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में मांगा जवाब
- शीर्ष कोर्ट में दायर करीब 250 से ज्यादा याचिकाओं में सीएए को दी गई है चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से जोरदार मांग के बावजूद मंगलवार को सीएए लागू करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में कोर्ट नौ अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा।

सीएए के तहत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने का प्रविधान है। यह कानून 2019 में पारित हुआ था लेकिन उसके नियम तय कर उसे लागू करने की अधिसूचना बीते 11 मार्च को जारी हुई थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा एआइएमआइएम व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इन करीब 20 अंतरिम अर्जियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सीएए को चुनौती दी गई है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, इंद्रा जयसिंह, निजाम पाशा ने सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। आइयूएमएल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई तो मामला महत्वहीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून बनने के चार साल तीन महीने बाद इसे लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है जब इतने दिन से कानून लागू नहीं था तो फिर अब ऐसी क्या जल्दी है?

इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि वह नोटिस जारी कर रहा है और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप कब तक याचिकाओं का जवाब दे देंगे। मेहता ने चार सप्ताह का समय मांगा जिसका विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ज्यादा समय है। मेहता ने कहा कि इसमें कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं, सभी का जवाब देना होगा। इसके अलावा कई रोक अर्जियां भी हैं, इसलिए समय लगेगा। पीठ ने उनसे कहा कि आप पहले अंतरिम रोक पर ही तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करिए। कोर्ट ने केंद्र से आठ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। साथ ही पक्षकारों के वकीलों से अपनी दलीलों का पांच पेज का संक्षिप्त नोट दो अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में वकील कनु अग्रवाल और अंकित यादव को नोडल वकील नियुक्त किया है।

एआइएमआइएम के वकील पाशा ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा गया है। पहले सीएए लागू होगा और फिर एनआरसी लागू होगी, इससे मुसलमान प्रभावित होंगे। सालिसिटर जनरल ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीएए का मुद्दा है न कि एनआरसी का। इसलिए वे इस तरह की दलीलें यहां न दें। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने असम और उत्तर पूर्व के राज्यों का मुद्दा उठाया। आदिवासी संगठनों की ओर से पेश हो रहे हंसारिया ने कहा कि कानून में आदिवासी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। इसमें एक तरह से पूरा उत्तर पूर्व अलग है, इसमें कई मुद्दे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह असम के खंड को अलग से सुनेगा।

मामले में नोटिस जारी होने के बाद इंद्रा जयसिंह ने कहा कि केंद्र से बयान लिया जाए कि वह इस बीच सीएए में किसी को नागरिकता नहीं देगा। लेकिन मेहता ने ऐसा बयान देने से इन्कार कर दिया। तब जयसिंह ने कहा कि कोर्ट आदेश दे कि अगर इस बीच किसी को नागरिकता दी गई तो वह कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। फिर सिब्बल ने कहा कि अगर किसी को इस बीच नागरिकता दी जाती है तो उन्हें कोर्ट आने की छूट दी जाए। पीठ ने कहा यह ठीक है।

किसी पीड़ित को नागरिकता मिलती है तो इससे याचिकाकर्ता कैसे प्रभावित होंगे

सुनवाई के दौरान सीएए का लाभ पाकर नागरिकता लेने की बाट जोह रहे व्यक्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि उनका मुवक्किल 2014 में बलूचिस्तान से आया है, उसे वहां हिंदू होने के कारण प्रताड़ित किया गया अगर उसे सीएए में नागरिकता मिलती है तो इससे याचिकाकर्ता कैसे प्रभावित होंगे। इंद्रा जयसिंह ने कहा कि नागरिकता मिलने पर उसे मतदान का अधिकार मिल जाएगा।

20 अंतरिम अर्जियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सीएए को दी गई है चुनौती

सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सालिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि क्या सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए कमेटी आदि गठित हो चुकी है, क्या स्थिति है? इस पर मेहता ने कहा कि तीन स्तरीय व्यवस्था है। कमेटी बनेगी आवेदन होगा। दस्तावेज देखे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है, वह ये नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी को नागरिकता देने से याचिकाकर्ता किसी तरह प्रभावित नहीं होते। केंद्र ने पीठ को बताया कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है।

30 लाख युवाओं की भर्ती, ओपीएस बहाली, पांच न्याय गारंटी बनेंगी कांग्रेस का हथियार

- कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र मसौदे को मिली मंजूरी
- केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने, जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा वहाल कराने का वादा
- चुनावी मुद्दों को भावनात्मक रूप देने की भाजपा की रणनीति से पार्टी सतर्क
- भाजपा के गारंटी जुमला का इंडिया शाइनिंग जैसा होगा हश्र : मल्लिकार्जुन खरगे

संजय मिश्र, नई दिल्ली

केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्ती करने, राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और ओबीसी-एससी-एसटी को भागीदारी देने संबंधी 'पांच न्याय' के तहत 25 चुनावी गारंटियों के सहारे कांग्रेस 2024 के चुनाव में भाजपा के भावनात्मक चुनावी दांव को थामने के लिए पूरा जोर लगाएगी। विकास के इस वैकल्पिक एजेंडे के साथ अपनी गारंटियों को कांग्रेस घर-घर तक पहुंचा कर चुनावी विमर्श को जन मुद्दों के इर्द-गिर्द फोकस करने की कोशिश करेगी। राजनीतिक न्याय के वादे के तहत पार्टी सीबीआइ, ईडी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का वादा करेगी। वहीं चुनाव आयोग, कैग और सीवीसी जैसे संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर विधानसभा चुनाव कराने और लद्दाख को विशेष दर्जा देने का भी कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा करेगी।

कांग्रेस कार्यसमिति की मंगलवार को हुई बैठक में 2024 के आम चुनाव के लिए पार्टी के 43 पेज के घोषणापत्र मसौदे को मंजूरी दे दी गई हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसमें संशोधन का विकल्प खुला होने की बात कहते हुए पार्टी नेताओं से कुछ और सुझाव देने का आग्रह किया। पार्टी घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने करीब ढाई घंटे तक पार्टी के चुनावी वादें-गारंटियों के मसौदे को बैठक में रखते हुए इसके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को समझाया। घोषणापत्र को पांच 'न्याय स्तंभों' के आधार पर लोगों को न्याय सुनिश्चित करने पर फोकस रखते हुए कहा गया है कि देश बदलाव चाहता है और वर्तमान भाजपा सरकार की 'गारंटियों' का वही हश्र होगा जो 2004 में 'इंडिया शाइनिंग' का हुआ था।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद दावा किया कि पार्टी की पांच गारंटियां इस चुनाव में गेम-चेंजर साबित होंगी। कांग्रेस 'भागीदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' के इन पांच मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही जिसमें 25 गारंटियां शामिल हैं। वेणुगोपाल और कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम केंद्र सरकार में पहले से खाली 30 लाख स्वीकृत पदों पर भर्ती करेंगे इसे भर्ती न्याय कहा जाएगा।

चुनावी गारंटियों-वादों के इस रोडमैप से साफ है कि कांग्रेस इस चुनाव को भावनाओं की सियासी पिच पर ले जाने का भाजपा को अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अपने संबोधन में इसका संदेश देते हुए पार्टी नेताओं से साफ कहा कि चुनाव अभियान में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर ही केंद्रित रखना है।

नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी। प्रेट्र

राहुल ने भी घोषणापत्र के संबंध में रखी बात

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने केवल घोषणापत्र के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखीं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बवंडर बनाने की भाजपा की रणनीति को लेकर न्याय पत्र में विशेष सर्तकता का ध्यान रखने की जरूरत बताई। चीन व पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विशेष पैकेज का सुझाव भी आया।

पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजग में हिस्सेदारी नहीं मिलने से पारस नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे अपने त्यागपत्र में पारस ने राजग से संबंध तोड़ने के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है। दो वाक्यों के इस्तीफे में उन्होंने अपने ऊपर किए गए विश्वास के प्रति संतुलित शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया है, जो बताता है कि पारस ने विकल्प अभी बचाकर रखा है। हालांकि वह राजद के संपर्क में हैं और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं। (पेज-4)

बाबा रामदेव व बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश

पतंजलि विज्ञापन मामला

- शीर्ष कोर्ट ने कारण वताओ नोटिसों का जवाव दाखिल नहीं करने पर जताई कड़ी आपत्ति
- पूछा था, अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर क्यों न शुरू की जाए अवमानना कार्यवाही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि उत्पादों की प्रभावशीलता के विज्ञापन मामले से जुड़ी अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि कोर्ट को दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब तलब किया था। मंगलवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो कोर्ट को बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अगली तारीख पर निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी अवमानना नोटिस जारी किया और उन्हें भी अगली तारीख पर निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया।

पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रामदेव को नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने जवाब दाखिल नहीं कर पाने पर सफाई भी दी, लेकिन पीठ नहीं मानी। पीठ ने कहा, हमने इसे बेहद गंभीरता से लिया था। इसे दाखिल नहीं करने का मतलब है कि आदेश जारी होंगे और उसके परिणाम होंगे।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई की क्योंकि उसने सोमवार शाम को जो हलफनामा दाखिल किया था, वह रिकार्ड पर नहीं था। साथ ही केंद्र को अपना पूर्व में दाखिल अतिरिक्त हलफनामा वापस लेने और आखिरी मौके के रूप में नया हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जिसमें उठाए गए कदमों का ब्योरा होगा।

बाबा रामदेव और बालकृष्ण। फाइल

कोर्ट ने कहा, आदेश में है नोटिस जारी करने का कारण पेज>>6

रिपोर्ट

स्विट्जरलैंड के संगठन आइएक्यू एयर द्वारा जारी नई रिपोर्ट 2023 में भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश, बांग्लादेश पहले व पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, बिहार का बेगूसराय सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र

दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

इसे सरकारों की अनदेखी कहें या प्रशासन की लापरवाही... दिल्ली को एक बार फिर से विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2023 में यहां पीएम 2.5 का औसत वार्षिक स्तर 102.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकार्ड किया गया है, जो उसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाता है। 2022 में यह आंकड़ा 92.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। मतलब इस दौरान दिल्ली के प्रदूषण में 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वहीं, भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है, पड़ोसी बांग्लादेश पहले, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। स्विट्जरलैंड के संगठन आइएक्यू एयर द्वारा जारी नई रिपोर्ट में बेगूसराय को वैश्विक स्तर पर 2023 के सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहा है, जिसमें पीएम 2.5 की सांद्रता डब्ल्यूएचओ के वार्षिक स्तर से 10 गुना से भी अधिक है।

100 प्रदूषित शहरों में 83 भारत के: रीजन एंड सिटर पीएम 2.5 रैंकिंग के अनुसार दिल्ली 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में रही है। 2022 में यह तीसरे नंबर पर थी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में यह भी अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोग पीएम 2.5 की उच्च सांद्रता की चपेट में हैं, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित वार्षिक स्तर पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में 83 भारत के रहे हैं। आइक्यू एयर रैंकिंग में बेगूसराय के बाद गुवाहाटी, दिल्ली और मुल्लानपुर (पाकिस्तान) आते हैं।

दिल्ली में प्रदूषण का एक नजारा। फाइल

इन कारणों से बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर

वाहनों का धुआं, कोयला और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं, पराली का धुआं, सर्दी से बचने और ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन जलाना, धूल।

आंकड़े बताते हैं कि भारत व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिन पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे इसकी विशाल आबादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही हैं। वाहन उत्सर्जन वायु प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो दिल्ली में पीएम 2.5 उत्सर्जन का 40 प्रतिशत है। डब्ल्यूएचओ को अपने वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित किए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से बार-बार मांग के बावजूद भारत ने अभी तक दिशानिर्देशों को अपडेट नहीं किया है। - अविनाश चंचल, अभियान प्रबंधक, ग्रीनपीस इंडिया

विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित पांच देश

देश	पीएम 2.5
बांग्लादेश	79.9
पाकिस्तान	73.7
भारत	54.4
तजाकिस्तान	49.0
बुर्किना फासो	46.6

सर्वाधिक प्रदूषित पांच राजधानी

राजधानी	पीएम 2.5
दिल्ली (भारत)	102.1
ढाका (बांग्लादेश)	80.2
उवागाडोगू (बुर्किना फासो)	46.6
दुशानबे (तजाकिस्तान)	46.0
बगदाद (इराक)	45.8

(आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

03 लाख पेड़ लगाने के इस वर्ष राजधानी में लगाने के प्रस्ताव का विवरण दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 20 मार्च, 2024

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
20 मार्च	33.0	13.0
21 मार्च	32.0	13.0
नोएडा		
20 मार्च	32.0	15.0
21 मार्च	31.0	15.0
गुरुग्राम		
20 मार्च	29.0	14.0
21 मार्च	29.0	14.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

आप के संजय सिंह ने ली रास सदस्य के रूप में शपथ

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के सभापति कार्यालय में उन्हें शपथ दिलाई। संजय दिल्ली से दूसरे कार्यकाल के लिए उच्च सदन के लिए फिर निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट में शपथ ग्रहण की तस्वीरें साझा कीं। तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को एक अदालत से अनुमति मिलने के बाद सुरक्षा घेरे में शपथ ग्रहण के लिए संसद भवन लाया गया था। (प्रेट्र)

सिसोदिया व संजय सिंह की हिरासत छह अप्रैल तक बढ़ाई

नई दिल्ली : आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की होली इस बार जेल में ही मनेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत छह अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया था। (जासं)

अवैध रिफंड आदेश जारी करने पर अधिकारी बर्खास्त

नई दिल्ली : मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंगलवार को एक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी मनोज कौशिक को अवैध रिफंड आदेश जारी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अधिकारी के आदेश से कई करोड़ का नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपित अधिकारी ने लाभार्थियों को अवैध रिफंड देने के आदेश जारी किए, जिससे सरकार को 14 करोड़ का नुकसान हुआ। (राब्यू)

केजरीवाल ने लोगों के विश्वास, सच्चाई और विकास का कत्ल किया है : पात्रा

कहा, अदालत ने ईडी को समन भेजने से नहीं रोका है

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का पालन नहीं कर संविधान का निरादर किया है। जांच एजेंसियों का गठन किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि संविधान के अनुसार हुआ है। जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर वह काम करती है।

केजरीवाल ने लोगों के विश्वास, सच्चाई और विकास का कत्ल किया है, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। इसी के आधार पर उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। इसका सम्मान करने की जगह वह छह माह में नौ समन पर 18 बहाने बना चुके हैं। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमवार से यह झूठ फैला रहे हैं कि अदालत ने समन खारिज कर दिया है। जमानत मिलने के बाद भी ईडी द्वारा समन भेजे जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताकर कोर्ट से इसे वापस कराने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आरोपित के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं। ईडी को अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि ईडी को समन भेजने से अदालत ने नहीं रोका है। समन का पालन नहीं करने पर आइपीसी की धारा 174 के अंतर्गत गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल को अदालत से जमानत मिली है। सोनिया, राहुल गांधी व राबर्ट वाड्रा की तरह केजरीवाल भी जमानत पर बाहर हैं। जमानत को राहत की तरह प्रस्तुत नहीं करें। जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप समाप्त हो गया। कुछ तो उन्होंने गड़बड़ किया है, जिससे जमानत लेने की नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार पर एफआइआर हुई है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं।

- भ्रष्टाचार किया है इसलिए मुख्यमंत्री को लेनी पड़ी है जमानत

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा। फाइल

सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है आप को 100 करोड़ रिश्वत मिलने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- आम आदमी पार्टी के चार नेताओं ने प्रेसवार्ता कर कहा, ईडी भाजपा का राजनीतिक हथियार

आम आदमी पार्टी ने ईडी पर भाजपा का 'राजनीतिक हथियार' बनने का आरोप लगाया है। आप ने ईडी के इस दावे को गलत बताया है कि बीआरएस नेता के. कविता आप नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थीं। आप ने कहा है कि सोमवार को ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी, जबकि इस दावे को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था।

ईडी के बाद मंगलवार को भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जाने पर आप ने भाजपा पर भी हमला बोला। आप के चार नेताओं दिलीप पांडेय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय ने प्रेसवार्ता कर कहा कि सोमवार से आबकारी मामले में ईडी और सीबीआइ द्वारा एक नया शिगूफा छोड़ा जा रहा है कि केजरीवाल घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो पहले 1000 करोड़ की बात कही जा रही थी अब 100 करोड़ की बात की जा रही है, इससे साजिश साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वह बताना चाहते हैं कि कोर्ट कह चुकी है कि इसके कोई सुबूत नही हैं। उसके बाद भी भाजपा के इशारे पर ईडी इसे साजिशन उछाल रही है कि जिससे केजरीवाल की छवि खराब की जा सके।

प्रेस कांफ्रेंस करतीं शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी। प्रेट्र

ईडी के नौवें समन को दिल्ली के सीएम ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- केजरीवाल की याचिका पर आज दो सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई

ईडी के किसी भी समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के नौवें समन को गैरकानूनी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ सुनवाई करेगी। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को नौवां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। वहीं, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भी पहला समन जारी कर 18 मार्च को पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ईडी द्वारा जारी किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं।

बार-बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमए) के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं। ईडी की शिकायत पर जारी दो समन पर 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल एडिशनल एसीएमए दिव्या मल्होत्रा के समक्ष पेश हुए थे और अदालत ने उन्हें 15-15 हजार के मुचलके व एक-एक लाख के जमानती पर जमानत दी थी। ईडी ने केजरीवाल पर समन के गैर-अनुपालन का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने कहा था कि ईडी के सामने पेश नहीं होने का अपराध जमानती होने के कारण आरोपित को जमानत दी जाती है। इस मामले में एक अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायत दाखिल कर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।

यह है मामला...

सीबीआइ और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआइ जांच की सिफारिश की। इसपर सीबीआइ ने प्राथमिकी की थी।

एक दिन में होंगे दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन के होंगे चुनाव : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- प्रत्याशियों के चुनावी पार्टियों के आयोजन, पोस्टर छापने और होर्डिंग लगाने पर लगा दी रोक
- विभिन्न याचिकाओं पर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने सुनाया निर्णय, दो साल के लिए होगा कार्यकाल

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के साथ ही दिल्ली की विभिन्न निचली अदालत व न्यायाधिकरण के चुनाव में मतदान से लेकर खर्चे में होने वाली अनियमितता पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने निर्णय सुनाया कि दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन का चुनाव एक ही दिन होगा और सभी का कार्यकाल दो साल के लिए होगा।

पूर्ण पीठ ने कहा कि डीएचसीबीए समेत सभी बार के चुनाव 19 अक्टूबर 2024 को होंगे और एक उम्मीदवार एक से अधिक बार एसोसिएशन के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, भले ही वह कई अदालतों में प्रैक्टिस करता हो। दिल्ली में छह जिला अदालतें हैं। अदालत ने उक्त निर्णय बार एसोसिएशन के चुनावों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत को निर्णय करना था कि क्या विभिन्न बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों के चुनाव एक साथ होने चाहिए और क्या ऐसी समितियों का कार्यकाल एक समान अवधि के लिए होना चाहिए। अदालत ने चुनावों में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों के चुनावी पार्टियों के आयोजन, पोस्टर छापने और होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी।

यूक्रेनी बच्चे की कस्टडी की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पांच वर्षीय यूक्रेनी बच्चे की कस्टडी याचिका खारिज करने के पारिवारिक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली एक पिता की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि बच्चे के हित में है कि वह मां और अपने भाई-बहनों के साथ रहे। अदालत ने कहा कि वह उस निर्णय में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी महिला बच्चे के साथ भारत छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

दोनों की वर्ष 2000 में शादी हुई थी और मई 2021 में यूक्रेन में अदालती डिक्री के माध्यम से शादी को खत्म कर दिया गया था। बाद में पिता को बच्चे से मुलाकात का अधिकार दिया गया। पांच साल के बेटे के अलावा 2002 में एक बेटी का भी जन्म हुआ। महिला ने दावा किया था कि उसका पूर्व पति वर्ष 2022 में नाबालिग बेटे को घुमाने ले गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में पता चला कि वह बच्चे के साथ सीमा पार कर रोमानिया से भारत भाग गया था।

डा. नरेश त्रेहन का डीपफेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- डीपफेक वीडियो में डा.त्रेहन 10 किलो तक मोटापा कम करने का दावा कर रहे, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मेदांता अस्पताल के सीएमडी डा. नरेश त्रेहन का डीपफेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में डा. त्रेहन 10 किलो तक मोटापा कम करने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल की मार्केटिंग टीम की शिकायत पर साइबर ईस्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मार्केटिंग टीम के हरीश अश्विनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि डा. त्रेहन का फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उसमें वह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसी दवा बनाई गई है, जिससे कोई भी वजन कम कर सकता है। इस दवा से दो हफ्ते में 10 किलो तक वजन कम किया जा सकता है। साथ ही 20 हजार भारतीयों पर प्रयोग का दावा भी किया जा रहा है। वीडियो में दवा के बारे में जानकारी के लिए लिंक भी दिया गया है। यह डीपफेक वीडियो करीब दो हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। यह वीडियो फेसबुक पर ड्रेटा रिवर बैंड नाम के पेज पर प्रसारित किया गया है। साइबर पुलिस केस दर्ज कर आरोपित का आइपी एड्रेस पता कर रही है।

डा. नरेश त्रेहन। फाइल

कैसे बनाते हैं डीपफेक वीडियो : डीपफेक वीडियो दो नेटवर्क की मदद से बनाया जाता है। इनमें एक इनकोडर और एक डीकोडर होता है। इनकोडर नेटवर्क असली वीडियो के लिए होता है और फिर असली वीडियो के हिसाब से एक डाटा डीकोडर नेटवर्क के लिए भेजा जाता है। इसके बाद एक वीडियो बन जाता है जो असली वीडियो की ही तरह लगता है।

कविता ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने मंगलवार को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। हालांकि एमएलसी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कविता ने याचिका में अपनी रिमांड और पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 (1) को भी चुनौती दी है। उन्हें गत 15 मार्च को दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बीआरएस नेता के अधिवक्ता ने कहा कि वे ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी ने दावा किया था कि एमएलसी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में लाभ पाने के लिए केजरीवाल व सिसौदिया जैसे आप नेताओं के साथ साजिश रची और वह लाभ के बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ का भुगतान करने में शामिल थीं।

जेएलएन स्टेडियम में सभी तरह के आयोजनों पर रोक

जागरण संवाददाता,नई दिल्ली

- आग से बचाव के इंतजाम दुरुस्त नहीं होने पर परिसर का उपयोग बंद करने को लिखा स्टेडियम प्रशासक को पत्र

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम के प्रशासक को अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी के कारण खेल आयोजनों व समारोहों के लिए परिसर का उपयोग बंद करने के लिए पत्र लिखा । आग से सुरक्षा के इंतजाम न होने से चाणक्यपुरी स्थित सम्राट होटल का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र भी रद किया गया है। वहीं, अग्निशमन विभाग का कहना है कि वह दिल्ली के अन्य स्टेडियमों में भी अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच करेगा। जिस स्टेडियम में अग्नि सुरक्षा उपाय पूरे नहीं होंगे और विभाग की एनओसी नहीं होगी, विभाग उस स्टेडियम को नोटिस जारी करेगा।

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने 15 मार्च को पत्र लिखकर जेएलएन स्टेडियम प्रशासक से खेलों, कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरे स्टेडियम परिसर का उपयोग बंद करने के लिए कहा। पत्र में 13 मार्च की सुबह करीब 7.32 बजे स्टेडियम में हुई एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें आग के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस आग में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। सूत्रों के अनुसार, स्टेडियम में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे। जांच से यह भी पता चला कि अभी तक स्टेडियम का अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रिन्यू नहीं हुआ है। विभाग ने पत्र में कहा है कि जब तक अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपकरणों की मरम्मत, सुधार और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र रिन्यू नहीं हो जाता, तब तक परिसर का उपयोग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आग की घटना स्टेडियम पी-वन टनल के पास मेन अरेना के निचले बेसमेंट में हुई थी। 12 दमकल गाड़ियों को भेजा गया था और आग पर काबू पाने में चार घंटे लगे थे।

बगैर सहमति के काम संभालना पड़ा अधीक्षण अभियंता को भारी

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली में ज्वाइन करने के लिए मुख्य अभियंता से सहमति नहीं लेने पर अधीक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिकल) को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में वापस भेज दिया गया है। ये मुख्य अभियंता (स्वास्थ्य) के अधीन कार्यरत थे। मुख्य अभियंता ने इन्हें आगामी एक अप्रैल से विभाग में प्रभारी अधिकारी के तहत कार्यभार संभालने के आदेश दिए थे, मगर उन्होंने अप्रैल की जगह मार्च में ही स्वयं जिम्मेदारी संभाल ली। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता माना है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन्हें तुरंत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस भेज दिया है। विभाग के प्रधान सचिव ए. अंबरासु के आदेश पर संतोष कुमार धनगर केंद्र सरकार में वापस भेजे गए हैं।

पूरा मामला इसलिए विवाद में आया क्योंकि कुछ माह पहले लोक निर्माण विभाग में जेल और अदालत से संबंधित नई इमारतें बनाने और उनके रखरखाव के लिए अलग से विंग बना दिया गया। विभाग के स्वास्थ्य विंग में अस्पतालों के निर्माण और रखरखाव के लिए दो अधीक्षण अभिंता कार्यरत थे, जिसमें संतोष कुमार धनगर करीब सात माह पहले ही विभाग में आए थे। इन दो में से एक मनोज कुमार सोनकर को जेल और अदालत विंग में तबादला के आदेश जारी किए गए और धनगर को पूरे स्वास्थ्य के मामले देखने के आदेश विभाग के उप सचिव ने विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर जारी किए। यह मामला फरवरी का है। इसके बाद विभाग के मुख्य अभियंता ने अपने उच्च अधिकारियों को विश्वास में रखकर एक इंटरनल नोट चलाया, जिसमें कहा गया कि मार्च का माह वित्तीय वर्ष के लिहाज से क्लोजिंग का मामला है। धनगर 31 मार्च तक अपने पहले से चले आ रहे कार्य देख लें और सोनकर अपने कार्यों की क्लोजिंग करा दें। इसके बाद वह अप्रैल से स्वास्थ्य विंग पूरी तरह से छोड़ दें। मुख्य अभियंता ने कहा कि क्लोजिंग का समय है। नए व्यक्ति को समझने में समय लगेगा, इससे काम में अड़चन आएगी।

बार-बार याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता पर एक लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता पर बार-बार याचिका दायर करने को लेकर एक लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि कानून और प्रक्रियाओं से अवगत अधिवक्ता ने बार-बार चेतावनी मिलने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया और 2009 के एक सिविल मुकदमे में दायर जाली दस्तावेज के मुद्दे को तीसरी बार पुनर्जीवित करने की कोशिश जारी रखी।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद एक प्रैक्टिस कर रहा अधिवक्ता है, ऐसे में अदालत यह नहीं मान सकती कि वह कानून से अनभिज्ञ है। वह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। अदालत ने कहा कि जब कानून के संरक्षक ही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं तो अदालत को भी सख्त रुख अपनाना पड़ता है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने में लगभग 40 मिनट समय लगा और इस पर आदेश तय करने में आधे घंटे और लगे।

जेएनयूएसयू छात्र संघ चुनाव में भी छाया सीएए का मुद्दा

जेएनयूएसयू चुनाव

उदय जगताप, नई दिल्ली

- आम सभा की बैठकों में जोर-शोर से उठाया जा रहा सीएए का मामला
- छात्रों के अपने मुद्दे हो गए हैं पीछे, चुनाव में जुटे हैं सभी छात्र संगठन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को छात्रों के बीच ले जाया जा रहा है। स्कूलों में हो रही आम सभा की बैठकों में काउंसलर प्रत्याशी खुद को पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, हालांकि छात्र संगठन जेएनयू से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन खुली बैठकों में ऐसा नहीं दिख रहा है।

हाल ही में समान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया गया है। अब यह मुद्दा जेएनयूएसयू चुनाव में भी छात्र नेताओं की जुबान पर है। मंगलवार को सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में हुई आम सभा की बैठक में सीएए का मुद्दा खूब उठाया गया। लेफ्ट पैनल की तरफ से काउंसलर प्रत्याशी ने आम सभा में भाषण की शुरुआत इसी से की। इसको समुदाय विशेष के खिलाफ बताया। इसके अलावा वाम छात्र संगठनों के प्रत्याशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ठीक से लागू न करने की बात कर रहे हैं। आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने लेफ्ट पैनल की तरफ से अध्यक्ष प्रत्याशी उतारा है।

आइसा के एक पदाधिकारी ने कहा, यह जेएनयू की प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई है। यहां के लोकतांत्रिक माहौल को खत्म किया जा रहा है। रोजगार पर बात होना बंद हो गई है। लेफ्ट पैनल प्रत्याशी धनंजय ने कहा, हेफा से लोन लेने की संस्कृति जेएनयू जैसे संस्थान को खत्म कर देगी। जहां वंचित वर्ग के छात्र शिक्षा लेने आते हैं, क्योंकि इसका सीध संबंध छात्रों की फीस से है।

बदलाव

देश के विभिन्न राज्यों में खेती और किसानों को एआइ व तकनीक से आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे युवा, कृषि व दुग्ध उत्पादन से लेकर विपणन तक में आ रहा है बदलाव, स्टार्टअप बदल रहा परंपरागत कृषि का तरीका

कृषि क्षेत्र में नई हरित क्रांति का बीज रोपित कर रहा देश का स्टार्टअप जगत

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

कृषि और किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच भी यह तेज है। इस बीच देश का स्टार्टअप जगत बिना शोर-शराबे के चुपचाप देश के गांवों और खेतों में हरित क्रांति के नए बीज रोपित कर रहा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों के किसानों के बीच तकनीक और विचारों में नवीनता लाकर देश का एक युवा वर्ग स्टार्टअप के माध्यम से तकनीक व आविष्कार के जरिये कृषि के परंपरागत तरीकों में बदलाव ला रहा है। आधुनिक व वैज्ञानिक आधारित खेती को बढ़ावा देने के साथ दुग्ध उत्पादन, विपणन और प्रशिक्षण की सुविधा हजारों किसानों के जीवन में खुशहाली लाया है, बल्कि शहरों की ओर युवाओं का पलायन भी रोक रहा है। भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ सफलताओं की ऐसी कहानियों से चमत्कृत है, जो एक एप के माध्यम से किसानों के जीवन को सशक्त बना रहा है। साथ ही आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआइ), रोबोट, सेंसर, डाटा विश्लेषण और ड्रोन तक के नवीनतम प्रयोग से आधुनिक कृषि की नीव रख रहे हैं।

ड्रोन दीदी लिनंता शेरके। जागरण

आकर्षण के केंद्र में ड्रोन दीदी

प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी का जिक्र करते हैं। जब स्टार्टअप महाकुंभ में ड्रोन दीदी लिंनता शेरके से मिलने का मौका मिला, तो लोग उनसे बात कर अनुभव साझा कर रहे। कृषि में बीएससी लिंनता बताती हैं कि केंद्र जब पिछले वर्ष ड्रोन दीदी योजना लाई थी, वह कई माह पहले ड्रोन उड़ाकर बदलाव लाने लगी थीं। इसलिए उन्हें महाराष्ट्र की प्रथम व देश की दूसरी ड्रोन दीदी का उपनाम मिला है।

इंडिया एआइ मिशन में स्टार्टअप्स के लिए दो हजार करोड़ मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्टार्टअप हब के सीईओ जितेंद्र विजय ने मंगलवार को कहा कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) मिशन के तहत एआइ स्टार्टअप्स के लिए दो हजार करोड़ रुपये का आवंटन हो चुका है। यह मिशन एक अप्रैल से शुरू होगा। स्टार्टअप महाकुंभ से इतर बातचीत में विजय ने बताया कि कैबिनेट ने इस मिशन पर पांच वर्षों में 10,372 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है।

एक लाख से अधिक किसानों में बदलाव लाया है 'सलाम किसान' : महाराष्ट्र के एक लाख से अधिक किसानों के जीवन में 'सलाम किसान' स्टार्टअप ने बदलाव लाया है। उसने किसानों को एक धागे में पिरोने के साथ संगठित किया है। प्रशिक्षण देकर गांवों के युवक-युवतियों को आधुनिक कृषि का दूत बनाया। केंद्र द्वारा ध्यान देने से पूर्व ही कृषि में ड्रोन का प्रयोग शुरू कर दिया था। उसके द्वारा डाटा आधारित और एआइ विश्लेषण कर परंपरागत खेती में बदलाव लाकर मांग आधारित कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए उसके पास गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और कपास के साथ ही 70 से अधिक विविध फसलों की श्रृंखला है। जो वहां की जलवायु व मिट्टी आधारित होने से लाभदायक है। एआइ आधार पर न्यूनतम कीटनाशक तथा खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि लागत को घटाते हुए अधिकतम उत्पादन लिया जा रहा है। तकनीक व उपकरण उपलब्ध कराने के साथ भंडारण व परिवहन तथा कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 22 जिलों के सात हजार से अधिक गांवों के किसानों में सलाम किसान क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

****

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

31,83,325 मतदाताओं के साथ संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तेलंगाना का मलकागिरी है। क्षेत्रफल के लिहाज से लद्दाख है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र।

भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस, भूपेश के साथ फंसे कई नेता

संदीप तिवारी • रायपुर

बड़ा मुद्दा

लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस बैकफुट पर है। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। दरअसल, महादेव आनलाइन सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआइआर होने बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव के लिए चल रही सभाओं व जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने कुछ इसी तरह से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था।

महादेव एप मामला समेत कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले में कई कांग्रेसियों के नाम आने के बाद पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में भूपेश की मुश्किलें बढ़ने के साथ-साथ पार्टी पर संकट के बादल छा गए हैं। महादेव एप मामले में जहां भूपेश कटघरे में हैं, तो वहीं कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। देवेंद्र को कांग्रेस बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य विधायकों पर भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में चल रही है।

दो हजार करोड़ से अधिक का शराब घोटाला: ईडी की जांच के बाद प्रदेश में 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में 35 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। ईडी की जांच में कांग्रेस के बड़े नेताओं में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज, सेवानिवृत्त आइएएस अनिल टुटेजा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, कारोबारी अनबर ढेबर समेत अन्य आइएएस-आइपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

540 करोड़ के कोयला घोटाले में कई अधिकारी भी शामिल

ईडी ने 540 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में कुल 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, आइएएस रानू साहू और आइएएस समीर बिश्नोई के नाम शामिल हैं। तीनों अधिकारी जेल में हैं। ईडी के मुताबिक कोयले के परिवहन को लेकर अधिकारियों, कारोबारियों और राजनेताओं का गठजोड़ था, जो प्रति टन 25 रुपये वसूलता था। ये घोटाला भूपेश बघेल सरकार के समय उजागर हुआ।

भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

- **लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरने से कांग्रेस असहज**
- **सट्टा एप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआइआर होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा**
- **भाजपा हमलावर है, उसने विस चुनाव में भी इसी तरह से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था**

महादेव एप मामले में ईडी जांच कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर अभी एफआइआर हुई। असीम दास की गिरफ्तारी के समय उसका बयान और शुभम सोनी के बयान में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जहां कांग्रेस होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा।

अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए साजिश कर रही है। भाजपा ने नरेन्द्र मोदी सरकार की नाकामियों व भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए यह एफआइआर कराई है। भाजपा ने इलेक्टोरल बांड घोटाले में छह हजार करोड़ वसूले हैं। पहले व्यापारियों के यहां छापा डालते हैं, फिर भाजपा उनसे चंदे की राशि लेती है।

सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, प्रदेश संचार विभाग, छत्तीसगढ़ कांग्रेस

पिछड़ों को लुभाने की जुगत में हर दल

राहुल को लालू-मुलायम के बाद समझ में आई ओबीसी वोट की अहमियत, भाजपा भी खींच रही पाले में

अरविंद शर्मा • नई दिल्ली

देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक बड़ा मतदाता वर्ग है। राजद और सपा जैसी समाजवादी पार्टियों के साथ आगे बढ़ रही कांग्रेस लगभग एक वर्ष से सामाजिक न्याय के मुद्दे को उछाल कर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के संयुक्त अभियान का अघोषित नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी देशभर में घूम-घूमकर आबादी के अनुरूप सत्ता में सबकी हिस्सेदारी का नारा लगा रहे हैं तो इसकी वजह है कि ओबीसी के बड़े वोटबैंक पर विपक्ष की नजर है। भाजपा भी इससे अनजान नहीं है। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले हरियाणा में मनोहर लाल के बदले ओबीसी समुदाय के नायब सिंह सैनी को सरकार की कमान देकर भाजपा ने संकेत कर दिया है कि उसके तरकश में तीरों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव पहले से ही बिहार व उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग को लीक बदलने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

ओबीसी वोटबैंक की जिस अहमियत को कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में राहुल गांधी ने हाल के दिनों में समझा है, उसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एवं बिहार में लालू प्रसाद ने लगभग चार दशक पहले ही भांप लिया था। दोनों ने उसी लाइन पर बढ़ते हुए सियासत के फार्मूले को पलट दिया। आज भी उनकी पार्टियां पुरानी लीक पर चलते हुए प्रासंगिक बनी हुई हैं। कांग्रेस ने देर से इस लीक पर कदम रखा। आजादी के वक्त ही यदि वह राजनीतिक करवट का अंदाजा लगा लेती तो आज शायद उसका ऐसा हाल नहीं होता। तब सिर्फ एससी-एसटी को आरक्षण दिया गया था। गर्दिश में जी रही अन्य जातियों की पहचान के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। आयोग ने 1955 में रिपोर्ट भी सौंप दी थी, लेकिन इसे तहखाने में डालकर छोड़ दिया गया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता तो सिफारिशों को लागू कर वोट में तब्दील कर सकता था। दूसरी पहल, 1977 में कांग्रेस के विरोध में बनी जनता सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाकर की। आयोग ने 1980 में रिपोर्ट सौंपी, किंतु कांग्रेस की इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की सरकारों ने उसे भी फाइलों में दबा दिया। तीसरी पहल, बनी वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की उन सिफारिशों को लागू कर की, जो दशकभर से किसी उद्धारक का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस फिर चूक गई। यहां तक कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने सदन में इसका विरोध किया।

ओबीसी का वोटिंग ट्रेंड विभिन्न राज्यों में भिन्न होता: इस बार 96.8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। केंद्र की ओबीसी सूची में कुल 2,479 जातियां हैं। राज्यों की सूची अलग होती है। संख्या भी अलग-अलग होती है। इसमें कहीं 50 प्रतिशत तो कहीं 10 प्रतिशत ओबीसी हैं। इन जातियों का वोटिंग ट्रेंड विभिन्न राज्यों में भिन्न होता है। केंद्र में नरेन्द्र मोदी को शीर्ष तक पहुंचाने में ओबीसी की बड़ी भूमिका है। राज्यों में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार की राजनीति भी ओबीसी की फैक्ट्री से ही निकली। आज भी कई राज्यों में राजनीतिक दलों का भविष्य ओबीसी वोटरों के मूड पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रहता है, जो बता सके कि किस वर्ग ने किस दल को वोट किया, किंतु लोकनीति सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि 2009 से कांग्रेस का ओबीसी वोट घट रहा एवं भाजपा का बढ़ रहा। 2009 में भाजपा को सिर्फ 22 प्रतिशत ओबीसी वोट मिला था, जो 2014 में बढ़कर 41 प्रतिशत और 2019 में 48 प्रतिशत हो गया।

भाजपा को ओबीसी वोट मिलने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा

2009	2014	2019
22%	41%	48%

96.8 करोड़ कुल मतदाता | **47.1 करोड़** महिला | **49.7 करोड़** पुरुष

पार्टियां तरह-तरह के प्रयास से लुभा रहीं

- **भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न व हरियाणा में ओबीसी के नायब सिंह सैनी को सीएम बना बताया कि उसके तरकश में हैं कई तीर**
- **मध्य प्रदेश में पार्टी पहले ही डा. मोहन यादव को सीएम बनाकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग को लुभाने के प्रयास में है**
- **आजादी के वक्त ही यदि कांग्रेस राजनीतिक करवट का अंदाजा लगा लेती तो आज शायद उसका ऐसा हाल नहीं होता**

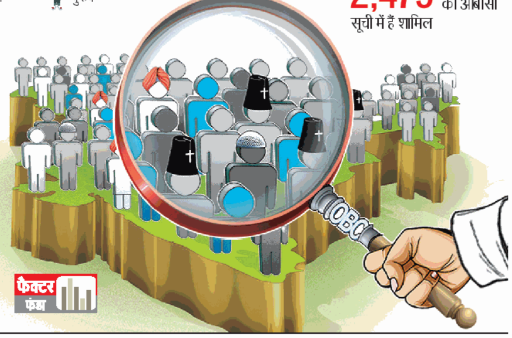

कांग्रेस ललकार रही है भाजपा को

भाजपा की जीत के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वोट की धारा बदल चुकी है। हिंदुत्व की पहचान रखने वाली भाजपा समाजवादी दलों के आधार में सेंधमारी कर चुकी है। कांग्रेस भी आज उसी अखाड़े में खड़ी होकर भाजपा को ललकार रही है, जिसमें कभी लालू-मुलायम ने उसे परास्त कर यूपी-बिहार से बाहर कर दिया था।

नरेन्द्र मोदी

राहुल गांधी

2,479 जातियां केंद्र की ओबीसी सूची में हैं शामिल

मोदी की विजय के लिए विदेश में हवन... »

भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विजय के लिए देश ही नहीं, विदेश में भी लोग पूजा-अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में सिलिकान वैली के भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों ने एक हिंदू मंदिर में विशेष हवन किया। ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी (ओएफबीजेपी)-यूएसए सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर' द्वारा आयोजित हवन-पूजन में अनेक लोग सम्मिलित हुए। ओएफबीजेपी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा की निर्णायक विजय की प्रार्थना करने के लिए भारतीय समुदाय एक साथ आया एवं 'अबकी बार, 400 पार' का नारा दोहराया • प्रेट्र

वाट्सएप और यूट्यूब के सहारे मतदाताओं को लुभाने में जुटे दल

मैसेजिंग प्लेटफार्म जैसे वाट्सएप और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लूएंसर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी माध्यम के तौर पर उभरे हैं। व्यापक पहुंच को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने और मतदाताओं से समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।

यूट्यूब चैनलों पर दिखे नेता

भाजपा नेता एस जयशंकर, स्मृति इरानी, पीयूष गोयल और राजीव चंद्रशेखर ने पाडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को इंटरव्यू दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कर्ली टेल्स की संस्थापक कामिया जानी के साथ बातचीत की है। कर्ली टेल्स एक ट्रैवेल और फूड वीडियो पाडकास्ट है।

9.63 करोड़ फालोवर हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक्स पर

2.51 करोड़ लोग फालो करते हैं राहुल गांधी को एक्स पर

₹325 करोड़ खर्च किए थे भाजपा ने मीडिया विज्ञापन पर 2019 के आम चुनाव के दौरान

₹356 करोड़ खर्च किए थे कांग्रेस ने मीडिया विज्ञापन पर 2019 आम चुनाव में

जिस राजनीतिक दल के पास, जितने अधिक वाट्सएप ग्रुप हैं, वह उतनी ही ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से मतदाताओं से जुड़ सकता है। इससे बड़े यूजर बेस तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने और विपक्ष से तुलना करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने में मदद मिलती है। **अमिताभ तिवारी**, चुनाव विश्लेषक, टिप्पणीकार

मतदाताओं को कैसे लुभा रही हैं पार्टियां

- भाजपा वाट्सएप पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र भेजकर मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रही है। वाट्सएप के भारत में करीब 50 करोड़ मासिक यूजर हैं। पत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई हैं और पत्र के जरिये मतदाताओं से फीडबैक मांगा गया है।
- कांग्रेस राहुल गांधी वाट्सएप ग्रुप संचालित कर रही है। राहुल गांधी ग्रुप में लोगों से बातचीत करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। वाट्सएप सूचनाओं के प्रसार की निगरानी जिला स्तर से की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूचनाएं बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचें।

झारखंड में कांग्रेस के रुख से झामुमो असहज, भाजपा ने भी चला बड़ा दांव

प्रदीप सिंह • रांची

झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने लोस में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनाई है, लेकिन अभी तक यह आधिकारिक तौर पर यह घोषित नहीं हुआ है। वहीं, इस बीच झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अपने परिवार की पार्टी छोड़ भाजपा में चली गई हैं। ऐसे में झामुमो को अब परिवार के मोर्चे पर भी चुनौती झेलनी पड़ेगी। चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा दुमका में अपना उम्मीदवार बदलकर सीता सोरेन को वहां से उतार सकती है। उधर, दुमका में झामुमो का गढ़ बचाने के लिए हेमंत सोरेन के भी वहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसा होता है तो सोरेन परिवार के सदस्य आमने-सामने होंगे।

गठबंधन की कहानी

उधर, महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रोज नए फार्मूले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस को सात सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, जबकि झामुमो का कहना है कि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

झामुमो की रणनीति थी कि सीटों के बंटवारे की घोषणा अंतिम समय में की जाए। मगर कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सात सीटें कांग्रेस, पांच झामुमो और एक-एक सीट राजद व भाकपा माले को दिए जाने पर सहमति बनने का दावा किया। कांग्रेस की इस घोषणा से झामुमो असहज है। झामुमो अबतक खुद को गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में बताकर ज्यादा सीटों का दावा करता रहा है। ऐसे में झामुमो ने भितरखाने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि इससे परिणाम के साथ-साथ उसकी सांगठनिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। झामुमो ने तय किया है कि सीटों के तालमेल को लेकर अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात होगी। झामुमो की कोशिश है कि कम से कम एक और सीट पाले में आए। दबाव लोहरदगा सीट को लेकर है। हालांकि कांग्रेस इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में चले जाने के बाद अब कांग्रेस ने सिंहभूम संसदीय सीट पर दावेदारी छोड़ दी है। इस सीट से अब झामुमो अपना प्रत्याशी देगा।

राजद के दावे अलग: एक सीट दिए जाने के फार्मूले से इतर राजद के दो प्रत्याशी चतरा और पलामू में चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। उनका दावा है कि राजद को झारखंड में दो सीटें दिए जाने पर सहमति बन चुकी है।

सीटें बढ़ाने का रहेगा दबाव: 2019 के लोस चुनाव में कांग्रेस ने सिंहभूम और झामुमो ने राजमहल सीट पर जीत हासिल की थी। शेष सभी 12 सीटों पर राजग के प्रत्याशी (11 पर भाजपा और एक पर आजसू) जीते थे। ऐसे में आइएनडीआइए के सभी घटक दलों पर सीटों की संख्या बढ़ाने का दबाव है। राज्य में भाजपा ने कुल 14 में 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गठबंधन मजबूत प्रत्याशियों का चयन कर मतदान में उतारना चाहता है, ताकि परिणाम में उलटफेर कर भाजपा को झटका दिया जा सके।

- **सीटों के बंटवारे पर धैर्य छोड़ कांग्रेस ने पहले ही फार्मूला कर दिया सार्वजनिक**
- **झामुमो में भितरखाने बढ़ी नाराजगी, रणनीतिक तौर पर विपरीत असर की आशंका**
- **शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के भाजपा में जाने से बढ़ी हलचल**

हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा

झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं। इस बीच दुमका सीट से उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। दुमका से आठ बार सांसद रहे झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन अब वृद्ध हो चुके हैं और यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार वह चुनावी मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में पार्टी सहानुभूति वोट के लिए हेमंत को दुमका से उतार सकती है।

अतीत के आईने से

सुकुमार सेन ने कराया पहला आम चुनाव

आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। राजनीतिक दल से लेकर प्रत्याशी तक चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटे हैं। आज बात करेंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के बारे में, जिनकी देखरेख में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ।

1951 में चुनाव करवाने को व्यग्र थे जवाहरलाल नेहरू

1947 में भारत की आजादी के दो साल बाद, मार्च 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। सुकुमार सेन को उसका पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उसके एक महीने बाद संसद में लोक प्रतिनिधित्व कानून पारित हुआ। संसद में इस अधिनियम के प्रस्ताव को पेश करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनाव 1951 के बसंत की शुरुआत में होने की उम्मीद जताई। नेहरू की व्यग्रता स्वाभाविक थी, पर उस समय चुनाव करवाने वाले व्यक्ति का नजरिया कुछ सावधानी भरा था। वर्ष 1899 में पैदा हुए सुकुमार सेन ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के प्रेसीडेंसी कालेज और लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय में गणित विषय में स्वर्ण पदक मिला। सेन देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। शायद यह सेन की गणित की पृष्ठभूमि ही थी, जिसके कारण उन्होंने प्रधानमंत्री से देश में आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया। वह जानते थे कि आम चुनाव की तैयारियों में वक्त लगेगा।

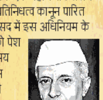

महासमर से जुड़ी खबरों और सामग्री को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र से राजनीति के देसी मैदान तक बढ़ते कदम

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ले ली। अमृतसर में जन्मे व पले-बढ़े संधू को भाजपा वहां से लोस उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो संधू भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) के दूसरे अधिकारी होंगे, जो इस आम चुनाव में भाजपा की तरफ से मैदान में होंगे।

2022 में विदेश सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हर्ष श्रृंगला बंगाल के दार्जिलिंग से इस बार अपना दम ठोक रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद से ही वह अपने गृह नगर दार्जिलिंग में डेरा डाल कर बैठे हैं। पिछले छह महीने से वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दार्जिलिंग भाजपा का पुराना गढ़ है और गृह नगर होने का लाभ भी श्रृंगला को मिलने की संभावना है। यह चर्चा भी है कि भाजपा विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी किसी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है।

विदेश सेवा के लोगों का भाजपा के प्रति और भाजपा का आइएफएस के प्रति लगाव का रिश्ता पुराना है। नरेन्द्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की विदेश नीति को लेकर नया अंदाज पेश किया। इसके जरिये विदेश सेवा विभाग को ज्यादा क्रियाशील व गतिशील बनाया गया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ज्यादातर देश में भारतीय दूतावास, उच्चायोग और मिशनों को आम आदमी के लिए खोला। इन मिशनों के जरिये मोदी ने सीधे तौर पर प्रवासी भारतीयों से संवाद की शुरुआत की। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के अंदाज को आक्रामक बनाया गया। मोदी को जब 2019 में दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने पूर्व विदेश सचिव (वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त) एस. जयशंकर को विदेश मंत्रालय की बागडोर सौंपी। आज जयशंकर वैश्विक मंच पर सबसे मुखर विदेश मंत्री हैं, जो ना सिर्फ भारत की वैश्विक नीति को साफगोई व धारदार तरीके से पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं बल्कि उनकी लोकप्रियता भारत के भीतर भी बढ़ रही है। जयशंकर से पहले पीएम मोदी ने 2017 में अपनी कैबिनेट में विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी हरदीप सिंह पुरी को आवास व शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। एक बेहद सफल कूटनीतिक करियर के बाद पुरी ने 2014 में भाजपा का दामन थामा था। मोदी के दूसरे कार्यकाल में पुरी को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और शहरी विकास जैसे दो बेहद मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा में आज भारतीय विदेश सेवा के चार पूर्व अधिकारी जुड़ चुके हैं।

पूर्व आइएफएस अधिकारियों को पहले भी मिला मौका: यह पहला मौका नहीं है, जब किसी सरकार में पूर्व आइएफएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। डा. मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल (2004-2009) में तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी पूर्व आइएफएस अधिकारियों ने संभाली थी। इसमें नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, जबकि मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय व पंचायती राज मंत्री थे। मीरा कुमार को समाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मनमोहन के दूसरे कार्यकाल (2009-2014) में मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के तौर पर सेवा दे चुके शशि थरूर भी मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं।

डा. जयशंकर से रविवार को मुलाकात के दौरान तरनजीत सिंह संधू • सौ. भाजपा

ग्रामीणों के साथ हर्ष श्रृंगला • जागरण आर्काइव

एक्स फैक्टर

- **भाजपा में शामिल हुए तरनजीत सिंह विदेश सेवा से राजनीति में आने वालों की ताजा कड़ी**
- **अमृतसर से इस बार हो सकते हैं उम्मीदवार, जयशंकर और पुरी पहले ही जमा चुके हैं जड़ें**
- **सेवानिवृत्त होने के बाद से ही अपने गृह नगर दार्जिलिंग में डेरा डाल कर बैठे हैं हर्ष श्रृंगला**

****

68 नेता सोमवार को एक साथ शामिल हुए मध्य प्रदेश भाजपा में। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर सहित बसपा प्रदेश प्रभारी डा. रामसखा वर्मा भी हैं। दल बदलने वालों में कांग्रेस के महामंत्री से लेकर पूर्व सरपंच तक शामिल हैं।

पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा

- राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष ने राजग से नाराज होकर उठाया कदम
- राजद के संपर्क में, हाजीपुर सीट से चिराग के विरुद्ध लड़ सकते हैं चुनाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजग में हिस्सेदारी नहीं मिलने से पारस नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे अपने त्यागपत्र में पारस ने राजग से संबंध तोड़ने के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है। दो वाक्यों के इस्तीफे में उन्होंने अपने ऊपर किए गए विश्वास के प्रति संतुलित शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया है, जो बताता है कि पारस ने विकल्प अभी बचाकर रखा है। हालांकि वह राजद के संपर्क में हैं और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं।

दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर प्रेस कान्फ्रेंस में पारस ने कहा -' मैं बेहद ईमानदारी के साथ राजग में रहा। प्रधानमंत्री मोदी बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी एवं व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं।' पारस 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने लोजपा के छह में से पांच सांसदों के साथ पार्टी को तोड़कर अलग गुट बना लिया था। केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले भाजपा ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग को भाव देकर पारस को नजरअंदाज कर दिया। भाजपा से लोजपा (रामविलास) की डील पक्की हो जाने और अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद चार दिन पहले पारस ने कहा था कि वह राजग एवं भाजपा की आधिकारिक सूची का इंतजार कर रहे हैं। हिस्सेदारी नहीं मिलने पर विकल्प खुला रखेंगे। भाजपा ने राजग के घटक दलों के साथ बिहार में सीट बंटवारा कर लिया और पारस को भाव नहीं दिया तो नाराज होकर उन्होंने भी केंद्र सरकार से नाता तोड़ लिया। उधर, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को विश्वास जताया कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रेसवार्ता करते राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस। प्रेट्र

चिराग की चतुराई में फंसकर 'पारस' बन गए पत्थर

- भाजपा से दोस्ती टूटते ही छिटकने लगे पारस के सहयोगी
- दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उनके साथ नहीं था कोई भी सांसद
- लोजपा तोड़कर चार सांसदों को उन्होंने कर लिया था अपने साथ

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

राजग में भतीजे चिराग पासवान को भाव मिलने से खफा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र देकर विकल्प की तलाश में निकल पड़े हैं। एक-दो दिनों में साफ हो जाएगा कि उन्हें कहां ठौर मिलता है और देश-प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी? इतना तय है कि उनके पास अब विकल्पों की कमी होगी। अभी दो ही रास्ते हैं-महागठबंधन में चले जाएं या फिर अपने दल का प्रत्याशी बनकर चिराग को हाजीपुर से चुनौती दें। फिलहाल वह चिराग की चालाकी और संतुलित राजनीति में बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं।

दिल्ली में मंगलवार की दोपहर प्रेस कान्फ्रेंस करके इस्तीफा देने वाले पशुपति पारस शाम होते-होते पटना पहुंच गए। लगभग तीन वर्ष पहले अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा से तोड़कर पारस जिन चार सांसदों को 'सोना' बनाने का सब्जबाग दिखाकर अपने साथ लाए थे, उनमें से किसी को सहेजकर नहीं रख पाए। दिल्ली में पारस की प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उनके साथ का कोई सांसद नहीं था। बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान के सांसद भाई चंदन सिंह भी नहीं और पारस का दूसरा सांसद भतीजा प्रिंस राज भी नहीं, जबकि पारस प्रिंस राज के सरकारी बंगले में ही रहते हैं। मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अलग बंगला नहीं लिया था। चार दिन पहले जब पारस ने भाजपा के फैसले पर पुनर्विचार के आग्रह के लिए प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी तो उनके अगल-बगल दोनों सांसद और सूरजभान भी थे। वैशाली की सांसद वीणा सिंह तो पहले ही पाला बदलकर चिराग के साथ चली गई थीं।

चिराग पासवान। फाइल

चिराग ने चली सधी चाल

रामविलास के निधन और पार्टी में टूट के बावजूद चिराग ने बहुत धैर्य और चतुराई के साथ अपने तीन वर्ष गुजारे। भाजपा के विरुद्ध मोर्चा नहीं खोला। बयानबाजी नहीं की और कदम-कदम पर जताते रहे कि वह आज भी मोदी के हनुमान हैं। इस भाव का उन्हें पुरस्कार मिला, जब भाजपा ने पारस को दरकिनार कर चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता चुना। पारस इस गलतफहमी में रह गए कि रामविलास के असली वारिस वही हैं।

भाजपा ने अंतिम समय तक पारस को समझाने का पूरा प्रयास किया। मंगल पांडेय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। दिल्ली-पटना के उनके दौरे बढ़ चुके थे। सूत्र का कहना है कि पारस और चिराग को भाजपा एक करना चाहती थी। इसके लिए पारस को आमचुनाव बाद किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और प्रिंस राज को एमएलसी बनाकर बिहार में मंत्री का पद। सूरजभान के भाई के लिए भी भाजपा का प्रस्ताव था। किंतु पारस अड़े रहे और नतीजा हुआ कि उन्हें गठबंधन बदलने पर मजबूर होना पड़ा।

पारस के पास विकल्प : भाजपा से अलग होकर राजद की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे पारस ने पहले से ही बोल रखा है कि वह हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। अब चिराग से दो-दो हाथ करने के लिए पारस को किसी दल या गठबंधन का सहारा चाहिए। सूचना है कि राजद से उनकी पहले से ही बातचीत चल रही थी। अगर दल के आधार पर गठबंधन होता है तो राजद को अपने मित्र दलों से सहमति लेनी पड़ेगी।

अमेरिका में राजदूत रहे संधू भाजपा में शामिल

अमृतसर से उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव के मैदान में

संधू ने कहा- अमृतसर तक पहुंचाना चाहिए विकास

नई दिल्ली, एएनआइ: अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। उन्होंने पार्टी महामंत्री विनोद तावड़े और तरुण चुघ की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली।

इस दौरान संधू ने भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती के बारे में बात की और कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझेदारी में बदल गए हैं जो दोनों के लिए लाभदायक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका लाभ रोजगार के अवसरों और विकास के मामले में अमृतसर जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम किया है, खासकर अमेरिका और श्रीलंका के साथ संबंधों के मामले में। तावड़े ने कहा कि संधू जैसे सफल कूटनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की मौजूदगी से पार्टी मजबूत होगी। संधू के पिता बिशन सिंह समुंद्री प्रसिद्ध शिक्षाविद् और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे। संधू ने फरवरी 2020 में अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक श्रीलंका के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। 2013 से 2017 तक वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख थे। 1997 से 2000 तक वाशिंगटन, डीसी में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी थे। 2011 से 2013 तक फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्यदूत रहे।

अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ, विनोद तावड़े तथा मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में भाजपा में सम्मिलित हो गए। प्रेट्र

अमृतसर सीट फिर जीतने के लिए प्रयासरत है भाजपा

प्रेट्र के अनुसार भाजपा पंजाब में अपना समर्थन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इस सीट पर भाजपा को आखिरी बार 2009 में जीत मिली थी, जब भाजपा के टिकट पर नवजोत सिंह सिद्धू सांसद चुने गए थे। सिद्धू अब कांग्रेस में हैं। भाजपा के अरुण जेटली और हरदीप सिंह पुरी क्रमश: 2014 व 2019 में यहां से लोकसभा चुनाव हार गए थे। संधू अमृतसर के सम्मानित जाट सिख परिवार से आते हैं और इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं।

हेमंत की विधायक भाभी सीता सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल

- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के समक्ष दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता
- झामुमो के साथ विधायकी भी छोड़ी, दुमका से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन झामुमो छोड़कर मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े तथा लक्ष्मीकांत बाजपेयी की उपस्थिति में भाजपा में सम्मिलित हो गईं। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक भाभी सीता सोरेन मंगलवार को झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं। इससे पहले उन्होंने झामुमो के साथ ही विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। चर्चा है कि भाजपा सीता सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। ऐसे में दुमका से घोषित भाजपा प्रत्याशी सुनील की उम्मीदवारी वापस ली जाएगी। दुमका झामुमो का गढ़ माना जाता है। यहां से शिबू सोरेन आठ बार सांसद रहे हैं।

भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड को झुकाएंगे नहीं, बल्कि और आगे बढ़ाएंगे। झामुमो छोड़ने को लेकर अपनी पीड़ा साझा करते हुए सीता ने कहा, अलग झारखंड मेरे ससुर शिबू सोरेन और पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के संघर्ष से बना। उनका सपना विकसित राज्य बनाने का था, लेकिन विकास नहीं हुआ। उन्होंने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन पत्र लिखकर कहा कि पति दुर्गा उरांव के निधन के बाद से झामुमो में वह उपेक्षा की शिकार होती रही हैं।

अमित शाह-राज ठाकरे की मुलाकात से शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस असहज

- संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुत्र अमित ठाकरे के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। प्रेट्र

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे की मंगलवार को मुलाकात ने शिवसेना (उद्धव गुट) एवं कांग्रेस को असहज कर दिया है। इन दोनों दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

राज ठाकरे से महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं की मुलाकात लंबे समय से होती आ रही है। बीच-बीच में राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिलते रहे हैं। लेकिन, अब तक यह तय नहीं हो पा रहा था कि राज ठाकरे की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी या वह किधर जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह कहकर असमंजस बढ़ा दिया था कि राज ठाकरे से बात तो हो रही है, हम कई मुद्दों पर एकमत भी हैं, लेकिन अभी 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' वाली स्थिति नहीं आ सकी है। इस बीच राज ठाकरे ने भी पिछले सप्ताह नासिक में हुए पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में यह कहकर कार्यकर्ताओं को निराश ही किया था कि राजनीति में धैर्य रखने की जरूरत होती है। अभी आप भी धीरज रखिए।

लेकिन, एक-दो दिन के अंदर ही भाजपा और मनसे के बीच बने समीकरणों का ही परिणाम है कि मंगलवार को राज ठाकरे अपने पुत्र अमित ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंच गए। वहां पहले उनकी मुलाकात महासचिव विनोद तावड़े से हुई। फिर वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के विपक्षी दलों को असहज कर दिया है। शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे के महायुति (महागठबंधन) में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग स्मार्ट हैं। हमारे वोट बांटने के लिए शाह कितनी भी योजनाएं बना लें, महाराष्ट्र की जनता इन योजनाओं को सफल नहीं होने देगी।

मनसे और भाजपा को मिलेगा इसका लाभ : राज ठाकरे और भाजपा का करीब आना दोनों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। राज ठाकरे ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। लेकिन, 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव न लड़ाते हुए भी भाजपा के विरुद्ध घूम-घूमकर कई रैलियां की थीं। भाजपा नहीं चाहती थी कि इस बार राज ठाकरे वही रुख दोहराएं। चूंकि वह अच्छे वक्ता हैं। इसलिए, उनके महायुति के मंच पर आने से भाजपा को लाभ ही होगा।

वास्तव में यह गठबंधन लोकसभा या विधानसभा से ज्यादा मुंबई महानगरपालिका चुनाव भाजपा को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। करीब 25 साल से मुंबई मनपा में जमी शिवसेना (अविभाजित) को इस बार भाजपा वहां से उखाड़ना चाहती है। दूसरी ओर राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के गिरते ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा का सहारा चाहते थे।

राज ठाकरे से गठबंधन कर भाजपा उत्तर भारतीयों का वोट कैसे मांगेगी : कांग्रेस

विपक्षी दल कांग्रेस को भी मनसे-भाजपा गठजोड़ रास नहीं आ रहा है। उसके प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इसे उत्तर भारतीयों से जोड़कर भाजपा से सवाल किया है कि राज ठाकरे से गठबंधन कर भाजपा उत्तर भारतीयों का वोट कैसे मांगेगी। लोंढे के अनुसार, यह गठबंधन एक तरह से उत्तर भारतीयों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ उत्तर भारतीय नेता रत्नेश सिंह कहते हैं कि भाजपा का असल चेहरा अब सामने आ गया है। अब तक वह उत्तर भारतीयों की नाराजगी के डर से छुपकर मदद करती थी। अब उसने खुलकर राज ठाकरे को साथ ले लिया है।

'कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मतलब नहीं, वे भाजपा में शामिल होंगे'

- असम के सीएम ने कहा, अब कोई कांग्रेस में नहीं रहना चाहता

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे अंततः भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। सरमा ने बराक घाटी के दो निर्वाचन क्षेत्रों-सिलचर और करीमगंज में भाजपा के लिए प्रचार करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि वे जीतें या हारें यह अलग बात है लेकिन सवाल यह है कि क्या उम्मीदवार कांग्रेस में रहेगा। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, वे भाजपा में शामिल होने को उत्सुक हैं। हिमंत सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारे सूरज हैं और हम उनके चांद हैं। पीएम मोदी से ही हमें ताकत मिल रही है और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कौन है, इसका कोई सवाल ही नहीं है। यहां कोई विपक्ष नहीं है। वो सभी हमारे हैं और हम उन्हें बुलाएंगे तो वो हमसे जुड़ेंगे। सरमा ने कहा कि अल्पसंख्यक कोई मुद्दा नहीं है। हम अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं और अब पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बिना रिश्वत दिए नौकरियां मिल रही हैं। क्या उन्हें कांग्रेस शासन के दौरान कभी नौकरियां मिलीं? उन्होंने दावा किया कि भाजपा करीमगंज और नगांव की अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर आसानी से जीत हासिल करेगी। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई के जोरहाट से चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भारी अंतर से हारेंगे।

हिमंत विस्वा सरमा। फाइल

टेरर फंडिंग के आरोपित इंजीनियर रशीद चुनाव लड़ने की तैयारी में

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : टेरर फंडिंग के आरोपित पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद भी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अनुसार, उनके चेयरमैन इंजीनियर रशीद उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामुला-कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इंजीनियर रशीद अगस्त, 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इंजीनियर रशीद का असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। वह वर्ष 2008 और वर्ष 2014 में उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत लंगेट विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए हैं। राजनीति में आने से पहले वह जम्मू-कश्मीर लोक कार्य विभाग में इंजीनियर थे। कश्मीर में जनमत संग्रह के समर्थक रहे इंजीनियर रशीद संसद हमले में शामिल आतंक अफजल, हिजबुल आतंकी बुरहान वानी समेत मारे गए सभी आतंकियों को बलिदानी बताते रहे हैं। इंजीनियर रशीद वर्ष 2019 में भी बारामुला-कुपवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने उस समय अपने चुनाव प्रचार में इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया था।

तेदेपा-भाजपा-जनसेना गठबंधन 160 से अधिक विस सीटें जीतेगा : चंद्रबाबू

अमरावती, आइएएनएस : तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को विश्वास जताया कि तेदेपा-भाजपा-जनसेना गठबंधन 160 से अधिक विधानसभा सीटें जीतकर आंध्र प्रदेश में सत्ता में आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री को यह भी विश्वास है कि राजग 400 से अधिक लोकसभा सीटें हासिल करेगा।

चंद्रबाबू नायडू ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरे आंध्र प्रदेश में चल रही लहर एक प्रगतिशील युग की शुरुआत का संकेत दे रही है। आंध्र प्रदेश में राजग के तीन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार तेदेपा 175 विधानसभा सीटों में से 144 और 25 लोकसभा सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ेगी। जन सेना जहां 21 विधानसभा हलकों और दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी,वहीं भाजपा 10 विधानसभा और छह लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

इस बीच, नायडू ने आंध्र प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि राज्य में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वाइएसआर कांग्रेस राजनीतिक हिंसा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि वाइएसआर के गुंडे सत्ता खोने के डर से अवसाद में हैं और तेदेपा कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं।

भाजपा ने तमिलनाडु में पीएमके को दीं 10 सीटें

चेन्नई, प्रेट्र: तमिलनाडु में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और डा. रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के बीच मंगलवार को सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया। क्षेत्रीय पार्टी पीएमके 10 और भाजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई और पीएमके संस्थापक रामदास ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाजपा और अन्नाद्रमुक दोनों ही पीएमके के साथ गठबंधन करने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि अंत में पीएमके ने भाजपा के साथ गठबंधन किया।

चुनावी दंगल

पहले पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से कर दिया था इन्कार, अब फिर कमेंटेटर के रूप में करेंगे पारी की नई शुरुआत, आइपीएल में व्यस्त रहने से चुनाव प्रचार में नहीं ले पाएंगे हिस्सा

नवजोत सिद्धू ने छोड़ा चुनावी रण, आइपीएल में करेंगे कमेंट्री

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्व की ओर से राज्य की राजनीति से किनारे करने की कवायद के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने बड़ा दांव चल दिया है। पहले पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से किनारा करने के बाद अब वह इंडियन पालीटिकल लीग यानी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रण से भी दूर रहेंगे। वे इस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के मैचों में कमेंट्री करने में व्यस्त रहेंगे। लंबे समय बाद सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी पारी की नई शुरुआत कर रहे हैं।

स्टार स्पोर्ट्स ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि सरदार आफ कमेंट्री बाक्स इज बैक। इससे साफ है कि आइपीएल में कमेंट्री करने के कारण सिद्धू उस समय सक्रिय राजनीति में दूर रहेंगे, जब पार्टी को उनकी जरूरत होगी। चूंकि, लोकसभा चुनाव और आइपीएल का समय एक ही है, इसलिए सिद्धू चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि, अभी आइपीएल के पहले चरण का कार्यक्रम ही जारी हुआ है। शेष कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। दरअसल, लंबे समय से सिद्धू पार्टी की सक्रिय राजनीति से दूर हैं। कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्व के साथ उनकी बन नहीं रही है। प्रादेशिक नेतृत्व उन्हें पटियाला लोकसभा सीट पर उतारना चाहता था। पार्टी हाईकमान पर लगातार जोर डाला जा रहा था कि सिद्धू को परनीत कौर की जगह पर पटियाला से खड़ा किया जाए। कांग्रेस में लंबे समय तक सांसद रहीं परनीत कौर पिछले सप्ताह ही भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनका पटियाला से भाजपा के टिकट पर लड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में किसी बड़े चेहरे के रूप में सिद्धू को उतारे जाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि, सिद्धू ने दो दिन पहले दैनिक जागरण के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।

सिद्धू और बाजवा ने एक-दूसरे पर किए थे शाब्दिक हमले

सिद्धू जब अप्रैल, 2023 में रोडरेज मामले में एक साल की सजा पूरी करके बाहर आए थे, तब वह कुछ समय के लिए अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ रहे। जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी के समानांतर राजनीतिक रैलियां शुरू की तो प्रादेशिक नेतृत्व को यह स्वीकार नहीं हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने तो यहां तक कह दिया कि सिद्धू साहब अपना अलग से अखाड़ा न लगाएं, बल्कि पार्टी की रैलियों में शामिल हों, लेकिन सिद्धू ने उनके ऊपर ही शाब्दिक हमला कर दिया। सिद्धू ने अलग-अलग क्षेत्रों में चार सफल रैलियां की। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने जब हस्तक्षेप किया तो उन्होंने रैलियां बंद कर दीं। साथ ही स्वयं को सक्रिय राजनीति से पीछे कर लिया। अब कमेंट्री करने के निर्णय से लगता है कि उन्होंने खुद को राजनीति से ही दूर कर लिया है।

****

शशि थरूर का तिरुअनंतपुरम में लेफ्ट पर वोट बांटने का आरोप

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि तिरुवनंतपुरम में उनके खिलाफ भाकपा के अभियान का एकमात्र प्रभाव भाजपा विरोधी वोट को विभाजित करना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वे वायनाड में गठबंधन धर्म का प्रचार करते हैं! इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा कि यह वामपंथी हैं जो 'सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं।'

शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि जो भाकपा वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाती है, वह तिरुअनंतपुरम में भाजपा के खेल में शामिल है। वह वायनाड में गठबंधन धर्म का प्रवचन देते हैं, लेकिन तिरुअनंतपुरम में भाजपा विरोधी वोटों के दो फाड़ कर दिए हैं। थरूर का मानना है कि निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में उनका काम खुद बोलेगा। इस पर पलटवार करते हुए भाकपा नेता डी. राजा ने सवाल किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। उनके मुख्य राजनीतिक दुश्मन कौन हैं...।

शशि थरूर। फाइल

8 सीटों पर मतदान होगा उत्तर प्रदेश में पहले चरण में। 20 मार्च से नामांकन शुरू होगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों में से तीन भाजपा, तीन बसपा व दो सपा ने जीती थीं। पिछले चुनाव में सपा, बसपा व रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था।

चुनावी हलचल

'अबकी बार 400 पार' नारे पर मैनपुरी के कवि का दावा

फेसबुक पर अवध मिश्रा के एकाउंट से पांच अगस्त 2019 को पोस्ट की गई कविता का स्क्रीनशाट। सौजन्य : स्वयं

मैनपुरी: लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा का 'अबकी बार 400 पार' का नारा खूब गूंज रहा है। पार्टी रैलियों में इसी नारे से माहौल बना रही है। अब इस नारे पर मैनपुरी के एक कवि ने अपना अधिकार जताया है। कवि का दावा है कि यह नारा उनकी एक कविता से लिया गया है, जिसे उन्होंने चार साल पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था। कवि ने नारे के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। कवि अवध बिहारी मिश्रा ने पांच अगस्त, 2019 को अपने फेसबुक एकाउंट पर एक कविता पोस्ट की थी। अवध बिहारी का आरोप है, भाजपा के आइटी सेल द्वारा इस कविता को उठाकर नारा बनाया गया है। इस नारे को बनाने में उनके योगदान को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से भाजपा के इस नारे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। (जासं)

...जब मेघालय में एडोल्फ हिटलर को जान एफ. केनेडी ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र: मेघायल में 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान 'एडोल्फ लू हिटलर को जान एफ. केनेडी ने किया गिरफ्तार' शीर्षक से अखबारों में छपी खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कई अखबारों में छपे शीर्षक ने पाठकों को खबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था और देखते ही देखते ही यह खबर राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि बता दें कि दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी जर्मन तानाशाह को गिरफ्तार नहीं किया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर यह किस्सा साझा किया। आयोग ने अपने पोस्ट में कहा कि राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) एडोल्फ लू हिटलर मारक को पुलिस अधीक्षक जान एफ.केनेडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि आयोग ने गिरफ्तारी के कारणों को अपने एक्स पोस्ट में साझा नहीं किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में हिटलर ने चुनाव में जीत हासिल लिया था। गत वर्ष एडोल्फ लू हिटलर मारक गत वर्ष तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और उसने अप्रैल 1945 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की नवंबर 1963 में हत्या कर दी गई थी।

कांग्रेस ने किया केरल में मतदान की तारीख बदलने का आग्रह

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : केरल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एमएम हसन ने चुनाव आयोग से केरल में मतदान की तारीख को बदलने का आग्रह किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केरल में मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार को होना है। एमएम हसन ने कहा, मतदान के दिन शुक्रवार होने के कारण एक वर्ग को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए तारीख बदलने का आग्रह किया है।

अमेरिका में मोदी की जीत के लिए हवन

वाशिंगटन, प्रेट्र : सिलिकन वैली में भारतवंशियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत की कामना करते हुए एक हिंदू मंदिर में हवन किया। हवन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

लोकसभा की 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से

जागरण टीम, नई दिल्ली

▸ **आज जारी होगी पहले चरण की अधिसूचना, 19 अप्रैल को मतदान**

लोकसभा चुनाव-2024 के पहले चरण की अधिसूचना बुधवार को जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होंगे। इस चरण के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं बिहार के लिए यह तारीख 28 मार्च है। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च है, जबकि बिहार में दो अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में कुल दस राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएंगे।

चेन्नई में युवा मतदाताओं के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलातीं कालेज की छात्राएं। एएफपी

पहले चरण में मतदान

पुडुचेरी (1), मिजोरम (1), मेघालय (2), मध्य प्रदेश (6), मणिपुर (2), महाराष्ट्र (5), अरुणाचल प्रदेश (2), असम (5), बिहार (4), छत्तीसगढ़ (1), जम्मू-कश्मीर (1), लक्षद्वीप (1), राजस्थान (12), सिक्किम (1), तमिलनाडु (39), त्रिपुरा (1), उत्तराखंड (5), उत्तर प्रदेश (8), बंगाल (3), नगालैंड (1), अंडमान निकोबार (1)।

उत्तर प्रदेश : सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर व पीलीभीत। 2019 में इन आठ सीटों में से तीन भाजपा, तीन बसपा व दो सपा ने जीतीं थीं।

मध्य प्रदेश : सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। 2019 में छिंदवाड़ा को छोड़कर शेष पांच सीटें भाजपा ने जीती थीं।

बंगाल : कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। 2019 में इन तीनों ही सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी।

राजस्थान : श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर। 2019 में भाजपा ने 12 में से 11 और एक सीट एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती थी।

बिहार : औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। 2019 में चारों सीटें राजग ने जीती थीं। जमुई और नवादा में लोजपा तो गया में जदयू व औरंगाबाद में भाजपा को जीत मिली थी।

उत्तराखंड : गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल-ऊधम सिंह नगर। पिछली बार पांचों सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी।

अधिसूचित विभागों के कर्मियों को ही पोस्टल बैलेट सुविधा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **सभी जिलों में इसके लिए अलग से नोडल अफसर तैनात होंगे**

चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिये होने वाले मतदान में गड़बड़ी की लगातार मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार इस पूरी व्यवस्था को और फूलप्रूफ बनाया है। इसके तहत सभी जिलों में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था संभालने के लिए एक नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश हैं। साथ ही सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को भी अधिसूचित किया गया है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के कर्मियों को इस बार चुनावों में पोस्टल बैलेट के जरिये वोटिंग की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक सेवा वाले विभागों की संख्या अलग-अलग है। सबसे लंबी सूची आंध्र प्रदेश ने दी है, जिसकी संख्या 33 है। अधिकारियों के मुताबिक राज्यों में इसके पात्र कर्मचारियों को पहले से ही चिन्हित कर दिया गया है। आयोग ने इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी सभी राज्यों में पोस्टल बैलेट की सुविधा देते हुए उन्हें आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल किया है। अब तक कुछ राज्यों में ही मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती थी।

बंगाल की छह लोकसभा सीट आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य के छह लोकसभा क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है। साथ ही चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्यों की 22 जांच एजेंसियों को उन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया है। आयोग की वित्तीय रूप से संवेदनशील केंद्रों की सूची में दार्जिलिंग, मालदा उत्तर और दक्षिण, आसनसोल, बनगांव और कोलकाता उत्तर शामिल हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में उन केंद्रों से काफी रुपये बरामद किए गए थे, शराब जब्त की गई थी, इसलिए इन केंद्रों पर अतिरिक्त ध्यान देने की बात कही गई है। 22 जांच एजेंसियों के लिए 22 पर्यवेक्षक हैं। एजेंसियों की ओर से प्रतिदिन आयोग के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट दी जाती है। इसके बाद आयोग पर्यवेक्षकों से प्रतिदिन रिपोर्ट लेता है। चुनाव आयोग ने इस बार पहले ही उन छह केंद्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित कर गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दे दी है।

11 राज्यों की 80 सीटों पर प्रत्याशी तय

कांग्रेस की बैठक ▸ एक-दो दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की तीसरी सूची

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा पूरी कर ली है। इसमें 11 राज्यों की करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। और अगले एक-दो दिनों में की घोषणा कर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव समिति की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे उन राज्यों की सीटों की चर्चा नहीं की गई है जहां कांग्रेस गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, अंडमान-निकोबार, कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ की एक सीट के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। बताया जाता है कि तीसरी सूची में 80 सीटों में से अधिकांश पर नाम तय हो गए हैं। चंडीगढ़ सीट को लेकर तीन उम्मीदवारों के पैनल पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका तो मामला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश की सीटें चर्चा के एजेंडे में नहीं थीं इसलिए अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की उम्मीदवारी पर सियासी सस्पेंस अभी बरकार है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली दो सूचियों को मिलाकर कांग्रेस अब तक अपने 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव समिति के सदस्य हैं मगर वे मंगलवार को हुई इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

नई दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी। प्रेट्र

चुनाव लड़ने से इन्कार करने वाले रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पर लगाया परेशान करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

रोहन गुप्ता। फाइल

अहमदाबाद पूर्व से बनाये गये हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रोहन गुप्ता

अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने पार्टी नेताओं पर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने कहा है कि रोहन नाम बताएं, ऐसे नेता को पार्टी से बाहर कर देंगे। प्रदेश प्रवक्ता मनीष दोशी ने इसे पार्टी के लिए आघात बताते हुए कहा है कि रोहन के लिए एक अच्छा अवसर था।

सोमवार रात्रि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व अहमदाबाद पूर्व से पार्टी के घोषित प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद पार्टी में खलबली मच गई। इससे पहले उनके पिता एवं गुजरात कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रमुख राजकुमार गुप्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को पत्र भेजकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुप्ता दो दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन मंगलवार को स्वयं रोहन सामने आए और कहा कि पिता को डर था कि मेरे साथ पार्टी में कुछ बुरा हो सकता है। पिता के साथ पार्टी के नेताओं ने कई बार गलत व्यवहार किया तथा उनको नुकसान पहुंचाया। इसलिए वे चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा न हो। रोहन ने पिता की जिद के आगे हार मान कर चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को अंतिम बताया है। उनका कहना है कि मुझे गद्दार व बेईमान बताने वाले नेता स्वयं का आकलन करें कि उन्होंने पार्टी में रहकर कितना नुकसान किया है। मैं और मेरे पिता कई दशक से कांग्रेस से जुड़े हैं। हर जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन अब पिता व परिवार की कीमत पर राजनीति नहीं करना चाहता। उधर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पार्थिवराज सिंह कठवाडिया, प्रवक्ता अमित नायक समेत कई युवा नेताओं ने इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।

दबाव बनाने के लिए भाजपा विधायक ने दिया इस्तीफा: वडोदरा जिले की राजनीति में इस बार उबाल नजर आ रहा है। सांसद रंजन भट्ट को उम्मीदवार घोषित करने के बाद भाजपा के कई नेता अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। सावली से विधायक केतन इनामदार ने बीती रात्रि मेल कर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, मंगलवार सुबह पार्टी अध्यक्ष सीआर पाटिल के हस्तक्षेप के बाद वह मान गए। इसे दबाव बनाने की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत कई दिग्गज भाजपा में: उत्तर गुजरात की धानेरा सीट से विधायक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता जोइता भाई पटेल भाजपा में शामिल हो गये। उनके साथ डीसा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लेबजी ठाकोर, धानेरा खरीद बेचाण संघ के अध्यक्ष हरदास पटेल ने भाजपा की सदस्यता ली।

वरुण गांधी व स्वामी प्रसाद को टिकट दे सकती है सपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भाजपा सांसद वरुण गांधी व सपा छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। मंगलवार को वरुण के सपा से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा संगठन तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा कि वह सपा छोड़कर कब गए थे।

लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जब अखिलेश से पूछा गया कि भाजपा सांसद वरुण गांधी के टिकट कटने की चर्चा है, क्या आप उन्हें टिकट देंगे, इस पर उन्होंने कहा इस पर हमारा संगठन निर्णय लेगा। इससे साफ संकेत है कि सपा आने वाले वक्त में वरुण गांधी को टिकट दे सकती है। उन्होंने इससे पहले पीलीभीत लोकसभा सीट के पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से वहां के बारे में विस्तृत चर्चा की। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद की वापसी के सवाल पर कहा कि क्या वे कभी सपा छोड़कर गए थे? जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वामी प्रसाद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो वह बोले, हमारी समिति विचार कर रही होगी। स्वामी प्रसाद भी सपा के प्रति नरमी का संकेत देते हुए विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के खिलाफ वोट कर इन गारंटी वालों की 'घंटी' बजाएंगे।

महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को दिया सात लोकसभा सीटों पर समर्थन का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▸ **कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को पत्र लिखकर कहा, महाविकास आघाड़ी वीबीए को आमंत्रित किए बिना लगातार कर रही बैठकें**

वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने मंगलवार को अपनी पार्टी के प्रति असमान रवैये के लिए शिवसेना (उद्धव गुट) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के प्रति नाराजगी व्यक्त की और महाविकास आघाड़ी के तीसरे घटक कांग्रेस को सात लोकसभा सीटों पर समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कांग्रेस को वीबीए के प्रस्ताव को न केवल एक 'सद्भावना संकेत', बल्कि भविष्य के संभावित गठबंधन के लिए 'दोस्ताना हाथ' भी बताया है।

आंबेडकर ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर कहा कि चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है और महाविकास आघाड़ी किसी भी चर्चा या बैठक के लिए वीबीए को आमंत्रित किए बिना लगातार बैठक कर रही है।

शिवसेना (उद्धव गुट) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने उनकी बात सुनने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मविआ की कुछ बैठकों में वीबीए के प्रतिनिधि भी गए थे। लेकिन वीबीए के प्रति उनके असमान रवैये के कारण हमने इन दोनों पार्टियों पर विश्वास खो दिया है।

आंबेडकर ने लिखा है कि वीबीए का मुख्य एजेंडा एक ही है, फासीवादी, विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक भाजपा-आरएसएस सरकार को सत्ता से बाहर करना। इस विचार के साथ मैंने महाराष्ट्र में सात सीटों पर कांग्रेस को वीबीए का पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कांग्रेस को महाराष्ट्र की वह सात सीटें चिन्हित कर बताने को कहा है, जिन पर उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना पूरा जमीनी और रणनीतिक समर्थन देगी। आंबेडकर के अनुसार, वीबीए की ओर से कांग्रेस को दिया गया प्रस्ताव न केवल सद्भावना है, बल्कि भविष्य के लिए संभावित गठबंधन के लिए मैत्रीपूर्ण हाथ का विस्तार भी है।

प्रकाश आंबेडकर। फाइल

वीबीए को अभी तक मविआ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला

पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वीबीए को अभी तक मविआ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और हमने मविआ द्वारा पहले भेजे गए तीन सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। फिलहाल, कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) के बीच 10 सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। आंबेडकर ने दावा किया कि तीन सहयोगियों - कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) में से कोई भी पांच महत्वपूर्ण सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

अकोला से की अपनी उम्मीदवारी की घोषणा

प्रकाश आंबेडकर ने अकोला से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले अकोला लोकसभा सीट पर मेरे खिलाफ दो बार मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था। इस बार भी अगर कांग्रेस अकोला में मेरे खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती है तो उस पार्टी का समर्थन पूरे देश में खत्म हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वीबीए महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि वह मविआ के फैसले का इंतजार करेंगे। बता दें कि आंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए ने जनवरी 2023 में ही शिवसेना (शरदचंद्र पवार) से गठबंधन कर लिया था। इसके बावजूद अब तक उन्हें महाविकास आघाड़ी का सदस्य नहीं बनाया गया है।

राजद नेता के बिगड़े बोल, कहा- मोदी की खोपड़ी में गोली मार देंगे तो...

जागरण संवाददाता, बोकारो

अवधेश सिंह यादव

वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर भाजपा ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग

झारखंड के कोडरमा में आइएनडीआइए की बैठक के दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव के बोल बिगड़ गए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खोपड़ी में गोली मार देने की बात की। इसका वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में यादव यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि देश का किसान अधिकार के लिए लड़ रहा है तो उस पर गोली चल रही है। हम मोदी की खोपड़ी में गोली मार देंगे तो गलत कहा जाएगा क्या? हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। राजद नेता के बयान को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर वीडियो अपलोड करते हुए आइएनडीआइए पर हमला बोला है। लिखा है-देखिए आइएनडीआइए का एजेंडा। बिहार के बालू माफिया सुभाष यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चार दिन पहले झारखंड के कोडरमा में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में आरजेडी के नेता अवधेश सिंह यादव मोदी की खोपड़ी में गोली मारने की बात कर रहे हैं।

शरद गुट को राकांपा-शरदचंद्र पवार नाम के उपयोग की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरद पवार गुट को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने इस गुट को पार्टी चुनाव चिह्न के तौर पर 'तुरही बजाता आदमी' के उपयोग की भी अनुमति दी है।

▸ **सुप्रीम कोर्ट ने 'तुरही बजाता आदमी' के उपयोग की भी दी इजाजत**

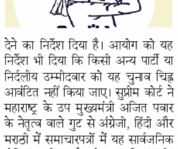

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने शरद गुट की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अजित पवार गुट को निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित 'घड़ी' चुनाव चिह्न का उपयोग करने से इस आधार पर रोकने की मांग की गई थी कि यह समान अवसर को बाधित कर रहा है। शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विभाजन से पहले इसका चुनाव चिह्न 'घड़ी' था। अब यह चिह्न अजित पवार की अगुआई वाले गुट के पास है। पीठ ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार और उसके चुनाव चिह्न 'तुरही बजाता आदमी' को मान्यता देने का निर्देश दिया है। आयोग को यह निर्देश भी दिया कि किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को यह चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में समाचारपत्रों में यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि 'घड़ी' चुनाव चिह्न अदालत में विचाराधीन है और इसका उपयोग फैसले के आधार पर होगा। आडियो-वीडियो विज्ञापनों और बैनर-पोस्टर आदि में भी इसी तरह की घोषणा करने को कहा है।

चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर बंगाल के डीजीपी को फिर बदला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

आयोग की नजर

▸ **विवेक सहाय की जगह वरिष्ठ आइपीएस संजय मुखर्जी बनाए गए नए डीजीपी**

▸ **बंगाल सरकार ने भेजी थी तीन अधिकारियों की सूची**

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजीव कुमार की जगह बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पद से हटा दिया। आयोग ने राज्य सरकार को उनके स्थान पर संजय मुखर्जी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहाय को वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त किया गया था, चूंकि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले मई के पहले सप्ताह में ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए आयोग ने उनके स्थान पर मुखर्जी को तत्काल डीजीपी नियुक्त करने को कहा है। भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मुखर्जी डीजीपी के पद के लिए निर्वाचन आयोग को बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई तीन अधिकारियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे।

बता दें कि इससे पहले 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता घायल हो गई थीं, उस समय उनके मुख्य सुरक्षा सलाहकार विवेक सहाय ही थे। उस घटना के बाद भी आयोग ने सहाय को हटा दिया था। पिछले नवंबर में उन्हें डीजी (होम गार्ड) के पद पर तैनात किया गया था।

संजय मुखर्जी। फाइल

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो 2024 का लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के दो दिनों के भीतर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बंगाल के डीजीपी पद से राजीव कुमार को हटाए जाने से भड़की तृणमूल कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम चुनाव कराने की मांग की है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। तृणमूल ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिवार में अपराधियों को शामिल बताते हुए अपने एक्स हैंडल पर भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें पोस्ट कर उनपर दर्ज आपराधिक मामले गिनाए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी तृणमूल को पहले जाकर शीशे में अपना मुंह देखना चाहिए।

जालंधर के डीसी का तबादला, एडीजीपी व डीआइजी को भी हटाया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने एक शिकायत के आधार पर मंगलवार को जालंधर के डीसी विशेष सारंगल का तबादला कर दिया है। सारंगल का तबादला इसलिए किया गया है, क्योंकि जालंधर उनका गृह जिला है। इसी तरह आयोग ने रोपड़ रेंज के एडीजीपी जसकरण सिंह और बार्डर रेंज के डीआइजी नरेन्द्र भार्गव को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीनों अधिकारियों को मौजूदा जिलों से बाहर लगाने को कहा है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि इनकी नई तैनाती उन जिलों में की जाए, जहां इनके गृह जिले की लोस सीट न आती हो। जसकरण व भार्गव अप्रैल और जून 2024 में सेवानिवृत्त भी होने जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में राकेश कंवर से लिया सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले अभिषेक जैन गृह सचिव का काम देख रहे थे, जिन्हें चुनाव आयोग के आदेश के बाद सोमवार को पद से हटाया गया था। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर को भी सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त दायित्व से भारमुक्त कर दिया है। ओंकार शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं वित्तायुक्त राजस्व हैं। इनके पास जनजातीय विकास तथा जल शक्ति विभाग का भी दायित्व है। ओंकार की नियुक्ति के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से हुए हैं।

****

250 जवान सीआइएसएफ के संसद परिसर में और तैनात किए जाएंगे। इनमें से 230 जवानों की सुरक्षा प्रभाग और अन्य की बल के अग्निशमन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। गत जनवरी में सीआइएसएफ के 140 जवानों को पहली बार यहां तैनात किया गया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 20 मार्च, 2024

भारत का चीन को कड़ा संकेत

कहा ▸ अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा

प्रधानमंत्री मोदी बोले– हिंद महासागर में भारत स्वतंत्र नौपरिवहन के लिए प्रतिबद्ध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हाल के दिनों में चीन की तरफ से जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयानबाजी बढ़ गई है, उसको देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। हर स्तर पर भारत अपने इस पड़ोसी देश को संकेत दे रहा है कि वह हर तरह की चुनौती से निपटने को तैयार है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले चीन के विदेश मंत्रालय और उसके बाद वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से नागवार गुजरने वाली टिप्पणियां की गई हैं। चीन सीधे तौर पर भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य को अपना हिस्सा करार देने लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्रालय को सीधा और करारा जवाब दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा है

रणधीर जायसवाल। फाइल

कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बेतुका बयान हमने देखा है। इन आधारहीन दावों का कोई महत्व नहीं है। वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहां के लोग हमारी विकास परियोजनाओं और ढांचागत विकास से आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे।

दूसरी तरफ, पीएम नरेन्द्र मोदी ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की तरफ से समुद्री डाकुओं के खिलाफ की गई सफल कार्रवाई के संदर्भ में एक बयान दिया है जो चीन की तरफ इशारा है। पिछले दिनों भारतीय नौसेना ने कार्रवाई करके हिंद महासागर में बुल्गारिया के एक जहाज को छुड़वाया था और दस्युओं के चंगुल से इस जहाज पर काम करने वाले बुल्गारियाई नागरिकों को बचाया था। 35 समुद्री डाकुओं को भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने इसकी तारीफ करते हुए भारतीय नौसेना और पीएम नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद कहा है। इसके जवाब में मोदी ने एक्स पर लिखा है–' हमें इस बात की खुशी है कि सात बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और अपने देश लौट रहे हैं। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में नौपरिवहन के स्वतंत्र आवागमन और समुद्री डाकुओं से क्षेत्र को मुक्त कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।' सनद रहे कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक होती गतिविधियों से इस पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र परिवहन को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं। पीएम मोदी इसी तथ्य को सामने लाए हैं।

बता दें कि बीते नौ मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इससे सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होगी। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है और जांगनान नाम से पुकारता है। वह भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के दौरों पर आपत्ति जताता रहा है।

सौंदरराजन का इस्तीफा मंजूर, झारखंड के राज्यपाल को तेलंगाना का भी प्रभार

नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं तमिलसाई सौंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी रिलीज के मुताबिक, राधाकृष्णन तेलंगाना-पुडुचेरी में नियमित नियुक्तियां होने तक प्रभार संभालेंगे। 62 वर्षीय तमिलसाई ने राज्यपाल और उपराज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद कहा था कि उनके ऊपर ऐसा करने का कोई दबाव नहीं था। अब वह जनसेवा करना चाहती हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनका अगला कदम क्या होगा और क्या वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? इस पर उन्होंने कहा कि वह अपनी योजनाओं के बारे में बाद में बताएंगी। तमिलसाई ने यह भी कहा कि उन्होंने संवैधानिक पदों से इस्तीफा देने के फैसले के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सूचित कर दिया है। वे जानते हैं मैं क्या चाहती हूं। माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में सौंदरराजन भी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं।

बघेल के राजनीतिक सलाहकार पर कांग्रेस के फंड गबन का आरोप

राज्य ब्यूरो, रायपुर

▸ छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भूचाल, पार्टी फंड के 5.89 करोड़ बेटे की कंपनी में लगाए, कोषाध्यक्ष भी घेरे में

छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) में एक नया भूचाल आ गया है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी फंड के 5.89 करोड़ रुपये का गबन कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के सदस्य व प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं, विनोद वर्मा ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि पार्टी कोषाध्यक्ष को बिना पार्टी समिति की जानकारी के फंड जारी करने की अनुमति नहीं है। पार्टी संविधान के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तावों पर स्वीकृति आवश्यक होती है।

सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने अपने मित्र विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब, गाजियाबाद को 5.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसकी जानकारी पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं दी गई। अरुण सिसोदिया ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन समिति सहित कई बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। मैं पार्टी के प्रति ईमानदार हूं, लेकिन कई भितरघाती पार्टी को खोखला कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से कार्यकर्ताओं का दर्द बयां करते हुए सिसोदिया ने कहा कि सरकार आने के बाद भी संगठन को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता था। हमारे द्वारा कई बार बैठक में और प्रभारी कुमारी सैलजा से अनुरोध करने के बावजूद ब्लाक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को संगठन के कार्य करने 5-10 हजार रुपये तक नहीं दिए गए, पर अपने परिवार के लोगों को एक कमरे में बैठकर कार्यादेश और गवाह निजी लोगों को बनाकर भुगतान कर दिया गया। 5.89 करोड़ रुपये के मामले में खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने गवाही में अपना हस्ताक्षर किया है।

भाजपा ने किया तंज

भाजपा इस मामले में कहा है कि कांग्रेस ने दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश की। अब खुद का घर नहीं बचा पा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि भूपेश सरकार के जनता से किए गए लूट के मामले तो सामने आ रहे हैं, अब कांग्रेस के पदाधिकारी पार्टी फंड को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

विनोद के फ्लैट में रहते हैं किरायेदार

जासं, साहिबाबाद : गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम की महागुन मेंशन फेज वन सोसायटी का फ्लैट नंबर 416 विनोद वर्मा का है। इसमें अनामिका मित्रा व उनके पति केके मित्रा स्वजन संग किराये पर रहते हैं। उन्होंने नवंबर, 2023 में किराये पर यह फ्लैट लिया था। अनामिका ने बताया कि यहां कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं होती। कंपनी के बारे में नहीं पता है। उनकी विनोद वर्मा से बात होती है, लेकिन कंपनी के बारे कुछ जानकारी नहीं है। वह यहां आए भी नहीं है। सोसायटी मेंटेनेंस मैनेजर राजीव ने बताया कि वह अब यहां नहीं आते हैं। एक फोटो व प्रार्थना पत्र से किरायेदार का सत्यापन हो जाता है। उन्होंने विनोद वर्मा को काफी दिन से यहां नहीं देखा।

प्रवासी श्रमिकों को दो माह में राशन कार्ड दें राज्य सरकारें : सुप्रीम कोर्ट

▸ कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश, पहले सरकारों को दिया था तीन महीने का समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि दो महीने के अंदर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। यह वह श्रमिक हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

जस्टिस हिमा कोहली और ए. अमानुलाह की खंडपीठ ने 20 अप्रैल, 2023 तक कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन की विफलता के बाद नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे पहले के आदेश में अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए तीन महीने का समय दिया था। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत निर्धारित कोटे के अतिरिक्त जारी करने अनिवार्य हैं। पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बेवजह की देरी से 80 करोड़ राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी में भी बाधा आ रही है। नए कार्डधारकों को इनसे संबद्ध करने से पहले इसको भी अपडेट किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने

शीर्ष अदालत का महत्वपूर्ण निर्देश।

केंद्र से ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा है कि बिना राशन कार्ड के भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

पीठ ने कहा कि हर नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित होना चाहिए और कल्याणकारी राज्य में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों तक पहुंचे। सरकार की ओर से बताया गया था कि लगभग 38 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से केंद्र द्वारा संचालित एक आनलाइन पोर्टल ई-श्रम पर देश भर के लगभग 28 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।

'आरोपित पर संदेह का मजबूत कारण हो तो तय किया जा सकता है आरोप'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अगर किसी अपराध में आरोपित की भूमिका को लेकर संदेह का मजबूत कारण हो तब भी आपराधिक मामले में आरोप तय किया जा सकता है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को रद करने से इन्कार करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का काम 'मुकदमे का ड्रेस रिहर्सल' करना नहीं है, वह भी प्रारंभिक चरण में जहां निचली अदालत ने केवल आरोप तय किए हैं। इस स्तर पर शीर्ष अदालत में सुनवाई संभव नहीं है।

शीर्ष अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले पुनीत सभरवाल और आरसी सभरवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के 2006 के आदेश को रद करने से इन्कार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को पिछले 25 वर्षों से लंबित इस मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

विवाह में दिखावा रोकने को 'नागरिक कर्तव्य संहिता' पर जोर

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▸ विहिप के प्रांतीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक में संत समाज ने की चर्चा

▸ पर्व-त्योहारों की तिथियां दो-दो दिन पड़ने व पूजन पद्धति भी अलग-अलग होने पर भी जताई चिंता

विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों पर दिखावा बढ़ गया है। कई विवाह आयोजनों में तेज संगीत के शोरगुल के साथ शराब व मांस परोसा जा रहे हैं। प्री वेडिंग और विवाह के दौरान फोटो शूट के नाम पर भी अभद्रता बढ़ रही है। दिल्ली में विहिप के प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अन्य धार्मिक आयोजनों और कर्मकांडों के दौरान भी इस तरह की असहज स्थिति पर संत समाज ने चिंता जताई है। साथ ही इस पर रोकथाम के लिए नागरिक कर्तव्य संहिता तैयार करने पर जोर दिया है।

विहिप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, पर्व-त्योहारों की तिथियों के दो-दो दिन पड़ने और पूजन पद्धति भी अलग-अलग होने पर चिंता व्यक्त की है। इसलिए पर्व, त्योहारों की तिथियों व पूजा-पद्धतियों में एकरूपता के लिए न्यूनतम मानक तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

रोहिणी स्थित इस्कान मंदिर में आयोजित इस बैठक में विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार व केंद्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती व विहिप दिल्ली के अध्यक्ष कपिल खन्ना समेत दिल्ली के 50 से अधिक प्रमुख संत शामिल रहे।

बैठक में शामिल एक पदाधिकारी के अनुसार, संत समाज संस्कारों में आ रही विकृति पर चिंतित था, इसलिए कर्तव्य संहिता पर जोर दिया गया, जिस पर आगे बढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि अगस्त में होने वाली मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इसे लेकर काफी कुछ तय हो जाएगा। बैठक में सीएए का विरोध करने वाले नेताओं द्वारा शरणार्थी सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध के साथ ही ईसाई और पारसियों को चोर, अपराधी बताए जाने पर चिंता व्यक्त की गई तथा लोकसभा चुनाव में ऐसे दल को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रवादी और सनातन संस्कृति की चिंता करने वालों को सहयोग देने की बात भी हुई।

शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता दिलाएगी विहिप : परांडे

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए विहिप जल्द पूरे देश में अभियान शुरू करेगा। साथ ही, मतांतरण के खिलाफ सभी राज्यों में कड़े कानून की मांग भी की जाएगी।

मिलिंद परांडे

विहिप के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना उत्तराखंड सरकार की बड़ी राजनीतिक पहल है। उन्होंने सीएए लागू किए जाने पर केंद्र और समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड सरकार का आभार भी जताया। मंगलवार को हरिद्वार में पत्रकारों से मिलिंद परांडे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की बड़ी राजनीतिक पहल की है। मतांतरण पर भी रोक लगे, इसके लिए समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में विहिप लगातार प्रयास कर रही है।

भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं, सीएए देशहित में : जाफर

राज्य ब्यूरो, भोपाल : देशहित में हुए भाजपा के सभी निर्णयों का मैंने हमेशा स्वागत और समर्थन किया है। मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकहित के निर्णयों की सराहना की है। जब लव जिहाद पर कानून बना था, उस समय कांग्रेस प्रवक्ता रहते हुए मैंने इस कानून स्वागत किया था। मैंने कभी भाजपा को मुस्लिम विरोधी नहीं कहा। यह बात कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले मप्र के पूर्व सीएम कमल नाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर ने कही। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित रहा हूं। जाफर ने कहा कि सीएए देशहित में है। सीएए के मामले में मुस्लिम लीग और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे नेता भ्रम फैला रहे हैं। इस कानून से भारतीय मुस्लिमों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मुस्लिम मुल्कों में प्रताड़ित मुस्लिमों के मामले में मुस्लिम लीग को इस्लामिक सहयोग संगठन से न्याय की मांग करना चाहिए।

ओटीटी व इंटरनेट मीडिया पर अपशब्दों का नियमन नहीं हो सकता : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म पर अपशब्दों और गालियों का अश्लीलता के आधार पर अपराधीकरण करके उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में वेबसीरीज कंपनी टीवीएफ और अन्य के खिलाफ दायर एफआइआर को खारिज कर दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के छह मार्च, 2023 के फैसले को खारिज किया जिसमें एक मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को कायम रखा गया था। इस आदेश में दिल्ली पुलिस को वेबसीरीज 'कालेज रोमांस' के खिलाफ निर्माता कंपनी टीवीएफ के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा गया था। इसके अलावा, आइटी कानून के तहत शो की निर्देशक सिमरनप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्व अरोड़ा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसीरीज की भाषा का अर्थ शब्दशः निकाला है। इसलिए बिना संदर्भ के इस मामले को गलत समझ लिया गया है।

बेंगलुरु में दुकानदार से मारपीट के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन

▸ शोभा करंदलाजे व सुरेश कुमार समेत कई नेता हिरासत में

▸ मारपीट के अब तक कुल पांच आरोपित किए गए गिरफ्तार

बेंगलुरु, प्रेट्र : हनुमान चालीसा सुनने पर एक दुकानदार की पिटाई के बाद बेंगलुरु के नगरतपेट में भाजपा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जबर्दस्त हंगामे के बीच कर्नाटक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और भाजपा विधायक सुरेश कुमार समेत कई लोगों को ऐहतियातन हिरासत में लिया गया। घटना के दूसरे दिन दो और आरोपितो को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक एक और आरोपित की तलाश जारी है। इस घटना से जुड़े कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की अक्षम कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए स्थानीय भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हर कोई यही सोच रहा है कि जब भी राज्य में पुरातन दल कांग्रेस की वापसी होती है, समाज में अशांति लाने वाले अराजक तत्वों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद सूर्या ने प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा कि दुकान में बैठे मुकेश, रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट और कर्नाटक विधान सौधा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद आप बेंगलुरु के लोगों को कैसे सुरक्षित रखोगे। भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने प्रदर्शन के दौरान एक विवादित बयान देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से लोग आकर कर्नाटक में बम लगा जाते हैं, जो यहां की कांग्रेस सरकार की नाकामी है। उनके इस बयान का तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कड़ा विरोध किया है।

बेंगलुरु में अजान के नाम पर एक हिंदू दुकानदार की पिटाई पर लोगो में गहरा आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में मंगलवार को यहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रेट्र

आइएफएस संजीव के मामले में केंद्र के अधिवक्ता ने बहस से किया इन्कार

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ पीठ ने जताई नाराजगी, कहा-सुनवाई में पेश नहीं हुए तो एकतरफा निर्णय

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) में वरिष्ठ आइएफएस अधिकारी व मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) उत्तराखंड संजीव चतुर्वेदी की मूल्यांकन रिपोर्ट के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई पर केंद्र के वकील हनु भास्कर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग माध्यम से पेश होने के बावजूद बहस करने से मना कर दिया। कैट की प्रधान पीठ ने इस पर नाराजगी जताई। कहा कि तय की गई अगली तिथि पर यदि प्रतिवादी (केंद्र) के वकील उपस्थित नहीं हुए तो गुण-दोष के आधार पर एकपक्षीय निर्णय कर दिया जाएगा।

पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत सरकार के दूसरे अधिवक्ता टीसी अग्रवाल से भी उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। न ही वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास मामले को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी है।

सभी चयन मानदंडों को पूरा करने के बाद आइएफएस संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन किया था। एपीएआर की जांच के बाद उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इस पद के लिए विचार के लिए पात्र पाया गया जबकि 15 नवंबर, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तराखंड सरकार को उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। नियमानुसार आवेदक को अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पैनल की अस्वीकृति के संबंध में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए चतुर्वेदी दिसंबर 2022 में कैट पहुंचे। मामला पिछले दो वर्षों से कैट के पास लंबित है, इसलिए प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे ने 18 मार्च, 2024 को चतुर्वेदी के मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति राजीव जोशी और प्रशासनिक सदस्य एएस खाती की विशेष पीठ का गठन किया।

कोर्ट ने कहा, आदेश में है नोटिस जारी करने का कारण

प्रथम पृष्ठ से आगे

जब रोहतगी ने कहा कि रामदेव पतंजलि आयुर्वेद में किसी पद पर नहीं हैं और कोई नया विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है, उन्हें नोटिस जारी करने का कोई कारण तो होना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि इसका कारण आदेश में दिया गया है।

इस मामले में आइएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति व कोविड टीकाकरण के विरुद्ध अभियान चलाने और कुछ बीमारियों के इलाज का दावा करने के भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप लगाया है। याचिका में मांग की गई है कि सेंटर एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस काउंसिल (एएससीआइ) और सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथारिटी (सीसीपीए) को इन भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों पर केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई थी।

हिमाचल की राजनीति

भाजपा के हाथ में है अयोग्य घोषित विधायकों का भविष्य

पार्टी में शामिल कर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने पर होना है निर्णय, जयराम ने कहा– हमें अयोग्य विधायकों के स्वाभिमान का पूरा ध्यान

जागरण संवाददाता, शिमला

हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के छह विधायकों के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ही भाजपा निर्णय लेगी। यह संकेत विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ने मंगलवार को शिमला में दिए हैं। इन छह विधायकों पर निर्णय अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। इनमें से कितने नेताओं को भाजपा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाती है या फिर लोकसभा चुनाव में उतारती है, इस पर सब की नजर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कह कर कुछ संकेत दिए हैं कि इन लोगों ने काफी अपमान सहने के बाद राज्यसभा चुनाव में भाजपा का खुला साथ दिया है। ये नेता कांग्रेस में सुरक्षित नहीं समझ रहे थे तो पार्टी एजेंट को दिखाकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन पर चर्चा कर रहा है। जयराम का यह कहना भी भविष्य का संकेत दे रहा है कि भाजपा एक परिवार है, जब परिवार में कुछ लोग आ जाते हैं तो नाराजगी परिवार के भीतर बैठकर ही सुलझा ली जाती है। इन्हें पार्टी में कब शामिल करना है, क्या इनकी भूमिका होगी, इन सभी मामलों पर चर्चा की जा रही है। भाजपा हाईकमान इनके स्वाभिमान से लेकर हर चीज का ध्यान रखते हुए निर्णय लेगा।

हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद हुआ राजनीतिक घटनाक्रम देशभर में चर्चा में रहा। अयोग्य घोषित विधायकों को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामला विचाराधीन है। ऐसे में क्या ये उपचुनाव में उतरेंगे या इनकी भूमिका पार्टी में कुछ और रहेगी, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को छह विधायकों पर निर्णय हो सकता है।

अल्पमत में सरकार, बिना बजट 1500 रुपये देने की घोषणा : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार अल्पमत में है। इस बात का आभास मुख्यमंत्री को हो गया है। सरकार ने आनन-फानन महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा बिना बजट की है। इस सरकार का जाना तय है। इसी डर से मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक नियुक्तियां की हैं।

मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में विधायक नाराज हैं, इसका परिणाम राज्यसभा चुनाव में सभी को देखने को मिला। छह कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के समर्थन में वोट किया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए। जागरण

राजनीतिक हालात देखकर कांग्रेस-भाजपा विधायकों को टिकट नहीं देंगी

लोकसभा की शेष दो सीटों और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा हाईकमान शीघ्र करेगा। वहीं, मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करता है और जो प्रदेश में राजनीतिक हालात बने हैं, उसको देखकर कांग्रेस और भाजपा विधायकों को टिकट नहीं देंगी। लोकसभा की चारों और विधानसभा उपचुनाव की छह सीटें भाजपा जीतेगी।

****

लोकपाल ने महुआ के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश दिए

▸ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप

▸ लोकपाल ने छह माह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने मंगलवार को सीबीआइ को तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फार-क्वेरी (पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने) के आरोपों की जांच करने और छह महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही जांच एजेंसी से कहा है कि वह हर महीने की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी दे। मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में इस अनैतिक आचरण के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, उन्हें पार्टी ने बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से दोबारा अपना उम्मीदवार भी बनाया है।

भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोइत्रा ने दुबई में बैठे व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के लेकर लोकसभा में सवाल पूछे थे। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने आदेश में कहा है कि पूरे मामले का रिकार्ड देखने और मूल्यांकन के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनप्रतिनिधि पर जो आरोप लगाए हैं, वह गंभीर प्रकृति के हैं।

लोकपाल ने महुआ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने और हर महीने की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पद हो, एक लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी बरतने के लिए बाध्य है।

508 किलोमीटर लंबा है मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का मार्ग। इस योजना के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद

विवाहिता की मौत के बाद सास और ससुर को जिंदा जलाया

प्रयागराज में बड़ी घटना ▶ चाची के साथ युवती ने बालकनी से कूदकर बचाई जान

एक पक्ष से हत्या, दूसरी तरफ से दहेज हत्या का केस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रयागराज के सत्तीचौरा तिराहे स्थित घर में लगी आग से बचकर निकली शिवानी बार-बार यही बोल रही थी मम्मी-पापा घर में है, बाहर निकालो। मंगलवार को रोती शिवानी को संभालते स्वजन। मुकेश कनौजिया

रेस्क्यू आपरेशन चलाकर मकान में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। आगजनी में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
– दीपक भूकर, डीसीपी सिटी, प्रयागराज

उप्र के प्रयागराज जिले में सोमवार रात विवाहिता अंशिका केसरवानी (21) की मौत के बाद उसकी सास शोभा देवी (62) व ससुर राजेंद्र केसरवानी (65) को जिंदा जला दिया गया। घर में लगी आग की लपटों के बीच में फंसी राजेंद्र की बेटी शिवानी ने अपनी चाची के साथ बालकनी से कूदकर जान बचाई। पुलिस ने शिवानी की तहरीर पर अंशिका के माता-पिता समेत 12 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ हत्या, बलवा, आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं, अंशिका के पिता सरदारी लाल की शिकायत पर राजेंद्र, उनकी पत्नी, बेटियों व दामाद के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आगजनी में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना को लेकर मंगलवार को भी कोहराम मचा रहा। बवाल की आशंका पर घटनास्थल व पोस्टमार्टम हाउस पर फोर्स तैनात रही।

सत्तीचौरा मालवीय नगर निवासी फर्नीचर कारोबारी अंशू केसरवानी की शादी 13 फरवरी, 2023 को टेंट व्यवसायी सरदारी लाल की बेटी अंशिका के साथ हुई थी। मंगलवार रात अंशिका की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। सूचना पाकर मायके से पिता, मां और भाई सहित करीब 70 लोग सत्तीचौरा पहुंच गए। मुट्ठीगंज पुलिस दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और घर के बाहर ले आई। इसी बीच मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया और फिर झगड़ा हो गया। ससुराल पक्ष का आरोप है कि मायके वालों ने हमला किया और मकान में तेल डालकर आग लगा दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू आपरेशन के साथ ही आग बुझाने में जुट गई। रात करीब तीन बजे आग पर काबू पाया। इसके बाद सर्च आपरेशन शुरू किया तो मकान के तीसरे मंजिल पर राजेंद्र और उनकी पत्नी की जली हुई लाश मिली।

गढ़चिरौली में 36 लाख के चार इनामी समेत छह नक्सली ढेर

नईदुनिया, बीजापुर : महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जवानों ने एक मुठभेड़ में 36 लाख रुपये के इनामी चार नक्सलियों को मार गिराया। यह सभी तेलंगाना राज्य समिति के सदस्य थे। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। वहीं, दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले की सीमा पर भी दो नक्सली ढेर कर दिए गए। ये नक्सली गढ़चिरौली में प्राणहिता नदी पार करके वारदात को अंजाम देने छत्तीसगढ़ में आए थे।
पुलिस अधीक्षक (नक्सल आपरेशन) यतीश देखमुख के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स सी-60 और सीआरपीएफ की टीम नक्सलियों की तलाश में निकली। मंगलवार की सुबह कोलामरका पहाड़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें वर्गीश, मैगटू, कुरसांग राजू, कुडीमेट्टा वेंकटेश मारे गए। तीनों केपास से एके 47, कार्बाइन और दो देसी पिस्तौल तथा नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। वहीं, दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले की सीमा पर पुरंगेल-गमपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में महिला व पुरुष नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने पुष्टि करते हुए बताया कि गमपुर के पास जंगल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। अभी दोनों की पहचान नहीं हो पाई है।

देश की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी : अश्विनी वैष्णव

▶ केंद्रीय मंत्री बोले- विभिन्न स्टेशनों के निर्माण में हुई खासी प्रगति

▶ कहा, पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी दिसंबर में तैयार होगा

अश्विनी वैष्णव। फाइल फोटो

नई दिल्ली, आइएएनएस : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2026 में चलने लगेगी। यह हाईस्पीड ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई मार्ग पर सूरत से एक खंड पर चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक भारत में पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को तैयार कर लिया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, पीएम नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बुलेट ट्रेन के लिए तैयार रहें। विभिन्न स्टेशनों के निर्माण में खासी प्रगति हुई है। मुंबई से ठाणे के लिए समुद्र के अंदर सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इससे पहले रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन का वीडियो साझा करते हुए कहा था कि दो शहरों के बीच 508 किमी लंबे मार्ग की दूरी सिर्फ दो घंटे में तय होगी। इस योजना के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इस कारिडोर के लिए भारत में पहली बार स्लैब ट्रैक प्रणाली तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन इस रूट पर कुल 24 नदी पुलों, 28 स्टील ब्रिज और सात पर्वतीय सुरंगों को पार करेगी। इस कारिडोर में सात किमी लंबी समुद्र के अंदर टनल भी होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस साल के अंत तक दिसंबर महीने में देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप को लांच कर दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा, इसे बनाने का प्रयास 1962 में किया गया था पर जब तक नीति सही नहीं होती है, सफलता नहीं मिलती है। सही प्रतिबद्धता से इसे साकार किया जा सकता है। कहा, इस मुद्दे पर पीएम ने विशेष रुचि ली है। जब इस विषय पर चर्चा के लिए उनसे 45 मिनट का समय मांगा गया, तो उन्होंने तीन घंटे तक चर्चा की। विगत एक मार्च को उन्होंने घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में ग्लोबल हब बनेगा।

सोमालिया का जहाज डूबने के मामले में हाई कोर्ट पहुंची सीबीआइ

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : सीबीआइ ने ब्लैकरोज जहाज डूबने की घटना की सीबीआइ जांच की मांग से संबंधित मामले में हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सीबीआइ ने कहा है कि राज्य सरकार से दो बार आग्रह करने के बावजूद जांच की अनुमति नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। बताते चलें कि नौ सितंबर, 2009 को सोमालिया का जहाज ब्लैकरोज पारादीप तट से पांच किलोमीटर दूर डूब गया था। जहाज में 23,500 मीट्रिक टन लौह अयस्क लदा था। इस हादसे में जहाज के एक इंजीनियर की भी मौत हो गई थी। जहाज के लंबे समय तक डूबे रहने से समुद्र में तेल का रिसाव होने लगा था। इसके बावजूद जहाज को किनारे पर लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

सीबीआइ ने कहा है कि ब्लैक रोज सोमालिया का जहाज था, जो भारतीय समुद्र में डूब गया था। ऐसे में 2018 में पोत परिवहन मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाज के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए मामले की सीबीआइ जांच कराने का फैसला किया था। इस संदर्भ में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हाई कोर्ट को बताया कि नवंबर 2019 में राज्य सरकार को पत्र लिखा पर जवाब नहीं मिला।

शौर्य चक्र विजेता की हत्या में नामजद आतंकी की जमीन अटैच

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मंगलवार को गुरदासपुर में आतंकी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा की जमीन को अटैच कर दिया। गुरविंदर को तरनतारन के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या के मामले में नामजद किया गया था। वह गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह हैरी चट्ठा उर्फ सुख भिखारीवाल का सहयोगी है। उसने शूटरों को हथियार मुहैया कराकर संधू की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी।

आतंकी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा। फाइलफोटो

जानकारी के अनुसार, एनआइए ने मोहाली की विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश पर यूएपीए की धारा 33 के तहत गांव पीरांबाग में गुरविंदर की जमीन अटैच की है। ज्ञात रहे कि अक्टूबर 2020 में तरनतारन के शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह की गांव भिखीविंड में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

डोभाल जैसे लोगों पर होना चाहिए शोध : कोविन्द

जागरण संवाददाता, बठिंडा

▶ पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समागम में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति और एनएसए

बठिंडा स्थित पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित दीक्षा समारोह में एनएसए अजीत डोभाल को डी लिट की मानद उपाधि दी गई। इस मौके पर मौजूद (बाएं से दाएं) चांसलर जगबीर सिंह, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, अजीत सिंह डोभाल व कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी। सौ. यूनिवर्सिटी

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि एक आइपीएस अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के पद तक पहुंचना आसान काम नहीं है। अतः यह जरूरी है कि देश के एनएसए अजीत डोभाल पर शोध हो। मैं डोभाल से कभी-कभी मजाक में कह देता हूं कि मैं आपसे बचकर रहता हूं।

यह बातें उन्होंने मंगलवार को पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विज्ञानी विजय भटकर, गायक जसपिंदर नरूला और समाज सेवी हरजीत सिंह सभ्रवाल को विश्वविद्यालय की ओर से डी लिट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मैं तो कहूंगा कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को इन चारों शख्सियतों पर शोध करना चाहिए। उनको बुलाकर उनकी सक्सेस स्टोरी जाननी चाहिए जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जिंदगी के बारे में उन्हें पढ़ना, सुनना चाहिए। वह देश के एक कोने रामेश्वरम से थे। हर रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अखबार वितरित करके आते थे। उन्होंने कहा कि पहले बेटियां पीछे होती थीं, लेकिन आज हर क्षेत्र में बेटियां सबसे आगे हैं। भले ही रक्षा का क्षेत्र हो या स्पेस का या कोई और। यह नए भारत की तस्वीर है।

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। अब जब भारत का राष्ट्रपति किसी देश में जाता है तो उसका उक्त देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्वागत करता है। यही नहीं, उनकी यही कोशिश होती है कि उन्हें कुछ समय राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठने का मौका मिल जाए।

जेल में बंद अमृतपाल पर पंजाब सरकार ने फिर से लगाया एनएसए

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अलगाववादी अमृतपाल सिंह सहित उनके सभी दस साथियों पर नए सिरे से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगा दिया है। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दी गई।

मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब अमृतपाल सहित उनके सभी दस साथियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पिछले वर्ष 18 मार्च को उनके खिलाफ एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। एनएसए के आदेश एक साल तक ही लागू हो सकते हैं।
इस पर पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि इन सभी के खिलाफ नए सिरे से एनएसए लगाया गया है। सरकार ने अगली सुनवाई पर आदेश की जानकारी देने के लिए समय की मांग की। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी। देश विरोधी गतिविधियों में गैंग बनाकर काम करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में मस्जिद कमेटी की याचिका निपटाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट में मामला उठाने की छूट दी

हाई कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले में सारी 15 याचिकाएं एक साथ संलग्न कर सुनवाई करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में लंबित आदेश वापस लेने वाली अर्जी पुनर्जीवित करने की छूट दे दी। साथ ही मस्जिद कमेटी की हाई कोर्ट के गत 11 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका निपटा दी।

जस्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को कहा, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर रखी है। जरूरत पड़ने वह अर्जी को पुनर्जीवित कर सकता है। इसके साथ कमेटी आफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की विशेष अनुमति याचिका निपटा दी। मस्जिद कमेटी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके आदेश को वापस लेने की अर्जी हाई कोर्ट में लंबित है। साथ ही अनुरोध किया कि पीठ उस लंबित याचिका को एक निश्चित तिथि पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इन्कार कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू वादी की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह मामले में लंबित सभी मुकदमों को संलग्न कर साथ सुनवाई करने की मांग स्वीकार कर ली। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिकाल अर्जी यानी आदेश वापस लेने की मांग अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

डीआरआइ ने दो विदेशी महिलाओं से 100 करोड़ की कोकेन जब्त की

▶ थाइलैंड-इंडोनेशिया की महिलाओं को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

▶ अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की मुंबई जोनल इकाई ने विदेश से आई दो विदेशी महिला यात्रियों के कब्जे से 100 करोड़ रुपये मूल्य की 9.8 किग्रा कोकेन जब्त कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। डीआरआइ ने महिला यात्रियों से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक नाइजीरियाई नागरिक और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया।

डीआरआइ ने बताया कि इथयोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एक थाइलैंड और एक इंडोनेशियाई महिला को रोका। तलाशी में दोनों के पास से 100 करोड़ रुपये मूल्य की तकरीबन 9.829 किग्रा कोकेन बरामद की गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि ड्रग्स को दिल्ली और आसपास के इलाकों से संचालित एक सिंडिकेट तक पहुंचाया जाना था। अधिकारी ने बताया कि डीआरआइ की एक टीम निगरानी के लिए मुंबई में तैनात की गई और एक अन्य टीम को सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए दिल्ली भेजा गया। डीआरआइ अधिकारियों ने आरोपितों को पकड़ने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मदद से ग्रेटर नोएडा में जाल बिछाया और मास्टरमाइंड की पहचान कर ली। हालांकि खतरे को भांपते ही आरोपित हिंसक हो गया और अधिकारियों को धक्का देकर भाग निकला। डीआरआइ टीम ने पीछा कर नाइजीरियाई नागरिक और उसके सहयोगी को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि ड्रग सिंडिकेट का जाल इथियोपिया, श्रीलंका और नाइजीरिया में फैला था।

इधर, डीआरआइ और मुंबई सीमा शुल्क के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सीबीआइसी की एक उच्च-स्तरीय ड्रग डिस्ट्रक्शन कमेटी ने मंगलवार को 265 करोड़ रुपये मूल्य के 31.948 किलोग्राम नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) को नष्ट कर दिया।

कोर्ट ने हत्या के नौ साल बाद आरोपित को किया बरी, दिया संदेह का लाभ

ठाणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र की ठाणे जिले की एक कोर्ट ने मजदूर की हत्या के मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह घटना 2014 में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने 11 मार्च को दिए गए फैसले में कहा कि जांच अधिकारी मामले की ठीक से जांच करने में विफल रहे। इस फैसले की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने कोर्ट को बताया कि राजेश बोधि साव नामक श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि साव ने दोनों आरोपितों में से एक की भतीजी से बदसलूकी की थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर श्रमिक शिविर में उसकी हत्या कर दी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपित हडसे की मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया। अदालत ने मितकर को बरी करते हुए कहा कि घटना दिनदहाड़े हुई, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है।

बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ से बिगड़े हालात, मुंबई के श्रद्धालु की मृत्यु

जागरण संवाददाता, वृंदावन

▶ मुंबई से आए 40 सदस्यीय दल में शामिल श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी ,भीड़ में फंसकर दम घुटने से एक श्रद्धालु बेहोश

सुनील मगो का फाइल फोटो। सौजन्य : स्वजन

रंगभरनी एकादशी से एक दिन पहले मथुरा स्थित ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। इनके आगे मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। भीड़ में फंसकर मुंबई के बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई। मंदिर में उनका दम घुटने लगा, वह किसी तरह बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गए। उनके साथी उपचार की गुहार लगाते रहे, पर तुरंत चिकित्सकीय मदद नहीं मिली। इस बीच बुजुर्ग बेहोश हो गए। साथी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पहले वर्ष 2022 में जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान भीड़ के दबाव में दो श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी।

बुधवार को रंगभरनी एकादशी पर ठाकुर बांकेबिहारी श्रद्धालुओं संग होली खेलेंगे। इसे लेकर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे, इससे स्थिति बिगड़ गई। सुबह करीब 11 बजे मुंबई के श्रद्धालुओं का दल पहुंचा। दल में शामिल मुंबई निवासी सेवानिवृत्त बैंककर्मी सुनील किशोरीलाल मगो की भीड़ के दबाव में तबीयत बिगड़ने लगी। उनका दम घुटने लगा, तो जैसे-तैसे वह गेट नंबर एक से बाहर निकले। बाहर निकलते ही जमीन पर बैठ गए। उनके साथ आए लोगों ने बताया कि वह तुरंत बेहोश हो गए। यहां तैनात पुलिसकर्मियों से चिकित्सकीय मदद मांगी गई, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं थी। पुलिस ने एंबुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील के साथ आईं प्रमिला कनौजिया ने बताया, गेट संख्या दो से मंदिर में प्रवेश किया, तो भीड़ के बीच अचानक सुनील की तबीयत बिगड़ने लगी। मृतक के पुत्र जयदीप मगो को पुलिस ने सूचित किया है।

दूसरी, घटना दोपहर करीब 12.45 बजे हुई। राजभोग के बाद दर्शन खुले तो एक साथ भक्तों की भीड़ मंदिर के अंदर घुसी। इसमें दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर भक्त 22 वर्षीय विशाल का दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गए। उनके साथ आईं तमन्ना ने बताया, भीड़ के बीच ऐसे फंसे कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी दौरान विशाल बेहोश हो गए। सुरक्षा गार्ड की मदद से मंदिर से बाहर निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल ले गए। यहां उन्हें भर्ती किया गया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालु की हृदयाघात से मृत्यु हुई है। वह मुंबई से अन्य श्रद्धालुओं के साथ आए थे। तबीयत खराब होते ही तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जोमैटो ने शाकाहारी ग्राहकों के लिए लांच किया 'प्योर वेज फ्लीट'

नई दिल्ली, प्रेट्र : आनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए 'प्योर वेज मोड' सेवा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। जोमैटो ने भारत में अपने शाकाहारी ग्राहकों के लिए "प्योर वेज फ्लीट" भी लांच किया है। इसके जरिये ग्राहकों को शत प्रतिशत शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

एक्स पर पोस्ट की श्रृंखला में गोयल ने कहा कि भारत में विश्व स्तर पर शाकाहारियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये नई सुविधाएं उनके फीडबैक के आधार पर लांच की गई हैं। 'प्योर वेज मोड' में केवल शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां को शामिल किया जाएगा। "प्योर वेज फ्लीट" के लिए लाल डिलीवरी बाक्स के बजाय हरे डिलीवरी बाक्स का उपयोग किया जाएगा। "प्योर वेज फ्लीट" के जरिये केवल शाकाहारी रेस्तरां के आर्डर को पूरा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मांसाहारी भोजन, यहां तक कि मांसाहारी रेस्तरां द्वारा परोसा गया शाकाहारी भोजन प्योर वेज के लिए बने हरे डिलीवरी बाक्स के अंदर नहीं रखा जाएगा।

जागरण विशेष
नवाचारी अधिकारी

बढ़ाया हाथ तो महिलाओं को मिला रोजगार का आकाश

बिहार के मुजफ्फरपुर में जीविका की जिला कार्यक्रम प्रबंधक के प्रयास से छह लाख से अधिक दीदियां बनी स्वावलंबी

प्रेम शंकर मिश्रा ● मुजफ्फरपुर

कम पढ़ी-लिखी होने के कारण घर के काम तक सिमटीं महिलाओं को बस दिशा व प्रोत्साहन की जरूरत थी। इसे देने का काम किया बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जीविका की जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) अनिशा गांगुली ने। आज उनके प्रयास से जिले में 52 हजार समूहों से जुड़कर छह लाख से अधिक जीविका दीदियां रोजगार कर रही हैं। इनमें वे दीदियों भी हैं जो रोजगार के नए क्षेत्र से जुड़ीं और कई उद्यमी बन गईं। इस महिला अधिकारी ने महिलाओं के रोजगार के लिए कई ऐसे काम किए, जो मिसाल बन गए हैं। इसी बेहतर कार्य के लिए अनिशा को वर्ष 2023 में राज्य सरकार की ओर से 'नायिका पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

90 हजार रुपये प्रतिमाह की मशरूम बेचने का है लक्ष्य

मशरूम क्लस्टर में उत्पादन को बनाई गई झोपड़ियां।

मशरूम क्लस्टर से दीदियों को जोड़ा जा रहा है। पिछले वर्ष नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। एक क्लस्टर में 30 झोपड़ियों में मशरूम उत्पादन हो रहा है। अनिशा कहती हैं, अनुमान था कि एक झोपड़ी से प्रत्येक दूसरे दिन 29 किलो मशरूम का उत्पादन होगा, लेकिन दीदियों की मेहनत से 53 किलो तक हो रहा है। खबड़ा से शुरू हुआ यह सफर जिले में 11 जगहों तक पहुंच रहा है। जय संतोषी समूह की मीना देवी कहती हैं, जब शुरुआत की तो 20 दिन बाद ही 9800 रुपये का मशरूम बिका। फरवरी में 39 हजार का बेच चुकी हूं। इसे 90 हजार रुपये प्रतिमाह ले जाने का लक्ष्य है।

उत्पादित मशरूम को पैकिंग के लिए तैयार करने में लगीं जीविका दीदियां ● सौजन्य जीविका

महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी बेहतर होगी। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
अनिशा गांगुली, डीपीएम, मुजफ्फरपुर

तीन वर्ष पूर्व जिले में डीपीएम का कार्यभार संभालने के बाद अनिशा ने पहले घर तक पहुंच महिलाओं में इच्छाशक्ति जगाई कि वह कुछ कर सकती हैं। इसके बाद घर के आसपास ही छोटे-छोटे काम की शुरुआत कराई। कुछ ही समय में दायरा बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना लेदर क्लस्टर से दीदियों को जोड़ने का काम किया। चार दिसंबर, 2022 को शुरू इस क्लस्टर से लगभग 800 दीदियां जुड़ी हैं। बैग निर्माण से जुड़े इस क्लस्टर की 42 यूनिटें काम कर रही हैं। यूनिट हेड दीदियां अब उद्यमी बन गई हैं। एक वर्ष में एक लाख से अधिक बैग का उत्पादन हुआ तो एक दीदी को मेहनत के हिसाब से 15 से 20 हजार प्रतिमाह पारिश्रमिक मिला।

घर-घर बैंकिंग सेवा: कभी घर का हिसाब रखने वाली दीदियों को प्रोत्साहित कर डीपीएम ने बैंकिंग सेवा से जोड़ा। जिले की प्रत्येक पंचायत में 'एक बैंक सखी' की उनकी परिकल्पना मूर्तरूप ले रही है। 373 पंचायतों में से 200 में घर-घर बैंक की सेवा बैंक सखी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। शेष पंचायतों में भी सेवा शुरू हो जाएगी।

ड्रोन दीदी की बढ़ेगी संख्या: जिले में करीब एक लाख दीदियों को बकरी पालन से जोड़ा गया है। बेहतर आमदनी के लिए इस माह से इन्हें मेशा बकरी पालक महिला उत्पादक कंपनी से जोड़ा जा रहा है। उन्नत किस्म की बकरियों के पालन के साथ बाजार की उपलब्धता से महिलाओं को घर में ही 20 से 25 हजार प्रतिमाह आमदनी का विकल्प मिलेगा। अनिशा कहती हैं, अब ड्रोन दीदियों को तैयार करना है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से तीन दीदियों से इसकी शुरुआत हुई है। इस वर्ष 500 तक पहुंचाना है।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आने से परेशान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : ऋण व क्रेडिट कार्ड के लिए बार-बार आने वाले फोन से आम लोग ही नहीं बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा भी परेशान हैं। उन्होंने मंगलवार को अदालत में एक मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता से ही इसे लेकर मदद मांगी। न्यायाधीश ने कहा-'मुझे पिछले कुछ दिनों से हर रोज विभिन्न बैंकों के नाम से सात-आठ फोन आ रहे हैं। मैं इसे लेकर काफी परेशान हूं। कृपया कुछ कीजिए। एक नंबर को ब्लाक करने पर दूसरे नंबर से फोन आ रहा है।' इस पर अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास भी ऐसे काल आते हैं। मैं इस पर ध्यान नहीं देने की कोशिश करता हूं। इस समस्या से आम और खास सभी लोग परेशान हैं।

दैनिक जागरण
परिवार सदस्यों को एकजुट रखने वाली कड़ी है

सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। यह इसलिए स्वागतयोग्य है, क्योंकि किसी भी कानून और उसके प्रविधानों पर फैसला उनकी संवैधानिकता की जांच-परख के बाद ही होना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तीन कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल पर रोक लगा दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले संगठनों एवं राजनीतिक दलों को यह माहौल बनाने में आसानी हुई कि कृषि कानून सही नहीं। इसी माहौल ने ऐसी परिस्थितियां बनाईं कि सरकार को न चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ ढेरों याचिकाएं दायर की गई थीं, वैसे ही नागरिकता कानून के विरुद्ध भी। इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या 237 है। इनमें से केवल एक उसके समर्थन में है, शेष सब विरोध में। विरोध में याचिकाएं दायर करने वालों में राजनीतिक दल और नेता तो हैं ही, हर छोटे-बड़े सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों का वह समूह भी है, जिसने जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में तब्दील कर दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में खड़े लोगों की दलील यह है कि आखिर इसे लोकसभा चुनावों के पहले क्यों लागू किया जा रहा है। क्या चुनाव के पहले किसी कानून को लागू करना निषेध है? प्रश्न यह भी है कि चार वर्ष पहले जब कहीं कोई चुनाव नहीं थे, तब विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आसमान सिर पर क्यों उठा लिया था? उन्होंने इस कानून के खिलाफ न केवल लोगों को गुमराह किया, बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाया। इस कानून के खिलाफ देश भर में केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए, बल्कि उस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को घेरकर और आवाजाही ठपकर महीनों तक धरना दिया गया। इसी धरने के कारण दिल्ली में भीषण दंगे हुए, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इस पर हैरानी नहीं कि शाहीन बाग धरने को खाद-पानी देने वाले ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वे यह जान रहे हैं कि इस बार लोग उनके इस झूठे दुष्प्रचार में नहीं फंसने वाले कि इस कानून के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस कानून के विरोधियों को यह समझ आए तो अच्छा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। उन्हें अपनी यह बेतुकी मांग भी छोड़नी चाहिए कि नागरिकता कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यकों और उनके हाथों प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यकों पर समान रूप से लागू हो। आखिर पीड़ित और आक्रांता के लिए एक जैसा कानून कैसे हो सकता है?

चुनाव प्रबंधन

भारत निर्वाचन आयोग की उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा के साथ ही सरकारी मशीनरी तैयारियों में जुट गई है। सही भी है, लोकतंत्र के सबसे बड़े इस उत्सव को संपन्न कराने में किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे और चुनाव निर्विघ्न हों, इसके लिए तैयारियों को प्रत्येक स्तर पर समय रहते परखना जरूरी है। यद्यपि, समूचा उत्तराखंड शांत है, लेकिन फिर भी पुख्ता चुनाव प्रबंधन जरूरी है। उत्तराखंड विषम भूगोल वाला राज्य है, ऐसे में चुनाव को लेकर व्यवस्थागत चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विशेषकर पर्वतीय जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चुनावी प्रबंध करना आसान नहीं रहता है। पहाड़ी जिलों के कई इलाकों में अभी भी बर्फ के कारण रास्ते बंद हैं, उम्मीद की जा रही है कि मतदान की तारीख तक बर्फ पिघल चुकी होगी। इससे चुनाव पार्टियों को यहां तक पहुंचाना अपेक्षाकृत सुगम हो जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी के साथ ही राजनीतिक दल भी महासमर के लिए कमर कस रहे हैं। इस सबके बीच इस बात का ध्यान रखना जरूरी है चुनाव अवधि में जनता से जुड़े रूटीन कामकाज निर्बाध चलते रहें। जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उनकी गति धीमी न पड़ने पाए। आमतौर पर देखने में आता है कि चुनावों के दौरान जो मशीनरी निर्वाचन संबंधी कार्यों से अलग रखी जाती है, वह उदासीन हो जाती है। इसके चलते रोजमर्रा के कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चूंकि आला अधिकारी चुनावी व्यवस्थाओं में जुटे होते हैं, इसलिए वह इस ओर कम ही ध्यान दे पाते हैं। मातहतों की जिम्मेदारी है कि वे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाएं। देखने में यह भी आता है कि चुनाव के दौरान अतिक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। अतिक्रमणकारियों को लगता है कि इस अवधि में रोक-टोक करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यह प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है।

गोपनीयता के आवरण में चुनावी चंदा

सुरेंद्र किशोर

समय के साथ देश में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन चुनावी चंदे में पारदर्शिता का अभाव जस का तस कायम है

अवधेश राजपूत

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सफलता चुनावी प्रक्रिया में स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से निर्धारित होती है। चूंकि चुनाव एक खर्चीली प्रक्रिया भी है तो इस कारण इसमें चुनावी चंदे की भूमिका अहम हो जाती है। इसी चंदे से जुड़े चुनावी बांड का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। भारत में देसी-विदेशी चुनावी चंदे को लेकर पर्दादारी की परपंरा दशकों पुरानी है। विदेशी चंदे के बारे में 1967 में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी, 'इस देश के राजनीतिक दलों को मिले विदेशी चंदे के बारे में भारत के केंद्रीय गुप्तचर विभाग की रपट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके प्रकाशन से अनेक व्यक्तियों और दलों के हितों की हानि होगी।' इससे पहले विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने उसके प्रकाशन की मांग की थी। इस प्रकार उस समय केंद्र में सत्तारूढ़ इंदिरा गांधी सरकार ने यह परंपरा स्थापित कर दी कि सियासी चंदे के मामले में देश को हानि भले हो जाए, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वह परंपरा कमोबेश आज भी देश में कायम है। ऐसे में इस पुरानी मांग पर एक बार फिर गौर करने की जरूरत है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के जरूरी खर्चे खुद सरकार उठाए। 1967 के आम चुनाव में सात राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। तब तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही होते थे। याद रहे कि 1967 में आम चुनाव के कुछ महीनों के भीतर दल-बदल के कारण दो अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकारें भी गिर गई थीं। उसके बाद वहां भी गैर-कांग्रेसी सरकारें गठित हो गई थीं। चौथे आम चुनाव में लोकसभा में भी कांग्रेस का बहुमत कम हो गया था। यानी, आज का यह तर्क सही नहीं है कि विविधताओं वाले इस देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग ही होने चाहिए। जब साथ चुनाव होने पर भी परिणाम अलग-अलग आते ही थे तो एक बार फिर एक ही साथ चुनाव कराने में नुकसान क्या है? असल में इसके लाभ अधिक हैं।

अतीत की ओर देखें तो 1967 की चुनावी हार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चिंतित हो उठी थीं। पहले से ही उन्हें यह अपुष्ट खबर मिल रही थी कि इस चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल हुआ है। तब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि विदेशी धन सिर्फ विपक्षी दलों को मिला। इंदिरा सरकार ने केंद्रीय गुप्तचर विभाग को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। जांच रपट सरकार को सौंप दी गई, लेकिन रपट को सरकार ने दबा दिया। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह रपट सत्तारूढ़ दल के लिए भी असहज करने वाली थी। जांच के दौरान इस बात के भी सुबूत मिले थे कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने अमेरिका से तो कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने सोवियत संघ से पैसे लिए थे। इस रपट को बाद में अमेरिकी अखबार 'द न्यूयार्क टाइम्स' ने छाप दिया था। इस रपट के अनुसार सिर्फ एक राजनीतिक दल को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों ने विदेशी चंदा स्वीकार किया था। गुप्तचर विभाग की उक्त रपट के अनुसार अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी और कम्युनिस्ट दूतावासों ने राजनीतिक दलों को काफी पैसे दिए। उन दिनों विश्व के दो खेमों के बीच शीत युद्ध जारी था। कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्ट देशों ने भारत में अपने-अपने खास समर्थक बना रखे थे। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि उस दौर में एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। न्यूयार्क टाइम्स की इस सनसनीखेज रपट पर 1967 के प्रारंभ में लोकसभा में बहुत तीखी बहस हुई। इसके परिणामस्वरूप तमाम भारतीय अखबारों में भी इस खबर को बाद में काफी कवरेज मिला। जो खबर न्यूयार्क टाइम्स ने ब्रेक की थी, वह खबर भारतीय मीडिया क्यों नहीं ब्रेक कर सका? क्या तब भी 'गोदी मीडिया' था? इस समय एक तबका गोदी मीडिया का आरोप भारतीय मीडिया को लेकर लगा रहा है। उन्हीं दिनों यह खबर भी आई थी कि इस देश के ही एक बड़े उद्योगपति ने तकरीबन पांच दर्जन सांसदों को अपने 'पे रोल' पर रखा हुआ था।

संसद में स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य ने गृहमंत्री चव्हाण से पूछा कि क्या वह गुप्तचर विभाग की रपट को प्रकाशित कराएंगे ताकि राजनीतिक दलों को जनता के बीच सफाई पेश करने का मौका मिल सके? रपट के प्रकाशन से इन्कार करते हुए चव्हाण ने यह जरूर कहा था कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग की मदद से संतानम समिति के उस सुझाव पर विचार कर रही है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को हरसंभव स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि की जांच की बात कही गई है। इस देश का दुर्भाग्य ही रहा कि जनता आज भी संतानम समिति की रपट को लागू करने की आस लगाए बैठी है।

समय के साथ राजनीति में काले धन के इस्तेमाल की खबरें बेहद आम होती गईं। कई मामलों में तो स्थिति यह हो गई है कि चुनाव में बाहुबल से अधिक प्रभावी भूमिका धनबल की होती जा रही है। कुछ समय पहले एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को दो हजार रुपये के नोट मतदाताओं के बीच बांटते हुए टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। अब तो इस देश के छोटे-छोटे दलों के नेता भी चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं। चुनाव में काले धन के बढ़ते असर से राजनीति की शुचिता प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप राजनीतिक कार्यपालिका भी दूषित हो रही है। प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में तो क्या ही कहा जाए। विशेषज्ञ बताते हैं कि एक स्तर पर भ्रष्टाचार विकास की गति को अपेक्षित रूप से बढ़ने नहीं दे रहा है। गुणात्मक एवं टिकाऊ ढांचा निर्माण की कोई गारंटी नहीं है। चुनावी चंदा भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है। इसी को देखते हुए चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भली मंशा वाली यह योजना राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में अपेक्षित परिणाम न देकर खुद विवादों के घेरे में घिर गई।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नागरिकता कानून पर बेतुकी आपत्ति

राजीव सचान

तीन पड़ोसी देशों के सभी लोगों को सीएए के दायरे में लाने की मांग कुतर्क के अलावा और कुछ नहीं

दुष्प्रचार की उपज है सीएए का विरोध। प्रेट्र

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर रोक लगाने से मना कर वकीलों के उस समूह को कुछ समय के लिए ही सही, अवश्य निराश किया होगा, जिन्होंने शीर्ष अदालत को एक तरह से तीसरे और सर्वोच्च सदन में बदल दिया है। इस कानून के खिलाफ करीब दो सौ से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एक याचिका उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी है, जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का छद्म रूप है। स्पष्ट है कि इतनी अधिक याचिकाओं के कारण नागरिकता कानून की संवैधानिकता पर लंबी सुनवाई चलेगी। सीएए पर आपत्तियों की कमी नहीं। एक आपत्ति यह है कि इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भारतीय नागरिक बन सकने की वैसी सुविधा नहीं दी गई, जैसी इन देशों के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को दी गई है। प्रश्न यह है कि क्या भारत का संविधान देश के बाहर के लोगों पर भी लागू होता है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि नागरिकता कानून का तो भारत के किसी नागरिक से लेना-देना ही नहीं। इसका संबंध तो केवल तीन पड़ोसी देशों के लोगों से है। सीएए पर बहस के बीच यह सवाल उठना ही चाहिए कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह तय करने का अधिकार नहीं कि वह किन देशों के लोगों को सरलता से नागरिकता दे और किन देशों के लोगों को अलग प्रक्रिया का पालन करके?

कहना कठिन है कि नागरिकता कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों के मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए अलग और वहां के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों के स्तर पर अलग नियमों को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन क्या यह विचित्र नहीं कि सीएए को लेकर तो यह जिद की जा रही है कि भारत के तीन पड़ोसी देशों के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को एकसमान अधिकार दिए जाएं, लेकिन बड़ी चतुराई से इसकी अनदेखी की जा रही है कि देश के नागरिकों पर लागू होने वाले कई कानून ऐसे हैं, जो उनमें खुला भेद करते हैं और तार्किक वर्गीकरण के संवैधानिक सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। ऐसा ही एक कानून है, शिक्षा अधिकार कानून। इस कानून के तहत बहुसंख्यकों के शिक्षा संस्थान अलग नियमों से संचालित हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों के अलग नियमों से। आखिर सबको शिक्षित करने के अभियान में सभी समुदायों के शिक्षा संस्थानों को एकसमान तरीके से सहयोग क्यों नहीं देना चाहिए? क्या कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उस तरह संचालित नहीं होता, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है? क्या सीएए को विभेदकारी बताने वाले यह कहने का साहस करेंगे कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों के संचालन के तौर-तरीके अलग-अलग नहीं होने चाहिए?

आम तौर पर जिन्हें नागरिकता कानून में खोट नजर आती है, उन्हें ही समान नागरिक संहिता का विचार डराता है या फिर यह कहें कि इस संहिता पर कोई पहल होते ही वे अपने समुदाय के लोगों को डराने में लग जाते हैं। आखिर देश के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के अधिकार एकसमान क्यों नहीं होने चाहिए? आखिर देश के सभी नागरिकों में भेद न करने वाली समान नागरिक संहिता के मामले में देश के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में भेद करने की जिद क्यों की जा रही है? कायदे से समान नागरिक संहिता का निर्माण आजादी के बाद तभी हो जाना चाहिए था, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था। यह बिल हिंदू समुदाय की कुरीतियों को दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन क्या कुरीतियां केवल हिंदू समाज में ही थीं? क्या जैसे सामाजिक सुधार की आवश्यकता हिंदू समुदाय को थी, वैसी ही अन्य समुदायों को नहीं थी? प्रश्न यह है कि क्या यह अब भी नहीं है? भारत के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में भेद करने वाला एक कानून वह भी है, जो सरकारों को हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण करने और उन पर टैक्स लगाने का अधिकार देता है। ऐसा कोई कानून अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। या तो ऐसा कोई कानून सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों को लेकर होना चाहिए या फिर मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि अन्य समुदाय यानी अल्पसंख्यक तो अपने धार्मिक स्थलों का नियमन और संचालन करने में सक्षम हैं, लेकिन हिंदू समुदाय अर्थात बहुसंख्यक समाज ऐसा करने में नाकारा है? आखिर तथाकथित सेक्युलर भारत के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में ऐसा खुला भेद करने वाला कोई कानून अस्तित्व में क्यों है? क्या इस कानून को तार्किक वर्गीकरण या उचित विभेद वाले कानून की वैसी ही संज्ञा दी जा सकती है, जैसी आरक्षण संबंधी कानूनों के मामले में दी जाती है?

नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में तीन पड़ोसी देशों के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में भेद न करने की मांग करने वाले भारत के विभाजन की परिस्थितियों की भी अनदेखी कर रहे हैं। आखिर जिन लोगों ने वोट के जरिये और साथ ही जोर-जबरदस्ती का सहारा लेकर भारत का विभाजन कराया, उनमें और उन लोगों में तार्किक-उचित विभेद क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिन पर पाकिस्तान जबरन थोपा गया? ये वे अभागे लोग हैं, जिनके बारे में यह कहना कठिन है कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब तक बचे रहेंगे। सवाल यह भी है कि क्या भारत कोई धर्मशाला है, जो हर किसी को अपने यहां आने और बस जाने की सहूलियत दे दे। वैसे धर्मशाला के भी अपने नियम होते हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनुशासन का महत्व

जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले सूत्रों में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन में नूतन ऊर्जा और आलोक प्रदान कर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ धुरी है। एक अनुशासित व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारी होने का गुण होता है। इससे नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। अनुशासन द्वारा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान होता है। यह एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो कहीं ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो हमारा जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, 'सारे अनुशासनों की जड़ व्यक्तिगत अनुशासन है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप अनुशासन और नियम पालन में बंध नहीं जाता, तब तक उसे दूसरे से वैसा कराने की आशा करना व्यर्थ है।'

अनुशासन हमारे जीवन में सभी व्यवहारों के स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। जब इन कारकों को एकीकृत किया जाता है, तो वे जीवन में घटनाओं के सामाजिक और व्यक्तिगत क्रम को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यह जवाबदेही और विश्वसनीयता की भावना उत्पन्न करता है और लोगों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुशासन के बिना जीवन उस नाव की तरह है, जिस नाव पर कोई नाविक नहीं होता और वह नाव लहरों की भंवर में फंसकर राह भटक जाती है। वर्तमान दौर में लोग इतने अधिक अनुशासनहीन होने लगे हैं कि उन्हें अनुशासन की दीक्षा देने की नौबत आ गई है। प्रकृति के अनुसार अनुशासन का अर्थ सीखने के लिए हर किसी के पास अलग-अलग समय और क्षमता है। इसलिए, कभी भी हार न मानें और हमेशा अनुशासन में रहने की कोशिश करें।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

'रेगिस्तान के जहाज' का संरक्षण

सुधीर कुमार

ऊंट खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के साथ-साथ एक मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं

संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को 'अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष' घोषित किया है। ऊंट जिस प्रजाति समूह का हिस्सा हैं, जिन्हें आमतौर पर कैमलिड्स के नाम से जाना जाता है। यह ऊंटों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उनके संरक्षण का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।

ऊंट खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के साथ-साथ दुनिया भर के समुदायों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं। ऊंट भूख के खिलाफ लड़ाई, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तीकरण और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देने में उनका योगदान अतुलनीय है। वास्तव में ऊंट एक बहुउद्देशीय जानवर है, जिसका उपयोग दूध, मांस, जैविक उर्वरक के उत्पादन में होता है। साथ ही विभिन्न त्योहारों एवं पर्यटन की दृष्टि से भी इनका व्यापक महत्व है। वहीं रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में सवारी करने और सामान ढोने के लिए परिवहन के सशक्त रूप में तथा विभिन्न कृषि कार्यों जैसे जोताई एवं पानी ढोने या निकालने में ऊंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंट ऐसी जलवायविक दशाओं में भी शान से जीते हैं, जहां अन्य जीवों का जीवनयापन संभव नहीं हो पाता है। ऊंट अपने कूबड़ में जमा वसा का उपयोग करके और उसे ऊर्जा में बदलकर लंबे समय तक बिना भोजन या पानी के जीवित रह सकता है। यही वजह है कि सीमित पानी और वनस्पति वाले क्षेत्रों में भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरी खासियत यह है कि ऊंट गर्म और ठंडे दोनों तरह के चरम वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ऊंट दुनिया के 90 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन (दो कूबड़ वाले ऊंट), ड्रोमेडरी (एक कूबड़ वाले ऊंट), लामा, अल्पाका, गुआनाको और विकुना ऊंट के विभिन्न प्रकार हैं। जंगली ऊंट-कैमलस फेरस-को 2008 में संकटग्रस्त प्रजातियों की 'लाल सूची' में शामिल किया गया था।

भारत में ऊंटों की तादाद लगातार कम हो रही है। भारत की लगभग 84 प्रतिशत ऊंट आबादी राजस्थान में रहती है। 19वीं पशुधन गणना (2012) की तुलना में 20वीं पशुधन गणना (2019) में ऊंट की कुल आबादी चार लाख से घटकर ढाई लाख रह गई है। केंद्रीय पशुपालन विभाग के अनुसार ऊंटों की आबादी में कमी होने का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के कारण ऊंट की उपयोगिता में कमी, परिवहन के आधुनिक साधनों और सड़क मार्ग के विकास से ऊंट की मांग में कमी, चरागाह भूमि में गिरावट तथा ऊंट पालन में आने वाली कमी है। राजस्थान सरकार ने ऊंट को अपना 'राज्य पशु' घोषित किया है और उनके संरक्षण के लिए ठोस कानून बनाए हैं। ऊंटों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए ठोस प्रयत्न की दरकार है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अवसान की ओर छद्म सेक्युलरिज्म

'सेक्युलरिज्म की भ्रामक अवधारणा' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रणय कुमार ने भारतीय संस्कृति से जुड़े 'धर्म' और 'सत्य' जैसे मानकों को लेकर की जाने वाली भ्रामक व्याख्या की भारतीय संदर्भों में जैसी विवेचना की है, वह सेक्युलरिज्म की ओट में भारतीय संस्कृति को दरकिनार करने वालों को आईना दिखाने वाली है। वस्तुतः, सेक्युलरिज्म 1975 के आपातकाल के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया ऐसा क्षेपक है, जिसे परिभाषित करने की जरूरत नहीं समझी गई। कालांतर में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बनने वाले छद्म सेक्युलरिज्म से भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं के प्रति उमड़ने वाली स्वाभाविक आस्था का जैसा ह्रास हुआ, वह राष्ट्रवादियों के लिए चिंता का विषय बन गया। यह अच्छी बात है कि वर्तमान में हमें कुछ शुभ संकेत देखने को मिले हैं। अपने प्रथम कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा लिए गए लोकहितैषी फैसलों से आम जनता में जो विश्वास पनपा, वह मोदी की गारंटी के रूप में आज तक कायम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रहितैषी मुद्दों को लेकर भाजपा के पक्ष में जैसा माहौल बना है, उससे लगने लगा है कि अब राष्ट्रहित के आगे छद्म सेक्युलरिज्म टिकने वाला नहीं है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

गलतियों से सबक लें राहुल गांधी

संपादकीय आलेख "राहुल गांधी की कमजोरी" में यह रेखांकित किया गया है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक सीखे और उसे दोहराने से बचे तो उसके लिए अच्छा है। राहुल गांधी अपनी गलतियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफा ही करते चले जा रहे हैं। उनके दिमाग में शक्ति का तात्पर्य और अर्थ की व्याख्या कुछ अलग ही है। बकौल राहुल उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, पर शक्ति का प्रयोग वे केवल सत्ता हासिल करने के लिए ही करना चाहते हैं। इससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा। राहुल अब अपनी वाक् शक्ति को लगाम दें। मोदी के लिए जैसे आपत्तिजनक और बेतुके बयान वह देते आए हैं, उससे बचें। यही उनकी और पार्टी की सेहत के लिए ठीक होगा, अन्यथा मोदी 400 के पार और कांग्रेस 40 के भी पार नहीं रह पाएगी। अभी भी 'चुनाव काले विपरीत बुद्धि' की जगह 'चुनाव काले अनुकूल बुद्धि' का प्रयोग करें नहीं तो पार्टी की खोती जा रही साख और जमीन खिसकने में संदेह नहीं है। यही वजह है कि उनकी पार्टी की आंतरिक कलह से नेताओं का पलायन जारी है और उनके गठबंधन के दल उनसे दूरी बना रहे हैं। वह दिन दूर नहीं कि घटक दल उनसे टाटा कर लें।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

हादसों का बड़ा कारण लापरवाही

देश में बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय हैं। सड़क हादसों में अमूमन वाहन में सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। सड़क हादसों में मरने वाले अपने स्वजन या रिश्तेदार होते हैं। परिवार में कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है। क्या सड़क हादसों से घबराकर वाहन चलाना छोड़ दिया जाए? यह सत्य नहीं है। वाहन को सावधानी पूर्वक चलाने और कम गति से चलाने की सलाह दी जाती है। वाहनों की अधिक गति से चलाने पर वाहन कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहन और यात्री की हालत क्या होती होगी। हिट एंड रन पर बनाया गया कानून भी अधर में लटका हुआ है। देश में 53 दुर्घटनाएं हर घंटे में होती हैं। इनमें 19 लोगों की मौत होती है। भारत में हर मिनट में होने वाली दुर्घटना में तीन लोगों की मौत होती है। दुर्घटनाओं में बाइक सवारों के हताहत होने का आंकड़ा चिंतित करने वाला है। 68 फीसद हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। यह सब लापरवाही का कारण है। दिल्ली-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही बंद नहीं होती है। हिट एंड रन कानून को तुरंत लागू करने और ऐसे ही और सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

1950 में हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत, किंतु इसका तेज विकास 1970 के बाद आरंभ हुआ। नवंबर 2022 में चैटजीपीटी नामक ओपन एआइ चैटबाट के अस्तित्व में आने के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक क्रांति आई है।

शिशिर शुक्ला
विभागाध्यक्ष,
भौतिकी विभाग,
स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय,
शाहजहांपुर (उप्र)

आजकल

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

पिछले दिनों भारत को पहली एआइ शिक्षिका मिली। केरल के तिरुअनंतपुरम के एक स्कूल में पेश की गई इस रोबोट शिक्षिका का नाम 'आइरिस' है। यह रोबोट शिक्षिका चैटजीपीटी जैसे एआइ प्रोग्रामों से लैस है। इसके पास गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता है। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग का यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है

तिरुअनंतपुरम के एक स्कूल में छात्रों से संवादरत 'आइरिस' नामक एआइ शिक्षिका। प्रेट्र

हाल में भारत को पहली एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) शिक्षिका मिली है। निश्चित रूप से तकनीकी के क्षेत्र में यह देश की अभूतपूर्व उपलब्धि है। केरल के तिरुअनंतपुरम के एक स्कूल में पेश की गई इस रोबोट शिक्षिका का नाम 'आइरिस' है। यह रोबोट शिक्षिका चैटजीपीटी जैसे एआइ प्रोग्रामों से लैस है और इसके पास गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता भी है। तीन भाषाओं में बात कर सकने वाली यह एआइ शिक्षिका साड़ी पहनकर स्कूल पहुंची और उसने बच्चों से हाथ भी मिलाया। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग का यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। यूं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में हुई थी, किंतु इसका तीव्रतर विकास 1970 के बाद आरंभ हुआ। हाल की बात की जाए तो नवंबर 2022 में चैटजीपीटी नामक ओपन एआइ चैटबाट के अस्तित्व में आने के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में निस्संदेह एक क्रांतिकारी प्रादुर्भाव हुआ है। चैटजीपीटी में उच्च स्तरीय एल्गोरिदम एवं प्रोग्रामिंग का प्रयोग करके प्रश्नों के उत्तर देने एवं मानव के उन सभी कार्यों को सहज एवं सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, जिनको पूर्ण करने के लिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी चैटजीपीटी को रोबोट के साथ संयुक्त करके कृत्रिम शिक्षिका को अस्तित्व में लाया गया है। यहां पर एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का प्रयोग कहां तक उचित है? कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के एक स्कूल ने भी एआइ चैटबाट को प्रिंसिपल हेड टीचर बनाया है एवं विद्यार्थियों को एआइ आधारित पर्सनल असिस्टेंट दिए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का समावेश आखिरकार किस सीमा तक उचित है? क्या किसी विद्यालय अथवा महाविद्यालय को पूर्णतया कृत्रिम मेधा से लैस रोबोट शिक्षकों के हवाले किया जा सकता है? ऐसा कदम उठाकर क्या विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतामुक्त हुआ जा सकता है? इन प्रश्नों पर अगर हम गहन वैचारिक मंथन करें तो हमें इनका उत्तर नकारात्मक ही प्राप्त होगा। कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह रोबोट शिक्षक महज एक उच्च कोटि की एल्गोरिदम एवं सूचनाओं की उच्च भंडारण क्षमता से युक्त मशीन है। यह प्रश्नों का उत्तर तो कदाचित दे सकती है, किंतु जब बात जिज्ञासाओं एवं रचनात्मकता की होगी तब निश्चित रूप से यह औंधे मुंह गिर पड़ेगी। वजह स्पष्ट है कि स्मृति क्षमता एवं तर्कशक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। एआइ युक्त रोबोट शिक्षक वास्तविक शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी विषय पर सोचने, समझने एवं तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता फिलहाल उनके पास नहीं है। किसी भी विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस पर अपनी विचारशक्ति एवं तर्क क्षमता का प्रयोग करना नितांत आवश्यक होता है।

आंकड़े यह कहते हैं कि एआइ तकनीक वर्ष 2030 तक 30 करोड़ नौकरियां खत्म कर देगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में की गई टिप्पणी भी यह कहती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी क्रांति है, जो हमारी उत्पादकता, वैश्विक आय एवं विकास को बढ़ाएगी, किंतु यही तकनीकी क्रांति कई नौकरियां लील सकती है एवं असमानता की खाई को और अधिक बढ़ा सकती है। आखिर इन सभी रिपोर्ट का क्या मतलब है? क्या भविष्य में शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे एवं उन्हें प्रतिस्थापित करने वाली निर्जीव मशीनें होंगी? संभवतः ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि मशीनी शिक्षकों को कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। उन्हें केवल अपने अंदर लगाई गई बैट्री की चार्जिंग की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। दूसरा बिंदु यह है कि मानव शिक्षकों द्वारा समय-समय पर अपनी विभिन्न मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। उनके पूर्ण न होने की दशा में विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, जबकि मशीनी शिक्षक कभी किसी तरह की कोई मांग प्रस्तुत नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात हो गई। कुछ अन्य अंतरों पर गौर करें तो मशीनी शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही विषय चाहे जितनी बार पढ़ा सकते हैं, जबकि मानव शिक्षक को एक ही बिंदु अथवा अध्याय की बार-बार पुनरावृत्ति करने के लिए कहने पर उन्हें मानसिक तनाव अथवा झुंझलाहट का अनुभव हो सकता है। इन तर्कों से तो यही प्रतीत होता है कि एआइ आधारित मशीनी शिक्षक वास्तविक बुद्धि पर आधारित मानव शिक्षकों से हर मामले में बेहतर साबित होंगे, किंतु यह केवल और केवल कोरी कल्पना है। सत्य यही है कि मानवता का स्थान मशीन ले सकती। हां, यदि किसी प्रकार से मशीनों में मानवता एवं भावनाओं का भी समावेश किया जा सके तब उस स्थिति में निस्संदेह हम सब खतरे के दायरे में आ जाएंगे, किंतु ऐसा कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि एआइ को शिक्षा के क्षेत्र में किस हद तक दखल देने की अनुमति दी जाए कि वह अपने सकारात्मक पहलुओं का उपयोग करते हुए शिक्षा को प्रगति के उच्चतम स्तर तक ले जाने में सफल हो सके?

तकनीक के सदैव से ही दो पहलू रहे हैं- सकारात्मक एवं नकारात्मक अथवा वरदान एवं अभिशाप। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें कृत्रिम मेधा के सकारात्मक पहलुओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षकों को मशीन से प्रतिस्थापित कर देना तो अनुचित है, क्योंकि यह कदम बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या को बढ़ाने का काम करेगा। इससे देश का विकास पूर्णतया बाधित हो जाएगा। बेहतर रूप में ऐसा किया जा सकता है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सहायता के लिए एआइ आधारित सहायक उपलब्ध करा दिए जाएं, किंतु यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि विद्यार्थियों को एआइ जैसी सुविधा की खुली छूट मिल जाने पर वे जरा सी समस्या के हल के लिए एआइ का ही मुंह ताकेंगे। स्वयं कोशिश करके हल ढूंढ़ने एवं रचनात्मक ढंग से कार्यों को अंजाम देने की प्रतिभा धीरे-धीरे उनसे दूर जाने लगेगी। एक दिन ऐसा होगा, जब वे किसी भी विषय पर अपना स्वतंत्र सोच एवं तर्क प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को स्वयं अच्छे एवं बुरे की पहचान करते हुए सकारात्मक एवं प्रगति की ओर ले जाने वाली दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उन्हें एआइ का प्रयोग केवल आवश्यकता की स्थिति में ही करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमता का सहारा केवल अपने ज्ञानवर्धन एवं विषय की अद्यतन जानकारी के लिए ही लेना चाहिए। अनुप्रयोगों एवं नवाचारों के माध्यम से शिक्षकों को हमेशा यह सिद्ध करते रहना चाहिए कि मशीनें चाहे कितनी ही उन्नत दशा में क्यों न पहुंच जाएं, वे एक जीते जागते शिक्षकों का मुकाबला कदापि नहीं कर सकतीं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक वरदान के रूप में देखते हुए हमें इसका उपयोग विषम परिस्थितियों एवं ऐसी स्थिति में करना चाहिए जहां पर मानव सामान्य रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए, हमने तीन वर्ष पहले कोविड जैसी महामारी को झेला है। इस महामारी ने प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। ऐसे संकटों के समय में शिक्षा को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए कृत्रिम मेधा का सहारा लिया जाना चाहिए। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षा के स्वरूप एवं स्तर में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि वह प्रयोग बुद्धिमत्ता से किया जाए।

नए दौर में एआइ

डा. शशांक द्विवेदी

एआइ तकनीक आज जीवन के हर आयाम को प्रभावित कर रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित अर्थ स्पीशीज प्रोजेक्ट (ईएसपी) के तहत किए जा रहे शोध के अनुसार विज्ञानी अब जानवरों के संचार को समझने के लिए एआइ तकनीक का विकास कर रहे हैं। इसके लिए वे मशीन लर्निंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं। वर्षों से मशीन लर्निंग का उपयोग मानव भाषाओं का विश्लेषण करने या प्राचीन संचार को समझने के लिए किया जाता रहा है। इस अध्ययन से पशुओं के संचार को समझने में मदद मिलेगी। इससे दूसरी प्रजातियों के साथ दो तरफा संचार की संभावना भी बढ़ेगी। इस दिशा में साल 2018 में भी जर्मनी के विज्ञानियों ने एक रोबो-बी यानी कृत्रिम मधुमक्खी बनाया था। प्रयोग के तहत उस कृत्रिम मधुमक्खी को असली मधुमक्खियों के बीच छोड़ा गया था। वह असली मधुमक्खियों को भ्रमित करने में सफल रही थी। उसकी उड़ान को असली मधुमक्खियों ने अनुसरण किया और छत्ते में जाने के लिए उन्होंने रोबोट मधुमक्खी की बात भी मानी।

यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इंसान भी जानवरों से संचार करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए विज्ञानी तकनीक के विकास में लगे हुए हैं। जानवरों से संचार करने वाली इस एआइ तकनीक को भविष्य में रोबोट्स में लगाया जा सकेगा, जिससे दो भिन्न प्रजातियों के बीच संचार संभव हो पाएगा। जहां एक ओर यह एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है वहीं इस तकनीक के संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग में जंगली जानवरों को गलत तरीके से नियंत्रित करने और उनके रहन-सहन के साथ छेड़छाड़ करने की भावना आ सकती है। विज्ञानियों ने एक एआइ आधारित एक सिस्टम भी तैयार किया है, जो छह बुनियादी भावनाओं खुशी, आश्चर्य, गुस्सा, घृणा, उदासी और भय को व्यक्त करने वाले चेहरे को पहचानने में सक्षम पाया गया है। कुल मिलाकर भविष्य में एआइ आधारित ऐसी मशीनें हमारे सामने होंगी, जो इंसानी भावनाओं को पहचानने में सक्षम होंगी। भविष्य में रोबोट और ड्रोन युद्ध के मैदान के अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में भी बड़ी भूमिका निभाते दिखाई देंगे।

(डायरेक्टर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी)

खरी-खरी

चुनावी रण में समर्थक

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

देश में तो हर वक्त चुनाव का मौसम रहता है। कुछ नेता फुल टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव लड़ना एवं लड़ाना उनका शगल होता है। अब कोई लड़ाई अकेले तो लड़ी नहीं जाती। उसके लिए वफादार समर्थकों की भी जरूरत होती है। वास्तव में किसी भी पार्टी की ताकत उसके समर्थकों की संख्या पर ही निर्भर करती है। समर्थक नेता जी के साथ पहुंचकर हर सभा की संख्या और शोभा दोनों बढ़ाते हैं।

नेता जी का टेंपो हाई करने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं समर्थकों पर होती है। ये बातों के बताशे फोड़कर चुनाव जिताते या हारते हैं। इनके पास ऐसे-ऐसे तर्क होते हैं कि सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक भी उन पर विश्वास करने लगते हैं। इनके पास ऐसे-ऐसे आंकड़ों का विश्वकोश होता है, जिसको ये अपने समर्थन में सनद की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे यह कुछ के लिए शौक होता है और कुछ के लिए धंधा। जिनके लिए यह शौक होता है उन्हें प्रायः चुनाव विश्लेषक का शाब्दिक तमगा प्रदान किया जाता है। न्यूज चैनलों की कान पकाऊ बहसों से लेकर नुक्कड़ पर लगे मजमे तक, ये शौकीन लोग विभिन्न राजनीतिक गुणा भाग का गणित समझाते दिख जाते हैं। वहीं जिनके लिए यह धंधा है, वे चुनावी रणनीतिकार कहलाते हैं। नेताओं के चुनाव कार्यालय से लेकर मतदान बूथ तक इनकी उपस्थिति सार्वभौमिक है। कार्यालय प्रभारी, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख जैसी संज्ञाओं से इन्हें सुशोभित किया जाता है।

समर्थकों की मुख्य रूप से तीन किस्में पाई जाती हैं। पहले वे होते हैं, जो पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। चाहे पार्टी कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए ये उसका साथ नहीं छोड़ते। दूसरे प्रेमिका रूपी होते हैं, जो पार्टी के नेता के आकर्षक व्यक्तित्व को आंखों में भरकर उसके दीवाने हो जाते हैं। बहुतायत में पाए जाने वाले तीसरे प्रकार के समर्थकों का जुड़ाव लिव इन रिलेशन जैसा होता है। ऐसे सत्ताधारी पार्टी में ज्यादा पाए जाते हैं। जब तक पार्टी सत्ता में रहती है, ये उसके साथ रहते हैं। सत्ताधारी पार्टी से सत्ता की डोर छूटते ही इनकी डोर भी टूट जाती है।

पोस्ट

हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की प्रशंसा में है। जहां तक मैं जानता हूं इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हनुमान एकमात्र सच्चे ईश्वर हैं। आखिर उससे कोई आहत कैसे हो सकता है? जफर@Zaffar_Nama

पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव को लेकर भाजपा के पास दो विकल्प थे। पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान। पशुपति पारस के पास सांसद थे तो चिराग पासवान के पास जनता। भाजपा के लिए यह फैसला बहुत आसान था।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

परिवारवाद वहां है, जहां पूरी राजनीतिक पार्टी की कमान एक परिवार के हाथ में होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के मुख्य महासचिव तक एक ही परिवार से होते हैं। जहां सीएम का नाम योग्यता से नहीं, परिवार के आधार पर तय होता है।
डा. ऋचा सिंह@RichaSingh_Alld

बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत की वापसी की खबर भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, दवाओं और सबसे बढ़कर रिषभ पंत की अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है।
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी की ओर से हिंदू धर्म में 'शक्ति' को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा?

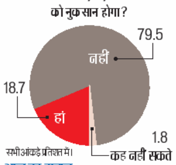

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भाजपा ने पशुपति पारस के बजाय चिराग पासवान को महत्व देकर ठीक किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चुनकर आए पुतिन जी पुनः पांचवी बार,
खुशियाली की बात है शुभ-शुभ बोलो यार।
शुभ-शुभ बोलो यार विश्व को दो सौगातें,
विश्वयुद्ध की आप कर रहे हो क्यों बातें!
डर लगता है बंधु आपकी बातें सुनकर,
शब्द मिसाइल आप जरा दागो चुनचुनकर!!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

एक खेमे में हताशा तो दूसरे में बेचैनी

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ,
उत्तराखंड

चुनाव के समय देशभर में जिस तरह दलबदल का सिलसिला चल रहा है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। पिछले लगभग दो महीने में कांग्रेस के एक विधायक समेत कई पूर्व विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर यह दिख रहा है कि कांग्रेस खेमे में हताशा का माहौल है। यद्यपि इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। वह यह कि बाहरी नेताओं की आमद से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस से इतने पूर्व विधायक और विधायक पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें एडजस्ट कैसे किया जाएगा? अगर अगले विधानसभा चुनाव में टिकट या बड़े ओहदे का वादा किया गया है तो फिर स्वयं उनके भविष्य का क्या होगा?

चुनाव विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, पाला बदलने का खेल खूब चलता है। उत्तराखंड में तो इसका पुराना इतिहास भी रहा है। सबसे चर्चित दलबदल यहां वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में हुआ था। तब लगभग 10 महीने की अवधि में एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 12 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें से नौ विधायकों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस छोड़ दी थी। इस बार का परिदृश्य बदला हुआ है। बीते वर्ष हरिद्वार जिले में हुए पंचायत चुनाव से पहले बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की राह पकड़ी। उसके बाद से यह क्रम थमा नहीं, बल्कि अब इसमें एकाएक तेजी आ गई है। पिछले कुछ समय में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, विजयपाल सजवाण, धन सिंह नेगी, मालचंद और हाल में बदरीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें से धन सिंह नेगी के अलावा सभी भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछला लोकसभा चुनाव गढ़वाल सीट से कांग्रेस टिकट पर लड़े मनीष खंडूड़ी भी भाजपा में चले गए हैं।

बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी (बाएं से दूसरे) का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी। फाइल

पूर्व मंत्री दिनेश धनै भी अब भाजपा का हिस्सा हैं।

एक के बाद एक बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा ही, साथ ही लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर भी नेताओं में हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। इसका उदाहरण पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, जिन्होंने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें गढ़वाल सीट से मैदान में उतार दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं।

उधर भाजपा नेताओं की चिंता अलग तरह की है। पिछले 10 वर्षों से पार्टी में आए नेताओं के राजनीतिक पुनर्वास ने कई भाजपा नेताओं के पैरों तले की राजनीतिक जमीन खिसका दी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज को जब भाजपा ने 2017 में विधानसभा का टिकट दिया तो तीरथ सिंह रावत को सीट ही नहीं मिली। यह अलग बात है कि बाद में तीरथ सिंह रावत को भाजपा ने गढ़वाल सीट से लोकसभा पहुंचाया और फिर वह चार महीने के लिए ही सही, मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से आए सभी विधायकों या उनके स्वजन को भाजपा ने टिकट दिया। यही नहीं, जब इस चुनाव में भाजपा तीन-चौथाई से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आई तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में छह स्थान पूर्व कांग्रेसियों के हिस्से आए। इनमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, रेखा आर्या एवं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा के नाम शामिल थे।

भाजपा ने पाला बदल अपना दामन थामने वालों के साथ किए गए वादे को निभाया, लेकिन इस फेर में उन क्षेत्रों के भाजपा नेताओं की अनदेखी हो गई, जो टिकट के स्वाभाविक दावेदार हुआ करते थे। अब भाजपा सांगठनिक रूप से मजबूत और अनुशासन से बंधी पार्टी मानी जाती है, इसलिए सतह पर तो इस स्थिति को लेकर कुछ हलचल नजर नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर नेताओं में इससे बेचैनी जरूर महसूस की गई। ऐसा ही कुछ इस चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं के भाजपा में आने से हो रहा है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां से विधायक या पूर्व पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने के लिए जिस तरह से कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं, उससे तो लोग यह भी कहने लगे हैं कि कांग्रेसमुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा ही कांग्रेसयुक्त हो गई है।

हरियाणा डायरी

चेहरा बदलने की रणनीति

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख,
हरियाणा

भाजपा के काम करने के तरीके पर निगाह रखने वाले इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं कि चुनाव से पहले पार्टी अपनी सरकार वाले राज्यों में मुख्यमंत्री क्यों बदलती है। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते, वहां चुनाव के बाद किसी नए और पार्टी की पिछली पंक्ति में रहकर काम करने वाले गैर विवादित चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। यह भाजपा का काम करने का तरीका है, जिसका उसको फायदा मिलता है। उत्तराखंड और गुजरात इसके उदाहरण हैं, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को बंपर सफलता हासिल हुई। हरियाणा में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। करीब साढ़े नौ साल तक बिना किसी दाग के भाजपा की सरकार चलाने वाले मनोहर लाल को अचानक बदल दिया गया और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। भाजपा का यह निर्णय मनोहर लाल के विरोधियों के लिए तो सामान्य था, लेकिन नायब सिंह सैनी के लिए बेहद चौंकाने वाला था।

हरियाणा से पहले भाजपा ऐसे प्रयोग कई राज्यों में कर चुकी है। गुजरात में भी इसी तरह अचानक सत्ता परिवर्तन किया गया। आनंदी बेन पटेल के स्थान पर मुख्यमंत्री बने विजय रुपाणी को साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से करीब 15 माह पहले हटा दिया गया। रुपाणी के स्थान पर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका नतीजा गुजरात में भाजपा की बंपर जीत के रूप में सामने आया। गुजरात के बाद उत्तराखंड में इसी तरह का घटनाक्रम हुआ। उत्तराखंड में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले बदल दिया था। जुलाई 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा दिया। वे चार महीने ही सीएम के पद पर रहे थे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद 2022 में चुनाव हुए और भाजपा की सरकार बनी तथा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया।

मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं, जहां चुनाव के बाद भाजपा ने नए चेहरों मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मोहन लाल यादव को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णु सहाय के रूप में भाजपा ने नए चेहरे पर दांव लगाया। अब हरियाणा में सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने राजनीतिक गलियारों में यह बहस छेड़ दी है कि आखिर भाजपा चुनाव से पहले अथवा चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री क्यों बदलती है?

इसके पीछे भाजपा की गहरी रणनीति है। चेहरा बदलने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्हें मुख्यमंत्री पद से अलग किया गया है, उनकी काबिलियत अथवा राजनीतिक क्षमता पर पार्टी को किसी तरह का भरोसा नहीं रह गया है। उनमें कुछ खास बात है, तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब पार्टी दूसरे स्थान पर उन नेताओं की सेवाएं लेने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी नई पीढ़ी के साथ-साथ नए चेहरों को भी सामने लाना चाहती है। भाजपा पिछले कई वर्षों में पार्टी के भीतर यह संदेश देने में पूरी तरह से कामयाब रही है कि एक दरी बिछाने वाला बेहद आम कार्यकर्ता भी पार्टी में शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। अनुभवी चेहरों का लाभ पार्टी केंद्र की राजनीति में उठाती है। नए-नए विकल्प तैयार करती है। नए चेहरों को मौका देने के पीछे राजनीति की दूसरी लाइन तैयार करने का भी सोच काम करता है, जो कि भाजपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति के पीछे भाजपा का एक सोच यह भी काम करता है

मनोहर लाल की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (दाएं)। फाइल

कि जब कोई नेता मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय तक बैठा दिखाई देने लगता है तो उसके राजनीतिक विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगता। वे अंदर ही अंदर उसका विरोध करते रहते हैं। साथ ही पार्टी को आशंका रहती है कि कहीं चुनाव में जाने पर उसे लोगों की सत्ता विरोधी मानसिकता का सामना न करना पड़ जाए। ऐसे में सीएम का चेहरा बदलकर पार्टी न केवल अपने संगठन के भीतर कुछ नेताओं में पनपने वाली कथित कुंठा को खत्म करने में कामयाब होती है, बल्कि लोगों में आने वाली सत्ता विरोधी मानसिकता को भी जड़ से खत्म करने में सफलता प्राप्त कर लेती है।

हरियाणा इसका बड़ा उदाहरण है। अपने एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वह पिछले एक साल से पार्टी में अपना विकल्प तैयार कर रहे थे और नायब सिंह सैनी के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी मनोहर लाल को पहले से पता था कि उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी है। मनोहर लाल भाजपा की केंद्रीय राजनीति में अब किस भूमिका में होंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा लोकसभा और उसके करीब छह माह बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में विरोधी राजनीतिक दलों का गणित जरूर बिगाड़ सकती है।

****

लेनोवो ने लांच किए लीजन सीरीज के नए लैपटाप

नई दिल्ली : वैश्विक टेक्नोलाजी कंपनी लेनोवो ने मंगलवार को भारत में अपनी नई सीरीज लीजन के नए गेमिंग लैपटाप लांच किए। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और अगली पीढ़ी के फीचर दिए गए हैं। इस सीरीज में चार लैपटाप लांच किए गए हैं जिनकी कीमत 1,29,990 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने इन लैपटाप में 14वीं जेनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर और एनवीडिया आरटीएक्स 4090 ग्राफिक कार्ड लगाया है। (आइएएनएस)

पिछले कुछ वर्षों में देश की गति सकारात्मक रही है। इसका सारा श्रेय सरकारी नीतियों को जाता है जिन्होंने कारोबारों के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा दिया है।

— अभिजीत झावर, मुख्य रणनीति अधिकारी, इन्फ्रा डाट मार्केट

सेंसेक्स	72,012.05	▼ 736.37
निफ्टी	21,817.45	▼ 238.25
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 66,250	▲ ₹110
चांदी प्रति किलोग्राम	₹76,500	▼ ₹500
डालर	₹83.03	▲ ₹0.13
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$86.54	

एक नजर में

बैंक आफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज घटाया

मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के आफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरों में 15 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। अब होम लोन पर बैंक का ब्याज 8.45 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत हो गया है। नई दर 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू होगी। इसके अलावा, बैंक ने मार्च के अंत तक प्रोसेसिंग फीस में छूट देने की भी घोषणा की है। बैंक ने छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए बिना प्रोसेसिंग शुल्क सात प्रतिशत की दर पर लोन देने की घोषणा की है। (प्रेट्र)

बैंक आफ जापान ने 17 वर्ष बाद बढ़ाया ब्याज

टोक्यो : बैंक आफ जापान ने मंगलवार को अपनी ब्याज दरों में 17 वर्ष बाद पहली बार बढ़ोतरी की। इसके साथ यहां ब्याज दर नकारात्मक दायरे से बाहर आ गई है। इससे पहले फरवरी 2007 में ब्याज में बढ़ोतरी की गई थी। बैंक आफ जापान ने ब्याज दरों को माइनस -0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0-0.1 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने महंगाई दर का लक्ष्य दो प्रतिशत रखा है। (एपी)

एनएचएआइ ने 16 हजार करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने राजमार्ग मुद्रीकरण के जरिये 16 हजार करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। यह राशि एनएचएआइ की निवेश ट्रस्ट एनएचआइटी से जुटाई गई है। एनएचएआइ ने करीब 900 लंबे राजमार्ग के लिए यह राशि जुटाई है। संपत्ति मुद्रीकरण के जरिये एनएचएआइ की ओर से जुटाई गई यह अब तक की सबसे ज्यादा राशि है। (प्रेट्र)

आइसक्रीम कारोबार को अलग करेगी यूनीलीवर

बेंगलुरु : ब्रिटेन की एफएमसीजी कंपनी यूनीलीवर अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करेगी। इसके साथ ही कंपनी लागत में कमी के लिए वैश्विक स्तर पर 7,500 नौकरियों की कटौती करेगी। कंपनी मैगनम और बेन एंड जैरी नाम से आइसक्रीम की बिक्री करती है। इसको अलग करने की प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है। (रायटर)

आठ प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है विकास दर

आरबीआइ ने मासिक रिपोर्ट में जताई उम्मीद, कहा- मजबूत बुनियाद से आगे भी बनी रह सकती है तेजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ ने मंगलवार को अपनी मासिक रिपोर्ट कहा कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान देश की औसत आर्थिक विकास दर आठ प्रतिशत से ज्यादा रही है। इकोनमी की मजबूत बुनियाद से संकेत मिलता है कि इसे आगे भी बनाए रखा जा सकता है और इसके आधार पर तेज विकास की नींव भी तैयार की जा सकती है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तीनों तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर क्रमशः 8.2, 8.1 और 8.4 प्रतिशत रही है। आरबीआइ ने वो सारे तथ्य भी गिनाए हैं जिनसे आगे भी विकास दर आठ प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है।

एक समय था जब योजना आयोग 10 प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर हासिल करने का एजेंडा तैयार कर रहा था। इस बारे में अंतिम बार शीर्ष स्तर पर चर्चा वर्ष 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने की थी। लेकिन उसके बाद विकास दर की रफ्तार वैसी नहीं रही। कोरोनाकाल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो दम दिखाया है, उससे अब सरकारी एजेंसियों का भरोसा लौटने के संकेत हैं। आरबीआइ की रिपोर्ट इसका उदाहरण है। केंद्रीय बैंक के भरोसे के पीछे एक वजह महंगाई की स्थिति है जिसमें कमी आ रही है।

रिपोर्ट में आरबीआइ ने कहा है कि चार प्रतिशत महंगाई दर के लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर ही थोड़ी चिंता है। खुदरा महंगाई के बीते दो महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में खाद्य कीमतों में नरमी आने का सिलसिला अस्थायी ही था। मोटे अनाजों की कीमतों में भी तेजी बरकरार है। मछली व मीट में भी महंगाई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा दूसरे उत्पादों की कीमतों में नरमी है। रिपोर्ट में ईंधन की कीमत का हवाला दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई हैं।

- वर्ष 2021 से 2024 तक आठ प्रतिशत से ज्यादा रही है औसत विकास दर
- चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में भी आठ प्रतिशत से ज्यादा तेजी
- महंगाई में आ रही कमी, खाद्य पदार्थों की ज्यादा कीमतों को लेकर थोड़ी चिंता

निवेशकों का बाजार पर आकर्षण बढ़ा

निवेशकों में भारतीय बाजार का आकर्षण और मजबूत हुआ है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी ने भारतीय इकोनमी की रफ्तार को और तेज करने का मौका दिया है। ऐसे में भारत को अब विश्वस्तर की ढांचागत सुविधाओं को खड़ा करने और मैन्यूफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए। साथ ही सर्विस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने पर काम करके और उच्च स्तर का श्रम उपलब्ध कराने से हम अगले दस वर्षों में भारतीय इकोनमी की चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं।

इन वजहों से रहेगी तेजी

रिपोर्ट में उन तथ्यों को एक-एक करके गिनाया गया है, जो विकास दर की तेजी को बनाए रखने में मदद करेंगे। इसमें प्रमुख हैं- चालू खाते के घाटे का कम होना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी होना और लगातार तीसरे वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के मुताबिक रहना। इसके अलावा, कंपनियों की तरफ से कर्ज चुकाने की स्थिति और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होना, दो अन्य सकारात्मक पहलू हैं। वित्तीय बाजारों पर इन सकारात्मक तथ्यों का ही असर दिख रहा है।

बड़ी कंपनियों में बिकवाली से 736 अंक लुढ़का सेंसेक्स

72,012 अंक पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

4.86 लाख करोड़ रुपये घटी निवेशकों की संपति

मुंबई, प्रेट्र : टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और कमजोर एशियाई संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 736.37 अंक की गिरावट के साथ करीब एक महीने के निचले स्तर 72,012.05 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 238.25 अंक गिरकर एक माह के निचले स्तर 21,817.45 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों का कहना है कि जापान की ओर से 17 वर्ष बाद ब्याज में वृद्धि से एशियाई बाजारों में कमजोरी रही। इससे प्रमुख घरेलू सूचकांकों की नकारात्मक शुरुआत हुई। इसके अलावा निवेशक अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले सतर्कता बरतते दिखाई दिए। इससे घरेलू बाजारों में 700 से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 4.86 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है।

एलआइसी के शेयरों में तीन प्रतिशत की गिरावट

जीवन बीमा कंपनी एलआइसी के शेयर मंगलवार को बीएसई में 2.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 879.50 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। बीते तीन दिनों में एलआइसी के शेयरों में 8.27 प्रतिशत की गिरावट हो चुकी है। अब शेयर का मूल्य अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर 1,175 रुपये प्रति इकाई से 25.14 प्रतिशत तक घट चुका है। दूसरी ओर, टाटा संस की ओर से 2.3 करोड़ शेयरों की बिक्री से टीसीएस के शेयर भी मंगलवार को चार प्रतिशत से ज्यादा लुढ़ककर बंद हुए।

10 वर्षों में एक हजार ट्रिलियन डालर की कंपनी बन सकती है चिप निर्माता एनवीडिया

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन: बीते दो-तीन वर्षों से पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मांग काफी बढ़ी है। इसके चलते चिप बनाने वाली दुनियाभर की कंपनियों के शेयरों में भी तेज उछाल आया है। अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयरों में बीते 12 महीनों में 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि चक्रवृद्धि गणित के सामान्य नियमों से गणना की जाए तो जिस तेजी से आज एनवीडिया के शेयर बढ़ रहे हैं, उससे एक दशक के अंत में कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक हजार ट्रिलियन डालर तक पहुंच सकता है। विश्व बैंक के अनुसार, इस समय पूरी दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 101 ट्रिलियन डालर है।

शेयरों में लगातार तेजी से एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण 2.2 ट्रिलियन डालर से ज्यादा हो गया है। पूंजीकरण के मामले में अब एनवीडिया माइक्रोसाफ्ट और एपल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जब तीन प्रमुख चैटबाट माइक्रोसाफ्ट कैपिलोट, गूगल के जैमिनी और एंथ्रोपिक के क्लाउड-3 से पूछा गया कि एनवीडिया के शेयर मूल्य में यह तेजी रहती है तो एक दशक में कंपनी का बाजार पूंजीकरण क्या होगा? तीनों चैटबाट ने सीधे इस सवाल का जवाब देने में अनिच्छा जताई। प्रत्येक चैटबाट ने कहा कि वे शेयर मूल्य का विश्वसनीय रूप से या थोड़ी भी सटीकता के साथ आकलन नहीं कर सकते हैं।

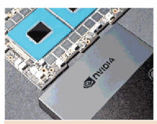

- एआइ की बढ़ती मांग के चलते बीते 12 महीनों में 290 प्रतिशत बढ़ा कंपनी का शेयर

2.2 ट्रिलियन डालर पूंजीकरण के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनी एनवीडिया

अब हमारे पास जेनरेटिव एआइ युग के लिए चिप : हुआंग

नई दिल्ली, आइएएनएस : एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग ने मंगलवार को कहा कि अब हमारे पास जेनरेटिव एआइ युग के लिए एक प्रोसेसर बनाया है। अमेरिका में आयोजित जीटीसी कान्फ्रेंस में हुआंग ने कंपनी का नया ब्लैकवेल कंप्यूटिंग प्लेटफार्म भी पेश किया। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई कंप्यूटिक पावर साफ्टवेयर से लेकर सर्विसेज, रोबोटिक्स से लेकर मेडिकल टेक्नोलाजी और अन्य क्षेत्रों के लिए काफी कुछ दे सकती है।

कंपनियां आडियो-वीडियो तरीके से दे सकेंगी आइपीओ की जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कंपनियों को आइपीओ के बारे में जानकारी आडियो-विजुअल फार्मेट में देने का प्रस्ताव दिया है। सेबी के इस कदम से निवेशकों के लिए आफर के अहम फीचर को समझना आसान होगा। प्रस्ताव पर हितधारकों से नौ अप्रैल तक टिप्पणी मांगी गई है। प्रस्ताव के अनुसार आडियो-विजुअल हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके प्रत्येक वर्जन की अवधि अधिकतम आठ मिनट होगी। सेबी के मुताबिक आडियो-विजुअल जितनी भी अवधि का बनाया जाएगा, उसमें पब्लिक आफर डाक्युमेंट के सभी सेक्शन में किए गए डिस्क्लोजर को बराबर-बराबर समय देना होगा। इसमें रिस्क फैक्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर, आफर का उद्देश्य, कारोबार, वित्तीय जानकारियां, कानूनी मामले व कंपनी पर असर डालने वाले अन्य मुद्दे शामिल हैं। अभी कंपनियां रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) के जरिये सेबी को जानकारी देती हैं। इसमें कंपनी की प्रमुख जानकारी होती है।

चालू वित्त वर्ष में 450 अरब डालर हो सकता है देश का वस्तु निर्यात

नई दिल्ली, प्रेट्र: लाल सागर संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारत का वस्तु निर्यात 450 अरब डालर तक पहुंच सकता है। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन आफ इंडिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के नवनियुक्त प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि समुद्री बीमा की उपलब्धता और माल ढुलाई शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि सुनिश्चित करके लाल सागर संकट की चुनौतियों का समाधान करना समय की मांग है।

फियो के प्रेसिडेंट ने कहा कि देश का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र खासतौर पर एमएसएमई के लिए आसान व कम लागत वाले कर्ज और मार्केटिंग मदद की आवश्यकता है। इसके अलावा, ब्रिटेन और ओमान जैसे देशों के साथ जल्द मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एमएसएमई से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इसका कारण यह है कि 2030 तक एक ट्रिलियन डालर के वस्तु निर्यात तक पहुंचने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि फियो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रहा है। वहीं, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर शेखरी ने मंगलवार को कहा कि 2030 तक 40 अरब डालर का गारमेंट निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी होगी।

फियो के नवनियुक्त प्रेसिडेंट ने कहा- निर्यात बढ़ाने के लिए लाल सागर संकट का समाधान करना समय की मांग

20 प्रतिशत बढ़ा शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल 2023 से 17 मार्च 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 19.88 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कारपोरेट टैक्स 9,14,469 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर 9,72,224 करोड़ रुपये रहा है। व्यक्तिगत आयकर में सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) भी शामिल है। सीबीडीटी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक 3.37 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.27 करोड़ रुपये रहा है और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 18.74 प्रतिशत की वृद्धि रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है। माना जा रहा है कि लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रीय फलक

17 राज्यों ने लिया 50,200 करोड़ रुपये का कर्ज

मुंबई, प्रेट्र : अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक नीलामी में 17 राज्यों ने मंगलवार को बाजार से 50,200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। यह नीलामी से पहले बताई गई राशि 27,500 करोड़ रुपये से 81 प्रतिशत अधिक है। यह राशि 7.45 प्रतिशत की ब्याज दर पर जुटाई गई है।

नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य वित्त वर्ष की समाप्ति करीब होने के कारण बाजार से अधिक उधार ले रहे हैं। आम तौर पर मार्च तिमाही सरकारी खर्च के लिए सबसे व्यस्त होती है।

इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने एक नोट में कहा कि राज्यों के कर्ज की औसत अवधि 16 से घटकर 15 साल होने के बावजूद रिकार्ड स्तर पर कर्ज की उपलब्धता रही है। चालू वित्त वर्ष में राज्य अब तक 9.28 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं। यह राज्यों की ओर से पिछले वर्ष समान अवधि में लिए गए 7.17 लाख करोड़ रुपये से 29.4 प्रतिशत ज्यादा है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका में रिश्वत मामले में जांच की बात स्वीकारी

- अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ने कहा- उसका जांच का सामना कर रही थर्ड पार्टी से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका में रिश्वतखोरी मामले की जांच से अवगत होने की बात कही है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसका जांच का सामना कर रही थर्ड पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही उसे जांच के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है।

घरेलू शेयर बाजारों ने अदाणी समूह की कंपनियों से उस मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें समूह की किसी इकाई के कथित तौर पर रिश्वतखोरी में शामिल होने की अमेरिका में जांच किए जाने की बात कही गई थी। इस संबंध में समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों ने अलग-अलग जवाब भेजा है। अदाणी ग्रीन एनर्जी को छोड़कर अन्य कंपनियों ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। साथ ही कहा है कि उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है। अदाणी ग्रीन एनर्जी ने अपने जवाब में जांच की प्रकृति या आरोपों का ब्योरा नहीं दिया है। वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मार्गन ने अपने एक नोट में कहा है कि इस जांच से संबंधित ब्योरा बहुत कम है और इससे किसी सफल अभियोजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। हालांकि, इसका सीमित वित्तीय या मौलिक प्रभाव पड़ सकता है। जेपी मार्गन ने कहा कि अदाणी समूह के अमेरिकी डालर बांड जारीकर्ताओं की प्रोफाइल के आधार पर यह इकाई अदाणी ग्रीन एनर्जी से संबंधित हो सकती है। अमेरिका में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत दोषी कंपनी पर 20 लाख डालर या लाभ की दोगुना राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यक्तियों के मामले में यह पांच साल तक की कैद और 2.5 लाख डालर का जुर्माना या लाभ का दोगुना हो सकता है।

बिहार में जांच में फर्जी पाए गए 815 शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : बिहार में फर्जी तरीके से नियुक्त नियोजित शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 815 शिक्षकों की सेवा 15 दिनों में समाप्त करने का निर्देश विभाग ने दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने मंगलवार को सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।

इसमें रंजीत पंडित की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए लिखा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में 2126 नियोजित शिक्षक फर्जीवाड़ा के दोषी पाए गए थे। इनमें से 1310 की सेवा नियोजन इकाई द्वारा समाप्त की गई है।

एक शिक्षक का केस निगरानी ने वापस ले लिया। शेष 815 ऐसे नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई लंबित है। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियोजन इकाई से समन्वय स्थापित करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने को कहा है।

ओडिशा में भोज नहीं कराने पर तीन दिनों तक पड़ा रहा महिला का शव

- पुलिस के हस्तक्षेप एवं दावत देने पर राजी होने के बाद किया गया अंतिम संस्कार
- मयूरभंज जिले के तेलबिला गांव की घटना, ग्रामीणों को दान के लिए देना था एक भेड़

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा में परंपरा की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इसका उदाहरण मयूरभंज जिले के तेलबिला गांव में देखने को मिला है। गांव की 70 वर्षीय महिला की मौत के बाद उसका शव तीन दिनों तक बिना दाह संस्कार किए पड़ा रहा। इसके पीछे कारण मृतका के परिवार का गांववालों को मांस की दावत दे पाने में असमर्थतता थी।

जानकारी के अनुसार तेलबिला गांव निवासी सोमवारी सिंह (70) की शनिवार की दोपहर मौत हो गई थी। मौत के बाद गांव के शुद्धिकरण के लिए गांव में भेड़ की दावत देने का रिवाज है। परंपरा के अनुसार सोमवारी के दोनों बेटों डाक्टर सिंह और चंदन सिंह को ग्रामीणों को दान में एक भेड़ देना था। बेटों ने जब भेड़ देने में असमर्थता जताई तो ग्रामीणों ने सोमवारी के शव के दाह संस्कार में मदद करने से इन्कार कर दिया। ग्रामीणों की जिद पर छोटा बेटा चंदन भेड़ लाने की बात कहकर गया, परंतु व्यवस्था नहीं हो सकी। बड़े बेटे ने भी भेड़ देने में स्वयं को असमर्थ बताया। ग्रामीण भी दावत की जिद पर अड़े रहे। इस जिद के बीच तीन दिनों तक शव घर में ही पड़ा रहा, उससे दुर्गंध आने लगी। यह जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने दोनों बेटों और ग्रामवासियों के साथ चर्चा की। ग्रामवासी यहां भी बिना दावत के सहयोग नहीं करने की जिद पर अड़े रहे। अंततः बेटे घर की संपत्ति बेचकर ही सही, दावत देने पर राजी हुए, तब जाकर सोमवारी का अंतिम संस्कार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण से जुड़े लेख पर दर्ज एफआइआर रद की

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में समाचार लेख पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद कर दिया। लेख से सार्वजनिक सद्भाव प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एफआइआर में लगे आरोप अपीलकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराध के जरूरी घटकों को खुलासा नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिव प्रसाद सेमवाल की दायर अपील पर फैसला सुनाया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने धारा 153ए के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरोपित के लिए 'बोले गए' अथवा 'लिखे' शब्दों ने विभिन्न समूहों के बीच मनमुटाव, या दुश्मनी पैदा हुई।

मथुरा के मंदिरों की वार्षिकी रोकना दुखद : हाई कोर्ट

- ठाकुर रंग जी महाराज विराजमान मंदिर की याचिका पर सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा, वृंदावन स्थित ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर सहित नौ मंदिरों की पिछले चार वर्षों से वार्षिकी (सालाना व्यय की धनराशि) का भुगतान रोके जाने को दुखद करार देते हुए नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राजस्व बोर्ड के सचिव/आयुक्त को बुधवार 20 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। पूछा है कि इन मंदिरों की चार वर्षों की वार्षिकी का भुगतान क्यों रोका गया है? यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर की याचिका पर दिया है। बता दें, मंदिरों को वार्षिकी सरकार देती है। पूर्व में सरकार ने मंदिरों से जुड़ी जमीन ले ली थी और इसके बदले हर वर्ष कुछ धनराशि देने की बात तय हुई। रंग जी मंदिर को 87 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी।

कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य के साथ दुख जताया कि मंदिरों को वार्षिकी के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। आधुनिक तकनीकी युग में बजट आते ही सरकारी ट्रेजरी से मंदिर के खाते में धन आ जाना चाहिए। अधिकारियों को इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को 24 घंटे में भेजने का आदेश दिया है ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसे एक्शन के लिए रखा जाए।

कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कोर्ट ने सरकार को फंड देने का आदेश दिया था। सचिव के हलफनामे को देखने से साफ है कि 9,12,507 रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें 2,23,199 रुपये का आंशिक भुगतान किया गया। अभी भी 6,89,308 रुपये का भुगतान बाकी है। आयुक्त/सचिव के हलफनामे में बताया गया है कि फंड की कमी के कारण भुगतान नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा, एक साल के भुगतान का मामला नहीं है पिछले चार साल का बकाया है। कोर्ट का कहना था कि जिलाधिकारी मथुरा ने विशेष सचिव को पत्र लिखने की जानकारी दी है। स्पष्ट संकेत है कि लखनऊ के अधिकारियों को मंदिरों की वार्षिकी की कोई परवाह नहीं है। हलफनामे से साफ नहीं है कि क्या प्रयास किए गए? कोई पत्राचार दाखिल नहीं किया गया है इससे यह पता चले कि बजट के लिए कितने गंभीर प्रयास किए गए। कोर्ट ने फंड की कमी के कारण वार्षिकी जारी न किए जाने की सफाई पर हैरानी जताई और सचिव को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बुजुर्ग से सवा करोड़ रुपये की ठगी

नईदुनिया, भिलाई : डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 62 वर्षीय रोहित कुमार बघेल से एक करोड़ 31 लाख से अधिक की ठगी हो गई। शातिरों ने झांसा दिया था कि वे लाभांश में सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा लेंगे और शेयर ट्रेडिंग कर उसके 50 लाख रुपये को चार महीने में तीन करोड़ के आसपास पहुंचा देंगे, लेकिन नहीं किया गया।

पुलिस ने आरोपितों सिद्धार्थ सक्सेना और राहुल गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपित एआरके टेक्नालाजी कंपनी के कर्मचारी है। बुजुर्ग ने बताया कि 22 दिसंबर, 2023 को उनके पास सिद्धार्थ सक्सेना के नाम से फोन आया था। आरोपित ने खुद को एआरके टेक्नालाजी कंपनी का कर्मचारी बताते हुए जानकारी दी थी कि उनकी कंपनी शेयर ट्रेडिंग करती है।

महिला को दो घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख ठगे

- गाजियाबाद की पीड़िता के पास 14 मार्च को आया था अपराधियों का फोन
- मुंबई से ताइवान भेजे गए पैकेट में ड्रग्स मिलने की बात कहकर धमकाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

साइबर अपराधियों ने एक महिला से 12 लाख रुपये ठग लिए। अपराधियों ने पीड़िता के कोरियर में ड्रग्स मिलने की बात कहकर वीडियो काल के जरिए दो घंटे तक निगरानी में रखा। महिला का कहना है कि उसने कोरियर भेजा ही नहीं। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता का कहना है कि 14 मार्च को उनके पास एक फोन आया। खुद को कोरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि मुंबई से ताइवान भेजे जा रहे कोरियर में ड्रग्स पाया गया है। उनका पैकेट कस्टम विभाग के पास है। पीड़िता को धमकाया गया कि उनका बैंक खाता दाउद इब्राहिम के साथी मोहम्मद इस्लाम से जुड़ा हुआ है। कुछ देर बाद मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर वीडियो काल के जरिये उन्हें दो घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसी दौरान बैंक खाता और आधार वेरिफाइ कराकर पीड़िता के बैंक खाते में मौजूद 12 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक में गाजी टूर ट्रैवल्स के खाते में ट्रांसफर कर लिए। अपराधियों ने कहा कि 15 मिनट बाद धनराशि उनके खाते में वापस आ जाएगी। एसीपी क्राइम रितेश त्रिपाठी का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर साइबर टीम जांच कर रही है। कोरियर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी हुई है।

गाजियाबाद का साइबर थाना। फाइल

पूर्व में भी आए हैं मामले

- नौ मार्च को कोरियर में ड्रग्स भेजने के आरोप में दंपती को दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख 11 लाख रुपये ठग लिए।
- 23 फरवरी को महिला को मुंबई से ईरान भेजे पार्सल में ड्रग्स रखने के आरोप में डिजिटल अरेस्ट बताकर 56 लाख रुपये ऐंठ लिए।

डिजिटल अरेस्ट का कानून में कोई अस्तित्व नहीं : साइबर विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल का कहना है कि डिजिटल अरेस्टिंग कानूनी भाषा में अस्तित्व में नहीं है। साइबर अपराधी पीड़ित को धमकाने व झांसे में लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वीडियो काल से पीड़ित को पूछताछ के बहाने निगरानी में रखते हैं। ऐसा कोई भी फोन आने पर सबसे बेहतर काम तत्काल काल काटना है।

****

5.4 तीव्रता का भूकंप आया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को। भूकंप का केंद्र क्वेटा से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 35 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप से किसी प्रकार की हानि की जानकारी नहीं मिली है

इजरायल का रफाह पर हवाई हमला, 14 की मौत

गाजा के अल-शिफा अस्पताल में मारे गए 50 बंदूकधारी, 180 संदिग्ध हिरासत में

पिछले हफ्ते इजरायल ने हमास के नंबर तीन कमांडर मारवान को मार गिराया

गाजा में मानवीय मदद को बाधित करना युद्ध अपराध : यूएन मानवाधिकार

हमास से लड़ाई के दौरान गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में ध्वस्त घर। एपी

यरुशलम, रायटर : फलस्तीनी शरणार्थियों से भरे रफाह शहर में इजरायली बलों ने सोमवार रात हवाई हमले किए हैं। इसमें 14 लोगों की जान गई है। वहीं, मंगलवार को इजरायली बल ने बताया कि सोमवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में की गई कार्रवाई में इजरायल ने 50 बंदूकधारी मार गिराए और 180 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इधर, अमेरिका ने जानकारी दी कि सात अक्टूबर की योजना बनाने वाला हमास का नंबर तीन कमांडर मारवान इस्सा पिछले हफ्ते इजरायल द्वारा मार गिराया गया।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि रफाह में सोमवार रात मरने वाले 14 लोगों में तीन महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हमलों से जान बचाकर 10 लाख से अधिक लोग इन दिनों रफाह शहर में शरण लिए हुए हैं। मिस्र की सीमा से सटे रफाह शहर में जमीनी हमले की योजना को लेकर अमेरिका ने इजरायल से पुनर्विचार का आग्रह किया है। अगर यहां इजरायली हमले तेज हुए तो मानवीय मदद पहुंचानी मुश्किल हो जाएगी। रफाह सीमा से ही गाजावासियों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने मंगलवार को कहा कि गाजा में इजरायल द्वारा मानवीय मदद पर प्रतिबंध लगाना युद्ध अपराध होगा।

इजरायल का कहना है कि हमास की चार राइफल की बटालियन और राकेट बनाने वाले लड़ाकों की फौज रफाह में ही है। हमास के इस अंतिम किले को नष्ट कर ही हमास पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन हमास की इस योजना ने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डरा दिया है। क्योंकि, ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में गाजा के लोग बेमौत मारे जाएंगे।

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया कि कई हत्या व सात अक्टूबर के हमास हमले की योजना बनाने वाला हमास कमांडर मरवान इस्सा को पिछले हफ्ते इजरायल ने मार गिराया था। वह फिर से घुसपैठ की कोशिश करने की फिराक में था। वहीं, इजरायल ने मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया है। दूसरी ओर, सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कई मिसाइलों को मार गिराया है। उल्लेखनीय है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में अब तक तीस हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सत्तर हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

रफाह में जमीनी कार्रवाई शुरू हुई तो युद्धविराम वार्ता होगी बाधित

इजरायल में युद्धविराम और बदले में बंधकों की रिहाई को लेकर ताजा दौर की वार्ता शुरू हो गई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोहा में इजरायल के खुफिया प्रमुख के साथ युद्धविराम की कोशिश के उद्देश्य से बातचीत के बाद कतर के अधिकारी आशावादी थे। लेकिन रफाह में अगर जमीनी कार्रवाई शुरू हुई तो यह वार्ता को अवरुद्ध कर देगी।

अमेरिका ने इजरायल से जमीनी कार्रवाई का विकल्प तलाशने को कहा

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने संवादाताओं से सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात होने की जानकारी दी। कहा, इजरायल से रफाह में जमीनी कार्रवाई का विकल्प तलाशने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल जल्द ही अमेरिका में बातचीत के लिए आएंगे। अमेरिका इजरायली योजना से चिंतित है। इजरायली हमले में अब त 31,819 फलस्तीनियों की जान गई है। वहीं, कनाडा की संसद ने एक अप्रतिबद्ध प्रस्ताव पास कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दो राष्ट्र के सिद्धांत पर काम करने का आग्रह किया है।

कमला हैरिस बोलीं, ट्रंप लोकतंत्र व मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा

- ट्रंप बोले, डेमोक्रेट को वोट करने वाले यहूदी अपने धर्म से नफरत करने वाले
- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों ओर से हो रही बयानबाजी से बढ़ा चुनावी पारा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। फाइल/एपी

वाशिंगटन, एएनआइ: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध जारी बयानबाजी ने चुनावी पारा बढ़ा दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और बंदूक हिंसा जैसे मुद्दों को सुलझाने का संकल्प लिया। दूसरी ओर, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो यहूदी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करना चाहते हैं समझो वे इजरायल और अपने धर्म से नफरत करते हैं।

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स पर डाले पोस्ट में ट्रंप पर जोरदार हमला किया। उपराष्ट्रपति का बयान तब आया जब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में जो बाइडन और रिपब्लिकन प्रत्याशी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपना नामांकन सुरक्षित कर चुके हैं। इनकी उम्मीदवारी का औपचारिक एलान जुलाई-अगस्त में किया जाएगा। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के अभियान के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने कहा कि ट्रंप छह जनवरी, 2021 जैसी हिंसा को फिर दोहराना चाहते हैं। वह ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित हुए तो खून-खराबा होगा।

एपी समाचार एजेंसी के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक साक्षात्कार में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा युद्ध से निपटने को लेकर आलोचना की। ट्रंप की टिपण्णी से व्हाइट हाउस और यहूदी नेता भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की लड़ाई अब धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है।

एच-1बी वीजा पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 को

- अमेरिकी संघीय एजेंसी ने बताया कि यह सुविधा यूएससीआइएस की साइट पर आनलाइन उपलब्ध

वाशिंगटन, प्रेट्र: भारतीय आइटी पेशेवरों में लोकप्रिय अमेरिकी एच-1बी वीजा की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि 22 मार्च को खत्म हो रही है। अमेरिकी संघीय एजेंसी ने बताया कि यह सुविधा यूएससीआइएस की साइट पर आनलाइन उपलब्ध है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियां हर वर्ष भारत और चीन जैसे देशों के हजारों एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों की भर्ती करती हैं।

अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) ने सोमवार को बताया कि तय तिथि तक संभावित आवेदकों और कानूनी प्रतिनिधियों को चयन प्रक्रिया के लिए हर लाभार्थी का पंजीकरण करने और पंजीकरण शुल्क भुगतान करने के लिए दिए गए आनलाइन अकाउंट का उपयोग करना होगा। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को विदेशी कामगारों की एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति करने की अनुमति देता है।

मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के लिए फार्म आइ-129 और प्रीमियम प्रोसेसिंग सेवा के लिए आइ-907 फार्म यूएससीआइएस पर आनलाइन उपलब्ध है। यूएससीआइएस ने बताया कि एक अप्रैल से एच-1बी कैप आवेदनों के लिए फार्म की आनलाइन फाइलिंग स्वीकार शुरू कर दिया जाएगा।

भगत सिंह शहीद दिवस कार्यक्रम की सुरक्षा पर निर्णय ले लाहौर पुलिस

लाहौर, प्रेट्र : लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को अगले सप्ताह भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के 93वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। भगत सिंह स्मारक फाउंडेशन के चेयरमैन वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने गत सप्ताह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लाहौर के शदमान चौक पर 93 वर्ष पहले भगत सिंह व उनके दो साथियों को फांसी दी गई थी। फाउंडेशन वहीं शहीद दिवस का आयोजन करेगा।

इम्तियाज ने अदालत से पंजाब सरकार को 23 मार्च को होने जा रहे समारोह की सुरक्षा करने और कार्यक्रम स्थल पर वाक-थ्रू गेट स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में इम्तियाज ने कहा कि पंजाब सरकार ने उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार व जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि शदमान चौका का नाम भगत सिंह पर रखने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उनके विरुद्ध क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

नवाज के दोनों बेटे पनामा पेपर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में बरी

- मुख्य आरोपित नवाज शरीफ को पहले ही किया चुका बरी
- गत 12 मार्च को ही दोनों भाई लंदन से लौटे थे स्वदेश

हसन नवाज हुसैन नवाज। फाइल

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन को पनामा पेपर से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में बरी कर दिया। उन पर 2018 में पनामा पेपर से संबंधित एवेनफील्ड, फ्लैगशिप व अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों का आरोप लगाया गया था। जांच में सहयोग नहीं करने और लंदन चले जाने पर 2018 में दोनों भाइयों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। हालांकि एवेनफीलड व अल-अजीजिया मामले में उनके पिता नवाज शरीफ दोषी करार दिए गए थे पर फ्लैगशिप मामले में बरी हो गए थे।

पाकिस्तान के तीन बार पीएम रहे नवाज शरीफ चार साल का आत्मनिर्वासन खत्म कर गत अक्टूबर में स्वदेश लौटे थे। उन्होने दो मामलों में दोषसिद्धि को चुनौती दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। गिरफ्तारी वारंट पर 14 मार्च तक रोक लगाए जाने के बाद हसन और हुसैन गत 12 मार्च को लौट आए और कोर्ट में पेश होने पर उन्हें जमानत दे दी गई।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान भी दो मामलों में बरी

पाकिस्तान की कोर्ट ने मंगलवार को मार्च 2022 में सरकार विरोधी मार्च के दौरान तोड़फोड़ से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने खान की याचिका स्वीकार की और उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया।

पाकिस्तान में पंजाब सरकार के साथ नवाज की बैठक से विवाद

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पंजाब सरकार की तीन प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता की है। प्रांतीय या संघीय सरकार में कोई आधिकारिक पद नहीं होने के बावजूद सरकारी बैठकों की अध्यक्षता करने के कारण विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज केवल नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। प्रांत में उनकी बेटी मरयम नवाज मुख्यमंत्री हैं। डान समाचारपत्र के अनुसार, तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे नवाज ने अपनी बेटी मरयम की अगुआई वाली पंजाब सरकार की प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता की। एक बयान में कहा गया कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने मंत्रियों एवं अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। बता दें कि आम चुनाव के बाद नवाज का चौथी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत पाने में विफल रही। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) समेत पांच अन्य पार्टियों की सहायता से बनी गठबंधन सरकार की अगुआई नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ कर रहे हैं।

बेनजीर की छोटी बेटी आसिफा राजनीति के मैदान में उतरीं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की दिवंगत पीएम बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी 31 वर्षीया आसिफा भुट्टो ने संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रख दिया है। वह अपने पिता और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा सिंध प्रांत में खाली की गई नेशनल असेंबली की सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में उतरी हैं। आसिफा ने सिंध प्रांत के शहीद बेनजीराबाद जिले के एनए-207 निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव में रविवार को नामांकन पत्र भरा। इस सीट के लिए 21 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। आसिफा की मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह 1988 से 1990 तक 11वीं और 1993 से 1996 तक 13वीं प्रधानमंत्री रहीं। 2007 में रावलपिंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। 2008 से 2013 तक जरदारी देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। आसिफा के भाई 35 वर्षीय बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पिता जरदारी सह-अध्यक्ष हैं।

न्यूज गैलरी

नेपाल में हथियार के साथ दो भारतीय गिरफ्तार

काठमांडू : नेपाल के सरलाही में हथियारों के साथ दो भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। संदिग्धों की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी जितेंद्र राउत और शानी सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गोलियां चलाईं जिसमें राउत घायल हो गया। राउत को मलंगवा में प्रांतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों भारत में अपहरण और लूटपाट की एक दर्जन घटनाओं में वांछित हैं। (प्रेट्र)

सिंगापुर में भारतवंशी नेता पर झूठ बोलने का लगा आरोप

सिंगापुर : सिंगापुर में नेता प्रतिपक्ष व भारतवंशी प्रीतम सिंह पर मंगलवार को संसदीय समिति के सामने शपथ के तहत झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। वर्कर्स पार्टी के महासचिव प्रीतम पर पूर्व सांसद रईस खान से संबंधित विशेषाधिकार समिति की सुनवाई में झूठी गवाही देने का आरोप है। दोष सिद्ध होने पर प्रीतम को तीन वर्ष जेल या प्रति आरोप 7000 सिंगापुरी डालर तक जुर्माना किया जा सकता है। (प्रेट्र)

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी का निर्देश

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपने मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे द्वीप देश में इसी वर्ष राष्ट्रपति चुनाव कराया जाना है। चुनाव आयोग सितंबर तक चुनाव की घोषणा करेगा और मध्य नवंबर तक मतदान कराया जाएगा। 2025 तक संसदीय चुनाव की जरूरत नहीं है, पर राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के पास 225 सदस्यीय असेंबली किसी भी समय भंग कर चुनाव कराने की शक्ति है। (प्रेट्र)

नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 87 लोगों का अपहरण किया

अबुजा : नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 87 लोगों का अपहरण कर लिया है। हाल ही में हमलावरों ने एक स्कूल से 286 छात्रों और कर्मचारियों को पकड़ लिया था। अधिकारियों के अनुसार, नया हमला कडुना प्रांत के कजुरु क्षेत्र में हुआ है। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नाइजीरिया में आए दिन बंदूकधारी गांवों में लूटपाट और फिरौती के लिए सामूहिक अपहरण करते हैं। (एएनआइ)

हैती में हालात बेकाबू, हमलों में 12 से अधिक की मौत

- प्रधानमंत्री हेनरी के इस्तीफे की मांग को लेकर की जा रही हिंसा
- हथियारबंद गिरोह कर रहे लूटपाट, लोग घर छोड़ने को मजबूर

हैती की राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस में हथियारबंद गिरोहों के हमले में स्वजन की मृत्यु पर शोकाकुल लोग। एएफपी

पोर्ट-औ-प्रिंस, एपी: हैती में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हथियारबंद गिरोहों ने सोमवार तड़के हैती की राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस के दो संपन्न इलाकों में हमले कर दिए। बंदूकधारियों ने पहले लाबूले व थोमासिन इलाकों में घरों में लूटपाट की। हमलों के कारण लोगों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कुछ लोग रेडियो पर पुलिस से मदद की गुहार लगाते नजर आए। हमलों में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लोगों के शव सड़कों पर पड़े थे और उनके आसपास भीड़ जुट रही थी।

गत 29 फरवरी से पोर्ट-औ-प्रिंस में पीएम एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग को लेकर हथियाबंद गिरोहों ने हमले शुरू कर दिए थे। गिरोहों का कहना है कि हेनरी को लोगों ने नहीं चुना है। वे उन्हें बढ़ती गरीबी के लिए दोषी मानते हैं। हेनरी ने संक्रमणकालीन परिषद बनाने के बाद पद छोड़ने का ऐलान किया था पर गिरोह हिंसा जारी रखे हैं। इधर, सोमवार को हैती की बिजली कंपनी ने घोषणा की कि उनके चार उपकेंद्र तबाह हो गए और अब काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पोर्ट-औ-प्रिंस में कहीं भी बिजली नहीं थी। इधर, सरकार ने कहा, रातकालीन कर्फ्यू को 2

स्वीडन में हमले की साजिश रचने में जर्मनी की पुलिस ने अफगानियों को पकड़ा

बर्लिन, एपी: जर्मन पुलिस ने मंगलवार को कुरान की प्रतियां जलाने के विरोध में स्वीडिश संसद के निकट हमला करने की साजिश रचने के आरोप में दो अफगान नागरिकों को हिरासत में ले लिया। ज्ञात हो, इस्लाम विरोधियों ने स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाई थीं। इससे दुनिया भर के मुस्लिमों में आक्रोश फैल गया था।

संघीय अभियोजक कार्यालय ने बताया कि गेरा के पूर्वी शहर में हिरासत में लिए गए संदिग्धों की पहचान इब्राहिम एमजी और रमिन एन. के रूप में की गई। जर्मन गोपनीयता कानूनों के अनुसार, पुरुषों की पहचान केवल उनके प्रारंभिक नाम से की गई। आइएस समूह के सहयोगी ने संदिग्धों को गत वर्ष स्वीडन व अन्य देशों में कुरान की प्रतियां जलाने के विरोध में यूरोप में हमले करने का काम सौंपा था। ये दोनों स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में संसद के निकट पुलिस और अन्य लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसमें घटनास्थल का आनलाइन शोध और हथियारों को खरीदने की अफसल कोशिश भी शामिल थी।

रूस की जब्त की गई संपत्ति से यूक्रेन की मदद करना चाहता हैं यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस योजना के लिए दी हरी झंडी
- यूक्रेन का सहयोग करने पर रूसी सैनिकों के निशाने पर फ्रांसीसी सेना

ब्रुसेल्स, एपी: रुस-यूक्रेन जंग के बीच यूरोपीय संघ यूरोप में जब्त की गई रूसी संपत्ति से यूक्रेन को हथियार और धन उपलब्ध कराने की योजना पर जोर दे रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल को इस सप्ताह अधिकांश सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से योजना के लिए हरी झंडी मिल गई है। उन्हें उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार से ब्रुसेल्स में शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन करेंगे। यह कदम तब उठाया गया है जब यूक्रेन में युद्ध सामग्री की बेहद कमी हो गई है। अमेरिका भी हथियारों के लिए धन उपलब्ध कराने से हाथ खड़ा कर दिया है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के पास रूसी केंद्रीय बैंक की लगभग 21 हजार करोड़ अमेरिकी डालर की संपत्ति हैं। इसमें से अधिकांश यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध के खिलाफ बेल्जियम में जमा हैं। यूरोपीय संघ का अनुमान है कि उस पैसे पर हर साल लगभग 330 करोड़ अमेरिकी डालर ब्याज मिलता है। बोरेल ने संवाददाताओं से कहा कि यह राशि बहुत अधिक नहीं है लेकिन कम भी नहीं है।

रुस की सीमा से 9,000 बच्चों को निकालने की योजना : वहीं, रुस के एक अधिकारी ने कहा कि रुस की सीमा पर यूक्रेन की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। रूसी सीमा क्षेत्र से लगभग 9,000 बच्चों को निकालने की योजना है। कीव की सेना तेजी से हमले कर रही हैं। रूस के बेलगोरोड सीमा क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लेव ग्लैडकोव ने कहा कि बच्चों को यूक्रेन सीमा से दूर पूर्व की ओर ले जाया जाएगा। इसके साथ ही टीएएसएस समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारीश्किन ने मंगलवार को कहा कि रूस से लड़ने में मदद के लिए यूक्रेन भेजी गई कोई भी फ्रांसीसी सेना रूसी सैनिकों के निशाने पर होंगे।

पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को तोड़ने का आह्वान किया

वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को सोवियत काल से स्थापित केजीबी के मुख्य उत्तराधिकारी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) से कहा कि वह रूसी कंपनियों को पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़ने और दुनिया भर के नए बाजारों में अपना दबदबा बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने एफएसबी अधिकारियों से कहा कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और वित्तीय संकट पैदा करने के लिए हथियारों का भी उपयोग कर रहे हैं।

'चरमपंथियों-आतंकवादियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय बताएं'

सिडनी, एपी: आस्ट्रेलिया की आनलाइन सुरक्षा नियामक ने मंगलवार को गूगल, मेटा, एक्स, वाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया दिग्गजों को नोटिस जारी किया है। इंटरनेट मीडिया दिग्गजों से लोगों को हिंसक चरमपंथियों-आतंकवादियों से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने को कहा गया है। कंपनियों को जवाब देने के लिए 49 दिन का समय दिया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कंपनियों पर 5.10 लाख डालर (4.23 करोड़ रुपये) प्रतिदिन का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।

आस्ट्रेलिया की ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट ने कहा, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे चरमपंथी बेहद हानिकारक सामग्री को बढ़ावा और साझा करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग, एल्गोरिदम व अन्य सुविधाओं जैसी तकनीक को हथियार बनाते हैं। आस्ट्रेलिया व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और आनलाइन कट्टरपंथ का उच्च खतरा बना हुआ है। इसीलिए हमने यह कदम उठाया है।

ब्रिटिश पीएम से मिलने पहुंचे ओबामा, एआइ समेत कई मुद्दों पर चर्चा

- माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच पहली बार मुलाकात हुई है

ऋषि सुनक बराक ओबामा

लंदन, प्रेट्र: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सोमवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने के लिए अचानक उनके आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने पहली बार मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। बयान में आगे कहा कि दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की।

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री सुनक ने सोमवार की दोपहर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अनौपचारिक बैठक के लिए स्वागत किया। प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति अपने फाउंडेशन के काम से लंदन आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री सुनक के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों और एआइ समेत कई मुद्दों पर बातचीत की।

तकरीबन एक घंटे तक रुकने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ब्रिटेन में अमेरिका के राजदूत जेन हार्टले के साथ बाहर निकले। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन के दोबारा रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के पत्रकारों के सवाल पर वह कुछ नहीं बोले। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा आखिरी बार अप्रैल 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और अब विदेश मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए थे।

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर लगाया गया पहला अभियोग

साओ पाउलो, एपी: ब्राजील की संघीय पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर मंगलवार को अपने स्वयं के कोविड-19 टीकाकरण आंकड़ों को गलत साबित करने का आरोप लगाया है। घोर दक्षिणपंथी नेता पर यह पहला अभियोग है और अब उनके खिलाफ और मामले दर्ज होने की आशंका है। महामारी के दौरान बोल्सोनारो वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठाने वाले दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शामिल थे। उन्होंने स्वास्थ्य प्रतिबंधों का खुलेआम उल्लंघन किया और लोगों को नियमों का नहीं मानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने साओ पाउलो राज्य के गवर्नर द्वारा चीनी कंपनी सिनोवैक से टीके की खरीद की भी आलोचना की थी।

अभियोग में आरोप लगाए गए है कि बोल्सोनारो व 16 अन्य ने सार्वजनिक स्वास्थ्य डाटाबेस में गलत जानकारी डाली। इससे यह लगे कि तत्कालीन राष्ट्रपति, उनकी 12 वर्षीय बेटी और उनके परिचित कई अन्य लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है।

अब अमेरिकी सीनेटर बेन कार्डिन ने सीएए लागू होने पर जताई चिंता

- कहा, सभी के मानवाधिकारों की रक्षा साझा मूल्यों पर आधारित हो
- भारत कह चुका है कि गलत जानकारी पर आधारित हैं ऐसी प्रतिक्रियाएं

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर बेन कार्डिन ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत के संबंध जैसे-जैसे गहरा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि सभी के मानवाधिकारों की रक्षा साझा मूल्यों पर आधारित हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। हालांकि, भारत सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सीएए से किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गलत जानकारी के आधार पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले सप्ताह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

शक्तिशाली सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा कि मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से बहुत चिंतित हूं। विशेष रूप से भारत के मुस्लिम समुदाय पर कानून के संभावित प्रभाव को लेकर। पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी करने पर चिंता जताई थी। कहा था कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए। हालांकि भारत ने अमेरिकी प्रतिक्रिया का तत्काल जवाब दिया था। भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से सीएए के बारे में की गई टिप्पणी गलत जानकारी पर आधारित है और अनुचित है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण बुधवार 20 मार्च, 2024
स्पोर्ट्स
12 www.jagran.com

❛ बुमराह को आराम की आवश्यकता है क्योंकि वह हर गेंद में बहुत प्रयास करता है। अगर वह खेलना जारी रखता है, तो उसके एक्शन से दबाव बनता है, उससे उसका चोटिल होना तय है।
— ग्लेन मैक्ग्रा, पूर्व गेंदबाज, आस्ट्रेलिया

विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंचे लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के लक्ष्य सेन मंगलवार को पांच स्थान की छलांग लगाकर बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य पिछले सप्ताह आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में हुआ। पेरिस ओलिंपिक में अप्रैल तक रैंकिंग में 16 शीर्ष खिलाड़ियों को कट मिलेगा। भारत के एचएस प्रणय नौवें स्थान पर हैं और वह भी ओलिंपिक कट प्राप्त करने की दौड़ में बने हुए हैं।

आरसीबी, दिल्ली और पंजाब... क्या खत्म कर पाएंगे 16 साल का इंतजार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: आइपीएल के 17वें सत्र की शुरुआत शुक्रवार से होगी। पिछले 16 वर्षों में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स पांच-पांच बार ट्राफी जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें हैं। लेकिन तीन टीमें ऐसी हैं, जो लीग में 2008 की शुरुआत से ही जुड़ी हैं, लेकिन एक बार भी ट्राफी उनके हाथ नहीं आ पाई है। आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को अब तक अपनी पहली ट्राफी का इंतजार है। तीनों ही टीमें फाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन चैंपियन नहीं बन पाईं। आरसीबी आगामी सत्र में अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के विरुद्ध करेगी, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम शनिवार को पंजाब किंग्स से उसके घर पर टकराएगी।

पंत की वापसी से दिल्ली को मिलेगी मजबूती

रिकी पोंटिंग के कोच बनने के बाद दिल्ली की टीम 2019 से लगातार तीन बार प्लेआफ में पहुंची। 2020 में टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई, लेकिन मुंबई के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी। 2021 में 14 में से 10 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रही, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल में नहीं पहुंच सकी। लेकिन पिछले सत्र में टीम का प्रदर्शन बेहद औसत रहा था। नौवें स्थान पर रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर रिषभ पंत की कप्तानी में दम दिखाने उतरेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कप्तान के रूप में पंत के नाम की घोषणा की। टीम के सह मालिक पार्थ जिंदल ने कहा, हमें कप्तान के रूप में रिषभ का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं उनकी कप्तानी में टीम को खेलते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि हम नए जोश और उत्साह के साथ नए सत्र का स्वागत कर रहे हैं। पंत पिछले वर्ष कार हादसे के कारण आइपीएल में नहीं खेल पाए थे। बाएं हाथ के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज की मौजूदगी से निश्चित रूप से टीम को मजबूती मिलेगी। इस बार दिल्ली ने कई युवाओं को टीम में शामिल किया है। अनकैप्ड खिलाड़ियों में कुमार कुशाग्र, सुमित कुमार, स्वास्तिक चिकारा पर दांव लगाया है। वहीं इस बार ट्रिस्टन स्टब्स और साई होप जैसे विदेशी खिलाड़ी भी टीम में हैं।

रिषभ पंत ●

इस बार किस्मत बदलने की कोशिश करेगी आरसीबी

तीन दिन पहले ही डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत चुकी आरसीबी फ्रेंचाइजी अब आइपीएल में खिताबी सूखा खत्म करने के इरादे से उतरेगी। आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है, जो तीन बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद एक भी बार ट्राफी नहीं जीत पाई है। आरसीबी के पास टी-20 प्रारूप के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद उसे खिताब का इंतजार रहा। 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए टूर्नामेंट में टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन डेक्कन चार्जर्स से उसे हार मिली। इसके बाद 2011 और 2016 में भी टीम ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया, लेकिन दोनों बार ट्राफी उसके हाथ से फिसल गई। पिछले साल टीम ने पांचवें स्थान पर रहकर अभियान समाप्त किया था। विराट कोहली 2008 से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं और उसके सबसे बड़े मैच विनर हैं। कोहली के अलावा मैक्सवेल, कप्तान फाफ डु प्लेसिस जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी इस टीम का हमेशा ही कमजोर पक्ष रहा है, लेकिन इस बार हुई मिनी नीलामी में टीम ने मैच विजेता गेंदबाजों पर दांव लगाया। सिराज का साथ देने के लिए अल्जारी जोसेफ, फर्ग्युसन और टाम कुर्रन और यश दयाल टीम में है। वहीं, आरसीबी ने मुंबई से आस्ट्रेलियाई आलराउंडर कैमरन ग्रीन को ट्रेड किया, जो उसके लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं।

विराट कोहली ● प्रेट्र »

❛ महिला टीम ने डब्ल्यूपीएल खिताब जीता। आशा है कि हम भी इस वर्ष आरसीबी के लिए ट्राफी जीतेंगे। यह बहुत विशेष होगा। यह जानना मेरा सपना है कि ट्राफी जीतने पर कैसा महसूस होता है। मैं यहां रहूंगा और उस टीम का हिस्सा बनूंगा, जो पहली बार ट्राफी जीतेगी। - **विराट**

पंजाब किंग्स को 'शिखर' पर लेकर जाएंगे धवन

पंजाब किंग्स की टीम 2008, 2010 में प्लेआफ में पहुंची, जबकि 2014 में उपविजेता रही। हालांकि इन तीन सत्रों को छोड़ दें तो आइपीएल में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। यह एक ऐसी टीम है, जिसने खिलाड़ियों का कोर ग्रुप नहीं बनाया। टीम प्रबंधन हर साल खराब प्रदर्शन के बाद कोच के साथ कप्तान की भी छुट्टी कर देता है। युवराज सिंह, एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग, जार्ज बेली, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल जैसे दिग्गजों को टीम ने कप्तानी सौंपी, लेकिन कोई भी उसे खिताब नहीं दिला सका। पिछले सत्र में शिखर धवन की कप्तानी में टीम आठवें स्थान पर रही थी। अब टीम एक बार फिर कप्तान धवन की अगुआई में शिखर पर पहुंचने उतरेगी। टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है और इस बार जानी बेयरस्टो पूरा सत्र खेलेंगे, ये उसके लिए अच्छी खबर है। टीम की गेंदबाजी उसका मजबूत पक्ष है। अर्शदीप सिंह, कैगिसो रबादा, नाथन एलिस जैसे तेज गेंदबाज हैं, तो राहुल चाहर और हरप्रीत बरार जैसे युवा स्पिनर हैं।

डब्ल्यूपीएल विजेता टीम को दिया गया गार्ड आफ आनर

आरसीबी की जर्सी लांच करतीं स्मृति मंधाना साथ में कप्तान डुप्लेसिस। ● प्रेट्र

नई दिल्ली, जेएनएन : डब्ल्यूपीएल का खिताब जीतने वाली आरसीबी की महिला टीम को मंगलवार को विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस समेत पुरुष टीम के खिलाड़ियों ने ने गार्ड आफ आनर दिया। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की महिला टीम ट्राफी के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची थी, जहां आइपीएल की तैयारी में जुटी पुरुष टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शाम को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की नई जर्सी और लोगो का अनावरण किया गया। इसके साथ ही अब टीम का नाम रायल चैलेंजर्स बैंगलोर से बदलकर रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर दिया गया। स्मृति मंधाना, विराट कोहली और डु प्लेसिस ने रंगारंग कार्यक्रम में टीम की नई जर्सी लांच की, जिसमें इस बार लाल के साथ नीला रंग भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर रघु दीक्षित, नीती मोहन, ब्रोथा वी जैसे कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आरसीबी के पूर्व तेज गेंदबाज आर विनय कुमार और एबी डिविलियर्स व क्रिस गेल के बाद आरसीबी हाल आफ फेम में शामिल किया गया। विनय कुमार आरसीबी की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

एक नजर में

ससेक्स से काउंटी क्रिकेट खेलेंगे जयदेव उनादकट

होव : भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट इस साल काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लैंड के क्लब ससेक्स की तरफ से अंतिम पांच मैचों में खेलेंगे। भारत की तरफ से चार टेस्ट खेलने वाले 32 वर्षीय उनादकट ने पिछले सत्र में ससेक्स की तरफ से काउंटी चैंपियनशिप में चार मैच में 11 विकेट लिए थे। उनकी टीम तब डिवीजन दो में तीसरे स्थान पर रही थी। उनादकट ने भारत की ओर से अपना अंतिम मैच पिछले साल वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट मैच के रूप में खेला था। सौराष्ट्र ने 2019-20 में उनादकट की अगुवाई में रणजी ट्राफी खिताब जीता था। उनादकट काउंटी चैंपियनशिप में खेलने से पहले आइपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलेंगे। (प्रेट्र)

क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए शाटगन टीम चयनित

नई दिल्ली : राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह, अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान और विश्व कप विजेता गनेमत सेखों को पेरिस ओलिंपिक के लिए दोहा में 19 से 29 अप्रैल तक होने वाले अंतिम क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मंगलवार को चुनी 12 सदस्यीय शाटगन टीम में चुना गया। दोहा में होने वाली इस प्रतियोगिता में चार कोटा दांव पर लगे होंगे। पुरुष ट्रैप में पृथ्वीराज टोंडाईमान, जोरावर संधू और विवान कपूर जबकि महिला ट्रैप के लिए श्रेयसी और मनीषा कीर तथा मेराज और शीराज शेख पुरुष स्कीट और गनेमत और महेश्वरी चौहान महिला स्कीट में शामिल होने वाले नियमित निशानेबाज हैं। (प्रेट्र)

सतीश कुमार मुख्य ड्रा में

बासेल : भारत के सतीश कुमार करुणाकर ने मंगवालर को पहले दो पुरुष सिंगल्स क्वालीफायर मैच जीतकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जगह बनाई। सतीश कुमार ने पहले क्वालीफिकेशन मैच में यूरियल फ्रांसिस्को कांजुरा अर्टिगा को 21-18 21-12 से हराया और फिर कोरिया के जोएन हयोक जी को पराजित किया। अनुभवी समीर वर्मा ने चौथे वरीय ब्राजील के यगोर कोएलो को 11-21 21-10 21-14 से मात दी, लेकिन वह अगले मैच में अल्वी फरहान से हार गए। (प्रेट्र)

फिटनेस टेस्ट में फेल सूर्यकुमार

मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे, गुरुवार को फिर होगा टेस्ट

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई इंडियंस को आइपीएल शुरू होने से पहले एक और झटका लगा है। दुनिया के नंबर एक टी-20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिससे फिलहाल राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से उन्हें आइपीएल में खेलने की हरी झंडी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि यह विस्फोटक बल्लेबाज पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की ओर से शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएगा। मुंबई अपने अभियान की शुरुआत रविवार को गुजरात टाइटंस के विरुद्ध करेगी। माना जा रहा है कि सूर्य दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध एक अप्रैल को होने वाले मैच से बाहर रह सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद एनसीए में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मंगलवार को उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसमें वह फेल हो गए। गुरुवार को उनका फिर से फिटनेस टेस्ट होगा और अगर वह पास होते हैं तो तभी वह आइपीएल में खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टखने की चोट के बाद से सूर्यकुमार क्रिकेट से दूर हैं। जनवरी में उन्होंने जर्मनी में टखने की सर्जरी कराई थी। एक दिन पहले मुंबई के कोच मार्क बाउचर ने भी कहा था कि टीम प्रबंधन को अब तक सूर्य की फिटनेस को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है।

मुंबई की टीम इस समय वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। इससे पहले, आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन बेहरनडार्फ चोट के कारण आइपीएल से हट गए थे, जिसके बाद मुंबई ने इंग्लैंड के गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम में शामिल किया था।

सूर्यकुमार यादव ● फाइल फोटो, प्रेट्र

हसरंगा टेस्ट से निलंबित, आइपीएल में खेलेंगे

दुबई : आइसीसी ने श्रीलंकाई आलराउंडर वानिंदु हसरंगा को बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद वह आइपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उपलब्ध रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने हसारंगा को 1.5 करोड़ रुपये में उनके आधार मूल्य में खरीदा था। हसरंगा को श्रीलंकाई टीम में चुना गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि वह आइपीएल के शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। हसरंगा को आइसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 के उल्लघंन का दोषी पाया गया जो एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायरों के फैसले के प्रति नाराजगी दिखाने से संबंधित है। उन पर दो टेस्ट मैचों से निलंबित किया गया है।

रोहित शर्मा ने हार्दिक और बुमराह का बहुत समर्थन किया : पार्थिव पटेल

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने कहा कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जब संघर्ष कर रहे थे तब रोहित शर्मा ने उनका पूरा समर्थन किया था। पार्थिव ने रोहित के नेतृत्व कौशल की तुलना सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी से करते हुए कहा कि शर्मा ने कभी कोई गलती नहीं की जबकि धौनी ने अपने लंबे करियर के दौरान कुछ गलतियां की। पार्थिव ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहित ने हमेशा अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया।

विनेश और साक्षी ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को खेलों से बाहर करने का आग्रह करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) को प्रशासनिक अधिकार सौंपने के लिए आइओए की कड़ी निंदा की। इन दोनों पहलवानों ने 'एक्स' पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। आइओए ने तदर्थ समिति भंग कर डब्ल्यूएफआइ को देश में कुश्ती की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी।

विनेश फोगाट ने लिखा, प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं, अपने प्रतिद्वंद्वियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। आप महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती महासंघ पर काबिज हो गया है। उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। साक्षी ने लिखा, बृजभूषण व संजय सिंह लगातार ये बयान देते रहे कि ये निलंबन सिफ एक दिखावा है, कुछ दिन बाद हम बहाल हो जाएंगे। ये बात सच साबित हुई।

आइपीएल में स्मार्ट रीप्ले प्रणाली से सटीक निर्णय लेंगे टीवी अंपायर

बीसीसीआइ शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र से नए सिस्टम को करेगा पेश, मैदान में लगे आठ हाकआइ कैमरों से लेंगे मदद

नई दिल्ली, जेएनएन : चेन्नई सुपरकिंग्स और आरसीबी के बीच भिड़ंत से शुक्रवार से शुरू होने वाले आगामी आइपीएल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) स्मार्ट रीप्ले प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिससे टीवी अंपायरों को जल्दी और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। स्मार्ट रीप्ले सिस्टम टीवी अंपायरों को पहले से ज्यादा विजुअल उपलब्ध कराएगा। टीवी अंपायरों को दो हाकआइ आपरेटरों से सीधे इनपुट मिलेगा, जो उसी कक्ष में बैठे होंगे, जिसमें अंपायर मौजूद रहेंगे। ये आपरेटर उन्हें पूरे मैदान में लगे आठ हाकआइ हाई स्पीड कैमरों की तस्वीरें उपलब्ध कराएंगे।

इस नए सिस्टम में टीवी प्रसारण निदेशक की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, जो पहले तीसरे अंपायर और हाकआइ आपरेटरों के बीच संपर्क का काम करते थे। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक मैच में आठ हाकआइ कैमरे मौजूद रहेंगे। इनमें से दो स्क्वायर लेग और पिच के दोनों तरफ दो-दो और सामने की तरफ बाउंड्री पर दो कैमरे होंगे। 2023 आइपीएल से पहले हाकआइ के लिए बाल ट्रैकिंग और अल्ट्रा एज का इस्तेमाल किया जाता था।

हाकआइ कैमरा ● फाइल फोटो, एक्स

लिहाजा मैदानी अंपायर द्वारा किसी भी रेफरल के लिए प्रसारणकर्ता अपने कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल करता था।

इसमें एलबीडब्ल्यू और एज लगना शामिल नहीं होता था, लेकिन नए रिप्ले सिस्टम में स्टंपिंग, कैच, ओवरथ्रो, रनआउट सभी को शामिल किया गया है। जैसे अगर स्टंपिंग का रेफरल मांगा गया तो टीवी अंपायर हाकआइ आपरेटर से स्प्लिट स्क्रीन दिखाने का अनुरोध करेंगे। नई तकनीक टीवी अंपायर को स्टंपिंग की तीन तस्वीरें दिखाएगी, जो आनसाइड और फ्रंट आन कैमरों का सिंगल फ्रेम होगा।

एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट खेलेगा भारत

क्रिकेट डायरी

मेलबर्न, प्रेट्र : भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इस वर्ष के अंत में होने वाली पांच टेस्ट मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज के बाकी मैच एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार. एडिलेड में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट डे-नाइट होगा। इससे पहले, भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 2020 में डे-नाइट टेस्ट इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें आस्ट्रेलिया आठ विकेट से जीता था। भारत ने अपना अंतिम डे-नाइट टेस्ट मैच मार्च 2022 में श्रीलंका के विरुद्ध बेंगलुरु में खेला था।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी ब्रिस्बेन करेगा। बाक्सिंग डे टेस्ट हर बार की तरह मेलबर्न में खेला जाएगा, जबकि नए साल पर दोनों टीम सिडनी में अंतिम मैच खेलेगी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस महीने के अंत में अगले सत्र का कार्यक्रम जारी करेगा। यह 1991-92 के बाद पहला अवसर होगा जबकि भारतीय टीम आस्ट्रेलिया में पांच टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इससे पहले 1991-92 में भारतीय टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने जब 2018-19 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तब पर्थ में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। 2020-21 में खेली गई सीरीज से पहले पर्थ को एक भी मैच की मेजबानी नहीं दी गई थी।

टेस्ट सीरीज का संभावित कार्यक्रम

पहला टेस्ट	पर्थ
दूसरा टेस्ट	एडिलेड (डे-नाइट)
तीसरा टेस्ट	ब्रिस्बेन
चौथा टेस्ट	मेलबर्न
पांचवां टेस्ट	सिड्नी

आस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के विरुद्ध टी-20 सीरीज स्थगित की : आस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में महिलाओं की खराब स्थिति का हवाला देते हुए इस साल अगस्त में अफगान टीम के विरुद्ध होने वाली टी-20 सीरीज स्थगित कर दी है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया का सीरीज स्थगित करने का अर्थ है कि उसने अफगानिस्तान को लेकर अपना कड़ा रवैया जारी रखा है। आस्ट्रेलिया ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के साथ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच को भी रद कर दिया था।

पंकज आडवाणी बिलियड्र्स हाल आफ फेम में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने चमकदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की जब उन्हें चीन के शंगराओ सिटी में विश्व बिलियड्र्स संग्रहालय में 'हाल आफ फेम' में शामिल किया गया। पिछले साल नवंबर में 38 साल के भारतीय स्टार आडवाणी ने हमवतन सौरव कोठारी को हराकर 26वां आइबीएसएफ खिताब जीता था। आडवाणी ने कहा कि मैं हाल आफ फेम में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस शानदार यात्रा के दौरान मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है, वो अद्भुत रहा है।

पंकज आडवाणी ●

मियामी ओपन में पदार्पण मैच में जीते नागल

खेल डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मियामी ओपन में अपने पदार्पण मैच में कनाडा के गैब्रियल डायलो को सीधे सेटों में हराकर शानदार शुरुआत की। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने गजब का धैर्य और जज्बा दिखाया तथा क्वालीफायर के पहले दौर में डायलो को 7-6(3) 6-2 से पराजित किया।

पिछले महीने चेन्नई ओपन की जीत के बाद विश्व के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले नागल अगले दौर में कोलमैन वोंग का सामना करेंगे। नागल ने पहले सेट को टाई ब्रेकर में जीतने के बाद दूसरे सेट में दबदबा बनाए रखा। उन्होंने इस सेट के पहले और सातवें गेम में डायलो की सर्विस तोड़ी। इस जीत से नागल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 92वीं रैंकिंग पर पहुंच सकते हैं। नागल ने राफेल नडाल के अंतिम अवसर पर हटने के कारण अपने पिछले टूर्नामेंट इंडियन वेल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी लेकिन तब वह पहले दौर में मिलोस राओनिक से हार गए थे। इस भारतीय खिलाड़ी ने जनवरी में आस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में भी जगह बनाई थी। अपने इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाने में मदद मिली थी।

प्रदर्शन करते नागल ● फाइल फोटो, एक्स

चोट के कारण मैत्री मैच नहीं खेल पाएंगे मेसी

ब्यूनस आयर्स : अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी दाहिने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अमेरिका में इस महीने होने वाले दो मैत्री मैचों में नहीं खेल पाएंगे। अर्जेंटीना फुटबाल संघ ने बताया कि मेसी पिछले सप्ताह इंटर मियामी की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए थे। अर्जेंटीना को शुक्रवार को फिलाडेल्फिया में अल सल्वाडोर के विरुद्ध मैच खेलना है जबकि इसके चार दिन बाद वह लास एंजिल्स में कोस्टा रिका का सामना करेगा। 36 वर्षीय मेसी इन दोनों मैच में नहीं खेल पाएंगे। मेसी के अलावा अर्जेंटीना के स्ट्राइकर पाउलो डायबाला और मिडफील्डर एक्सक्विल पलासियोस भी चोटिल होने के कारण इन मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

राष्ट्रीय फलक

आरएसएस नेता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपित शफीक गिरफ्तार

पीएफआइ के कार्यकर्ता को एनआइए ने केरल से दबोचा, मामले में एनआइए ने अब तक दो चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, एनआइए : एनआइए ने केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में शामिल मुख्य आरोपित शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वह प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) से जुड़ा हुआ था। एनआइए ने मंगलवार को बताया गया कि मल्लपुरम निवासी शफीक को कोल्लम जिले से सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पलक्कड़ में 16 अप्रैल 2022 को आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी और तभी से शफीक फरार था। शफीक ने हत्यारोपी अशरफ केपी को शरण दी थी।

श्रीनिवासन की हत्या में 71 आरोपित शामिल हैं। मामले में एनआइए दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पहली चार्जशीट 17 मार्च 2023 और दूसरी छह नवंबर 2023 को दाखिल की गई थी। एक आरोपित अब्दुल नसीर की पिछले साल जनवरी में मौत हो चुकी है। दो भगोड़े अब्दुल नसीर को पिछले साल अक्टूबर और साहिर केवी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। साहिर पीएफआइ का सक्रिय सदस्य है। वह हिंदुओं में दहशत फैलाने और 2047 तक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के पीएफआइ के नापाक एजेंडे के तहत काम कर रहा था। आरोप यह भी है कि साहिर मामले के मुख्य आरोपितों को संरक्षण भी दे रहा था।

बाथरूम में नाबालिग ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म, दरवाजा पीटती रही बच्ची की मां

नईदुनिया, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या का मामला सामने आया है। आरोपित 15 वर्षीय नाबालिग है जो बच्ची को लेकर बाथरूम में घुस गया और हैवानियत की। बच्ची की मां दरवाजा पीटती रही, लेकिन आरोपित ने नहीं खोला। नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही बच्ची को अस्पताल लेकर जाने के बजाय छोड़कर भागने वाले आरोपित के चाचा को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपित ने बच्ची की आवाज दबाने के लिए मुंह और नाक को बंद कर दिया था। इससे दम घुटने के कारण बच्ची की मौत हो गई। आरोपित ने चेहरे पर काटा भी था।

जिले के सरगांव क्षेत्र में एक ड्राइवर किराए के मकान में रहते हैं। रविवार रात वह ड्यूटी पर गए थे। पत्नी व तीन साल की बेटी घर में थे। शाम को बेटी नहीं दिखी तो मां ने तलाश की। पता चला कि बच्ची पड़ोस में ही रहने वाले 15 साल के किशोर के साथ खेल रही थी। तभी किसी ने बताया कि किशोर बच्ची को लेकर बाथरूम की ओर गया है। बाथरूम बंद होने के कारण महिला ने बाहर से आवाज दी और दरवाजा पीटती रही। तब तक आरोपित के स्वजन और आसपास के लोग भी वहां पर आ गए। बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर किशोर और बच्ची बेहोश पड़ी थी। आरोपित का चाचा बच्ची व उसकी मां को अस्पताल ले जाने की बात कहकर निकला। वह मां-बेटी को लेकर मगरपारा चौक तक गया। वहां पर दोनों को छोड़कर भाग गया। महिला बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपित के मकान पर किया पथराव

तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी लगने पर मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। रात को ही कुछ लोगों ने आरोपित के मकान में पथराव किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह भीड़ को नियंत्रित किया।

लखनऊ में कर विभाग के उपायुक्त दो लाख की घूस लेते गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार शाम लखनऊ में उप्र के कर विभाग के उपायुक्त धर्नेंद्र कुमार पांडेय को जीएसटी मुख्यालय में निर्यात कंपनी का 20 लाख रुपये का जीएसटी रिफंड पास करने के बदले दो लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ।

डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण के अनुसार रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर निर्यात कंपनी आर्डेम डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने धर्नेंद्र पांडेय की शिकायत की थी। एसपी विजिलेंस डा.अरविंद चतुर्वेदी ने मामले की जांच की और शिकायतकर्ता को बुलाकर पूछताछ की। सामने आया कि केंद्र सरकार ने निर्यातकों को जीएसटी में विशेष छूट देने की व्यवस्था की है। यदि कोई फर्म निर्यात के लिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के क्रय पर अलग-अलग दरों से जीएसटी का भुगतान करती है तो संबंधित फर्म जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकती है।

आर्डेम डेटा सर्विसेज कई वर्षों से अमेरिका की कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कैंड डाटा शीट्स को डैशबोर्ड में डिजिटल फार्म में तैयार कर वापस भेजती है। कंपनी ने इनमें दिए गए जीएसटी के आधार पर लगभग 20 लाख रुपये का रिफंड क्लेम किया था। इसे पास करने के बदले दो लाख रुपये घूस देने का दबाव बनाया जा रहा था।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार, 20 मार्च, 2024

होली के रंगों में सबसे सुंदर रंग है उल्लास और उमंग का। यह रंग और निखर सकता है यदि आप होली खेलने के पूर्व सेहत से जुड़ी सावधानी भी रखें। आइए जानें, रंग खेलने से लेकर खानपान तक किन बातों का रखें ध्यान...

होली विशेष

सुरक्षा और सतर्कता भरी हो होली

जीवनशैली

डा. जुगल किशोर
जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली

जीवन का उल्लास अच्छी सेहत के बगैर अकल्पनीय है। इस उल्लास में जब होली जैसे अवसर जुड़ते हैं, तो अच्छी सेहत का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे मौकों पर खानपान में थोड़ी अनियमितता सेहत के लिए परेशानी बन सकती है। अगर किसी को मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्या है, तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। अभी खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, यह सोच या प्रवृत्ति सही नहीं है। सजगता से होली नहीं खेलने पर त्वचा व आंख से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। प्रयास करें कि हानिकारक रंगों से बचें और सजग रहें ताकि सेहत को लेकर जोखिम उत्पन्न न हो।

रंग में न करें भंग : होली के दौरान अल्कोहल, गांजा व भांग का धड़ल्ले से प्रयोग होता है। भांग को सामान्य चीज मान लिया गया है, पर खतरा इसके साथ भी है। जो लोग किसी मानसिक समस्या की दवा ले रहे हैं, उनके लिए यह बड़ी परेशानी बन सकता है। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन हो सकता है। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन अल्कोहल टाक्सिटी का शिकार बना सकता है, जिससे सांस की परेशानी, चेतना की हानि, उल्टी आदि की समस्या हो सकती है।

बालों का हाल: बालों को कृत्रिम रंगों और गुलाल से बचाने का प्रयास करें, अन्यथा बाल रूखे, बेजान हो सकते हैं। कपड़े या टोपी से बालों को ढक लें। कुछ लोग बालों में तेल भी डाल लेते हैं यह तरीका अच्छा है।

बातचीत : सीमा झा

ऐसा हो खानपान

- बाजार की मिठाइयों या भोजन से दूर रहें। गुणवत्ता सही हो तभी उसका सेवन करें।
- लापरवाही भरा खानपान पाचन के लिए समस्या बन सकता है।
- यदि आप मधुमेह, उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो देख लें कि मधुमेह नियंत्रित है या नहीं।
- खानपान में अनियमितता बरतने से आप हाइपरग्लासिमिया के शिकार हो सकते हैं।

आंखों का रखें ध्यान

- आंखों में रंग या गुलाल न जाए, चश्मे का प्रयोग करें।
- कृत्रिम रासायनिक रंग आंखों में चला जाए, तो कार्निया को नुकसान पहुंचा सकता है।
- आंखों में रंग या गुलाल चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धोएं। चिकित्सक से सलाह लें।
- चोट के कारण खून निकल आए तो घबराएं नहीं। पहले सूती कपड़े से आंखों को ढकें।

वायरल से बचें

- सूखे और हर्बल रंगों का प्रयोग करें। अधिक देर तक गीले रंगों या पानी में रहने से बचें। इससे बुखार हो सकता है।
- वायरल संक्रमण होने पर विटामिन सी, विटामिन 12 की गोली ले सकते हैं। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।

सुरक्षित रहे त्वचा

- होली खेलने से पूर्व त्वचा पर माइश्चराइजर क्रीम या नारियल तेल लगा लें।
- धूप तेज हो, तो सनस्क्रीन लगाकर निकलें।
- बचाव के लिए वाटरप्रूफ कपड़े पहन सकते हैं।
- नाखूनों की सुरक्षा के लिए कुछ महिलाएं नेल पेंट लगाती हैं, यह तरीका अच्छा है।
- कृत्रिम रंगों में ब्रोमाइड के अलावा आयरन सल्फाइड, जिंक, निकिल, ब्लैक लेड, आक्साइड, क्रोमियम आयोडाइड, सिल्वर एल्युमिनियम ब्रोमाइड, मर्करी, अमोनिया सहित कई हानिकारक तत्व और धातु मिले होते हैं। इनसे त्वचा की एलर्जी हो या सूजन आ गई हो तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।

आफत न बन जाए स्क्रीन देखने की आदत

पापकार्न ब्रेन

स्क्रीन देखते समय दिमाग किसी चीज पर टिक नहीं पाता, तो संभव है कि पापकार्न ब्रेन सिंड्रोम से ग्रस्त हो गए हों। जानें क्या है यह समस्या और कैसे करें बचाव...

टीवी हो या मोबाइल स्क्रीन, स्क्राल करते रहने के आदी हो चुके हैं। हरदम कुछ नया देखने की इच्छा होती है। दिमाग कहीं टिकता नहीं। संभव है कि पापकार्न सिंड्रोम के शिकार हों। जैसे, कड़ाही में पापकार्न उछलता है, ठीक उसी तरह स्क्रीन देखते समय दिमाग अस्थिर रहता है। इसे ही पापकार्न ब्रेन की स्थिति कहा जाता है।

कम होती एकाग्रता : हर सेकंड दिमाग सूचनाओं की गति के साथ दौड़ना चाहता है। दस साल पूर्व तक इंसान की एक काम पर ध्यान देने की क्षमता 75 सेकंड तक थी जो अब आठ सेकंड मानी जा रही है।

डा. नंद कुमार
प्रोफेसर एवं प्रमुख मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली

व्यापक असर : दिमाग को किसी एक चीज पर टिकना पसंद है। इससे उसे सेंस आफ अचीवमेंट का अहसास होता है। जैसे, तीन मिनट टहलते हैं या कुछ लिख रहे हैं, आप उस पर एकाग्र होते हैं, तो उसका एक लक्ष्य होता है, पर पापकार्न ब्रेन ऐसा करने से रोक देता है। इससे स्मरण शक्ति खराब हो रही है।

हर उम्र की समस्या : जब अटेंशन स्पैन यानी ध्यान बनाए रखने का समय कम हो जाता है तो पापकार्न सिंड्रोम का शिकार माना जा सकता है। हर व्यक्ति की एकाग्रता अलग होती है। यह समस्या हर उम्र में देखी जा रही है।

क्या हैं लक्षण : लंबे समय तक एकाग्रता में कठिनाई, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाना, समझने में कमी आना और हर दिन की जरूरत के काम को पूरा करने में परेशानी होना।

कारण और भी हैं: इंटरनेट मीडिया वजह-बेवजह जोड़े रहता है। हर वक्त नोटिफिकेशन के लिए चौकन्ना रहना भी समस्या का कारण बन रहा है।

चिकित्सक से कब मिलें

- एकाग्रता में परेशानी, संकल्पशक्ति कमजोर पड़ रही हो।
- इंटरनेट मीडिया सामान्य जिंदगी व कामकाज पर प्रभाव डालने लगे।
- बिना फोन जिंदगी कठिन लगे।

ऐसे करें नियंत्रण

- स्वयं समय निश्चित करें। स्क्रीन देखना हो या फोन, नियंत्रण की बागडोर किसी एप को नहीं अपने हाथ में लें।
- प्रोमोडोरो तकनीक अपनाएं। इसमें स्टाप वाच की मदद से फोन देखने व बंद करने की गतिविधि को रोकना है।
- दिमाग को नियंत्रित करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें।
- अपने शौक को समय देना शुरू करें।
- सप्ताह में कम से कम एक दिन के लिए डिजिटल डिटाक्स करें यानी मोबाइल, गैजेट आदि से दूरी बनाएं।

वर्ग पहेली-2579

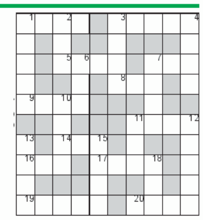

बाएं से दाएं
1 जल्दी चिढ़ने वाला (4)।
3 माथा-पच्ची करना (2,3)।
5 नीला वस्त्र पहनने वाला (4)।
7 प्रलय, लोप, नाश, घुलना (3)।
8 शेर, सिंह, व्याघ्र (3)।
9 उन्मादन, सुंदरता (4)।
11 जिसकी चाह न हो (4)।
14 मुंबई का प्रसिद्ध स्लम (3)।
16 लाड़-प्यार करना (3)।
17 लिखने की मसि, स्याही (4)।
19 कल्पना से परे (5)।
20 खिन्न, उदास, रोगी (4)।

ऊपर से नीचे
1 चिराग या दीया रखने का आधार (5)। 2 फैक्ट्री से धुआं आदि निकालने वाली नली (3)। 3 रोंगटे खड़े होना, ठंड से कांपना (4)। 4 अनुचित, जो जायज न हो (4)। 6 कलंकित, दागदार (3)। 7 निर्माण, बनाना (4)। 10 समस्या का निराकरण (4)। 11 सहारा देना (3)। 12 स्वीकार करना (2,3)। 13 कलाकारी से युक्त (4)। 15 वीरों के लिए उचित कार्य (4)। 18 सच्चाई (3)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

स	रा	ब्रो	र		आ	ल	सी		वि
			क्ष		भा				ना
बा		ब	क	बा	स		वि		श
च				ता			भा	ज	क
क	पी	श		य	म	रा	ज		
		म	स	न	द		न	व	ल
शि	बा	नी			सा				गा
बा		य		म	र	घ	ट		न
ल				ह		मं			
य		श्री	ख	ल		डॉ	र	पो	क

जागरण सुडोकू-2579

	7	9		6		2		1
1					7			5
		2	5			6		
2			7		3	4		8
		3					7	
	4			5				9
9			8			7	1	
		8		7			5	
7			9		5			3

कल का हल

1	9	4	3	5	8	2	6	7
7	8	5	6	2	9	3	4	1
6	3	2	1	7	4	5	8	9
2	7	1	9	4	3	6	5	8
5	4	3	7	8	6	1	9	2
8	6	9	2	1	5	7	3	4
4	1	6	8	3	2	9	7	5
3	2	8	5	9	7	4	1	6
9	5	7	4	6	1	8	2	3

आज का भविष्यफल- 20 मार्च, 2024 बुधवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : फाल्गुनमास शुक्ल पक्ष एकादशी। आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक। दिशाशूल : उत्तर। पर्व एवं त्योहार : एकादशी व्रत।
आज की भद्रा : दोपहर 01 बजकर 23 मिनट से रात्रि 02 बजकर 44 मिनट तक।

कल 21 मार्च, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : दक्षिण
कल का पर्व एवं त्योहार : गोविंद द्वादशी
विशेष : शनि उदय
विक्रम संवत 2080 शके 1945 उत्तरायण, उत्तरगोल, बसंत ऋतु फाल्गुनमास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तत्पश्चात त्रयोदशी आश्लेषा नक्षत्र तत्पश्चात मघा नक्षत्र सुकर्मा योग तत्पश्चात धृति योग कर्क में चंद्रमा तत्पश्चात सिंह में।

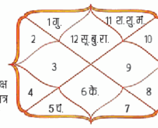

- **मेष :** आर्थिक मामलों में सुधार होगा। शिक्षा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
- **वृष :** रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
- **मिथुन :** शासन का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- **कर्क :** रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वजन का सहयोग रहेगा।
- **सिंह :** दांपत्य जीवन सुखमय होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
- **कन्या :** उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शिक्षा में प्रयास सार्थक होगा।
- **तुला :** घर में सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- **वृश्चिक :** सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।
- **धनु :** व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
- **मकर :** दांपत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक योजना फलीभूत होगी।
- **कुंभ :** उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
- **मीन :** संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा में आशातीत सफलता मिलेगी।

टीबी दिवस (24 मार्च)

सतर्कता ही टीबी से बचाव

डा. रोहित कुमार
एसो. प्रोफेसर, पल्मोनरी मेडिसिन, वीएमएमसी, नई दिल्ली

अगर लगातार बुखार, खांसी की समस्या बनी हुई है, वजन में कमी व थकान हो रही है तो ये सब टीबी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दरअसल, यह बैक्टीरिया जनित एक गंभीर संक्रमण है, जिससे हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। टीबी का संक्रमण फेफड़ों, मस्तिष्क, हड्डियों में हो सकता है। फेफड़ों में टीबी होने पर रक्त के जरिये अन्य अंगों तक फैलाव हो जाता है।

होता क्यों है टीबी : जब टीबी का कोई मरीज खांसता है, तो ड्रापलेट पार्टिकल निकलते हैं। इसके संपर्क में आने पर संक्रमण होने की प्रबल आशंका रहती है। वैसे तो टीबी का जोखिम हर किसी को रहता है, लेकिन संक्रमित होने या न होने के पीछे इम्युनिटी की बड़ी भूमिका रहती है। अगर इम्युनिटी कमजोर होगी, तो टीबी संक्रमण का जोखिम रहेगा।

असावधानी और अस्वच्छता भी कारण : घनी बसावट वाली जगहों पर, जैसे शरणार्थी कैंपों, कारागार आदि में टीबी का ट्रांसमिशन अधिक होता है। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है, तो उसके खांसने से अन्य लोगों को भी टीबी होने की आशंका रहती है। दूसरा, यदि किसी को किडनी, कमजोर लिवर, कैंसर, एचआइवी जैसी कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसे टीबी की प्रबल आशंका रहती है। एक साथ एचआइवी और टीबी के भी बहुत मामले देखने में आते हैं।

बातचीत : ब्रह्मानंद मिश्र

टीबी होने के लक्षण

- लगातार बुखार, भूख में कमी, वजन में गिरावट।
- फेफड़ों में टीबी होने पर खांसी और बलगम में खून आने की समस्या हो सकती है।
- बोन टीबी होने पर हड्डियों में दर्द, लिम्फ नोड टीबी में शरीर में गांठें, ब्रेन टीबी में दौरे, सिरदर्द।

बचाव के उपाय

- बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह गंभीर संक्रमण रोकता है।
- अपनी प्रतिरक्षा मजबूत रखनी चाहिए।
- डायबिटीज है तो इलाज कराएं, सतर्क रहें और शुगर स्तर को नियंत्रित रखें।
- दिनचर्या को नियमित रखें, समय पर भोजन और नींद का पालन जरूर करें।
- टीबी का इलाज बीच में न छोड़ें। ऐसा करने से दवाओं का असर होना बंद हो जाता है, इसलिए इलाज में निरंतरता रखें। आज गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। ये सरकारी स्तर पर निश्शुल्क भी मिलती हैं।

राष्ट्रीय फलक

मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- **हाई कोर्ट ने शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के फैसले को किया रद**
- **कहा, ट्रायल कोर्ट ने आरोपित के विरुद्ध उपलब्ध सुबूतों को नजरअंदाज किया**

हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निचली अदालत ने इसी मामले में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। यह मामला अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन के सहयोगी रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर से संबंधित है।

मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपितों के विरुद्ध उपलब्ध सुबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। हाई कोर्ट ने इसी मामले में 13 अन्य आरोपितों की उम्रकैद की सजा भी बरकरार रखी है। इनमें 12 पुलिसकर्मी एवं एक नागरिक शामिल है। जबकि, छह नागरिकों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में आरोपित रहे एक पुलिस अधिकारी और एक नागरिक की मृत्यु हो चुकी है। दोषसिद्धि के बाद उनके निधन के कारण उन पर मामला समाप्त कर दिया गया है।

हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह में समर्पण करने को कहा है। कोर्ट ने जिन 12 पुलिसकर्मियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है, उनके नाम दिलीप पलांडे, नितिन सरतापे, गणेश हरपुडे, आनंद पटाडे, प्रकाश कदम, देवीदास सकपाल, पांडुरंग कोकम, रत्नाकर कांबले, संदीप सरदार, तानाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी और विनायक शिंदे हैं। यह फैसला जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की बेंच ने सुनाया है।

प्रदीप शर्मा। फाइल

ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्मा को बरी किए जाने का फैसला जुलाई 2013 में आया था। इस मामले की जांच का जिम्मा संभाल रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) का कहना था कि इस मुठभेड़ की योजना शर्मा द्वारा बनाई गई थी। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2006 को लखन भैया का वाशी से अपहरण कर लिया गया था और बाद में फर्जी तरीके से हत्या कर दी गई थी। वर्सोवा में नाना-नानी पार्क के पास हुई इस मुठभेड़ का नेतृत्व प्रदीप शर्मा कर रहे थे।

हाई कोर्ट की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के जज की तीखी आलोचना की है। हाई कोर्ट ने माना है कि सभी परिस्थितियां शर्मा के अपराध की ओर इशारा करती हैं। जबकि, ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ उपलब्ध सभी सुबूतों को नजरअंदाज कर दिया था।

फिल्म 'अब तक छप्पन' उनके चरित्र पर ही आधारित

मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी प्रदीप शर्मा महाराष्ट्र पुलिस बल के 1983 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 113 एनकाउंटर किए हैं। इसलिए उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के मामले में अगस्त 2008 में उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बताया जाता है कि फिल्मकार राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म 'अब तक छप्पन' उनके चरित्र पर ही आधारित है। इस मामले में कुछ समय बाद ही वह बरी हो गए थे। लेकिन, लखन भैया मामले में आरोपित होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और उन्हें पुनः बर्खास्त कर दिया गया था। लखन भैया मामले में 2013 में बरी होने के बाद 2017 में एक बार फिर वह पुलिस सेवा में बहाल हुए और ठाणे में जबरन वसूली सेल के प्रमुख बनाए गए। 2019 में उन्होंने पुलिस सेवा से त्यागपत्र देकर शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन जीत नहीं सके। फिर 2021 में एंटीलिया बम कांड एवं ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। अब उन्हें लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्रकार उनका पूरा करियर विवादों से भरा रहा है।

बदायूं में दो बच्चों की गला काटकर हत्या, पुलिस ने आरोपित जावेद को मुठभेड़ में किया ढेर

जागरण संवाददाता, बदायूं

बदायूं में दो बालकों की हत्या का आरोपित जावेद का फाइल फोटो। सौजन्य : पुलिस

बदायूं में दो बालकों की हत्या के आरोपित जावेद की दुकान में तोड़फोड़ के बाद सामान में लगाई गई आग। जागरण

उप्र के बदायूं में हेयर ड्रेसर जावेद ने छत पर खेल रहे आयुष (12) व भाई अहान (8) की गर्दन काटकर हत्या कर दी। जावेद ने उनके सीने और पेट में ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। चीख सुनकर तीसरा भाई पीयूष छत पर आया तो उसे भी उस्तरे से घायल कर दिया। घटना के बाद जावेद भागा नहीं, चेहरे पर खून लगाकर चीखता रहा। उसे चाकू व उस्तरे दोनों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसे पुलिस चौकी ले गई। उग्र भीड़ ने आरोपित को चौकी से खींचने का किया। भीड़ से बचाने के लिए पुलिस उसे चौकी से थाने ले जाने लगी तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित हमलावर हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जावेद मारा गया।

इससे पहले, दो मासूमों के शव देखकर उग्र भीड़ सड़क पर उतर आई। जावेद की दुकान में तोड़फोड़ की, पड़ोस में एक मुस्लिम की किराना दुकान फूंक दी। स्थिति बेकाबू होने पर पीएसी और पांच थानों से फोर्स बुलाकर भीड़ को खदेड़ा जा सका।

बच्चों के खजन बने रहे थे जावेद के लिए चाय: पुलिस के अनुसार, पड़ोस में किराये की दुकान में जावेद सैलून संचालित करता है। मंगलवार शाम दुकान बंदकर वह 5.30 बजे अचानक ठेकेदार विनोद सिंह के घर पहुंचा। विनोद की मां होमगार्ड मुन्नी देवी ने बताया कि पड़ोसी दुकानदार होने के कारण जावेद से परिचय थे। घर आने का कारण पूछा तो चुप हो गया। इस बीच परिवार की महिलाएं चाय बनाने की बात कहकर कुछ कार्य में व्यस्त हो गईं। वह निगाह बचते ही दबे पांव छत पर गया और खेल रहे विनोद के बेटे आयुष (12), अहान (8) की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। दोनों की चीख सुनकर पीयूष छत पर पहुंचा तो उसके कंधे पर भी उस्तरा मार दिया, वह बचकर नीचे भागा। चंद सेकंड में जावेद भी नीचे आकर चीखने लगा कि दोनों बच्चों को मार डाला है। उनका खून अपने चेहरे पर मलने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि दो बालकों की हत्या पर विनोद के घर में चीख-पुकार मची तो वहां पहुंचे। जावेद दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, पुलिस उसे मंडी चौकी ले गई। रात 8.15 बजे क्षेत्र के दर्जनों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। बवाल होने पर डीएम मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी घटनास्थल पर पहुंचे।

मन, शरीर, हृदय व आत्मा की शुद्धि का अभ्यास है रमजान

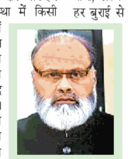

डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, संस्थापक व अध्यक्ष, इंटर फेथहार्मोनीफाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली

रोजा या व्रत हर दौर और हर धार्मिक व्यवस्था में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। रमजान का पवित्र महीना मन, शरीर, हृदय व आत्मा की शुद्धि का एक अभ्यास है। यह माह स्वयं को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर है। रोजे का अर्थ केवल भूखा रहकर अपने आप को तकलीफ देना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य संपन्न होते हुए भी भूखे रहकर उन जरूरतमंदों एवं गरीबों की अवस्था से अवगत होना है जिन्हें दो समय का भोजन नसीब नहीं होता। पूरे दिन कुछ ना खाना-पीना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, हर बुराई से खुद को दूर रखना, गरीब की जरूरत और परेशानी का ध्यान रखना ही रोजे की विशेषताएं हैं। त्याग-करुणा को जीवन में आत्मसात कर अल्लाह के प्रति समर्पित रहना रमजान का वास्तविक सबक है। आशा है कि मुस्लिम समाज इस महीने की रूहानी कार्यशाला से जो कुछ भी प्राप्त करे उसका पालन वह पूरे जीवन करे। इस माह सबकी खुशहाली की दुआ करनी चाहिए।

मेजर ने बनाया कई लक्ष्यों को एक साथ तबाह करने वाला उपकरण, मिला पेटेंट

नई दिल्ली, एएनआइ: सेना के कोर आफ इंजीनियर्स के मेजर राजप्रसाद ने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस (डब्ल्यूईडीसी) के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त कर नवाचार के क्षेत्र में कामयाबी की कहानी लिखी है। यह उपकरण माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रानिक सिस्टम है जिसकी रेंज वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में फायरिंग के साथ 2.5 किलोमीटर है। इसकी मदद से दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ तबाह किया जा सकता है। इस उपकरण को सेना में शामिल किया जा चुका है। भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा, सेना के जवान इस उपकरण की मदद से दूर से ही लक्ष्यों को तबाह कर सकते हैं। इससे जवानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसमें कई अत्याधुनिक खूबियां हैं। पहले उपयोग की गई प्रणाली 400 मीटर की सीमित सीमा वाली वायर्ड प्रणाली है। सेना की सुरक्षा सीमा को बढ़ाने और लंबी दूरी से वायरलेस तरीके से कई लक्ष्यों को ध्वस्त करने की थी। सेना को ऐसे उपकरण की जरूरत थी जो लंबी दूरी से वायरलेस तरीके से कई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम हो।

कर्नल रैंक का अधिकारी होगा नई टेक यूनिट का प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना के संचार ढांचे को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य से गठित नई तकनीकी यूनिट 'सिग्नल्स टेक्नोलाजी इवेल्यूशन एंड एडाप्शन ग्रुप' का प्रमुख सिग्नल कोर से कर्नल रैंक का अधिकारी होगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लगभग 280 कर्मियों वाली यह यूनिट भविष्य की संचार तकनीकों पर शोध एवं उनका मूल्यांकन करेगी। यह यूनिट दिल्ली में स्थित होगी और सिग्नल्स निदेशालय के तहत संचालित होगी। उन्होंने कहा कि यह यूनिट भविष्य के लिए सेना को तैयार करने की दिशा में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने के सेना के विजन 'आन द पाथ टू ट्रांसफारमेशन' के अनुरूप है।

साइबर ठगी के लिए तीन लाख से अधिक विदेशी नागरिकों के डाटा का उपयोग

राज्य ब्यूरो, रांची

- **झारखंड की साइबर अपराध थाने की पुलिस ने किया पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, काल सेंटर सील**
- **विदेशी खुफिया एजेंसी का अधिकारी बनकर विदेशी नागरिकों को धमकाते थे, मंगाते थे रुपये**

झारखंड की साइबर अपराध थाने की पुलिस ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय काल सेंटर के माध्यम से जालसाजों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। साइबर ठगों ने तीन लाख से अधिक विदेशी नागरिकों के डाटा का उपयोग कर ठगी को अंजाम दिया था।

सीआइडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि जालसाजों ने यूनाइटेड किंगडम व आस्ट्रेलिया के तीन लाख से अधिक नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा का ठगी के लिए दुरुपयोग किया। इस डाटा में फोन नंबर, नाम, पता, शहर व देश के पोस्ट कोड और उम्र शामिल हैं। जालसाजों ने इन देशों के नागरिकों को विदेशी खुफिया एजेंसी के नाम पर धमकाया और उनके बैंक खातों से धन की निकासी की। फोन करने के लिए ये कालिंग साफ्टवेयर का प्रयोग करते थे। इनके पास से ब्रिटिश टेलीकाम, वर्जिन मीडिया लिमिटेड, वोडाफोन लिमिटेड के सब्सक्राइबर का नाम, मोबाइल नंबर व पता पाया गया। पुलिस ने इस मामले में काल सेंटर के दो संचालकों रविकांत व मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने काल सेंटर में नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों का सत्यापन कर उनका बयान लिया।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक ऐसे पहुंची पुलिस : रांची के अपर बाजार स्थित किशोरगंज चौक में बीएम हाइट्स नामक बिल्डिंग में साइबर ठगी के लिए काल सेंटर चलाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई। अधिकारियों ने पाया कि रांची में 2021-22 में एक गिरोह काल सेंटर चलाता था। उसके बाद काल सेंटर गोरखपुर शिफ्ट हो गया। गोरखपुर वाले काल सेंटर से ये अपराधी यूनाइटेड किंगडम व आस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अब किशोरगंज में काल सेंटर चलाने लगे और यहां से धोखाधड़ी करने लगे। सीआइडी ने साइबर सेल गोरखपुर व भारतीय अपराध समन्वय केंद्र से संपर्क किया तो पता चला कि कादिर अंसारी व मोहम्मद एकरामुल अंसारी गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए थे। वह जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद रांची के गौरव गुप्ता, विकास, सलोनी, वसीम व रविकांत के साथ मिलकर पिछले करीब एक साल से यूनाइटेड किंगडम व आस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 20 मार्च, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

बृहस्पति, शनि व मंगल के संयोजन से ब्लैक डेथ का जन्म

1345 में आज ही शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह एक सीध में आ गए थे। खगोलविदों के अनुसार इस संयोजन ने ब्लैक डेथ को जन्म दिया था। ब्लैक डेथ एक महामारी थी। इसका प्रकोप यूरोप में 1346 से 1353 तक रहा। इससे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई।

एफडीए ने एड्स की पहली दवा एजेडटी की बिक्री को मंजूरी दी

1987 में आज ही एफडीए (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) ने एजिडोथाइमिडीन (एजेडटी) की बिक्री को मंजूरी दी थी। एजेडटी एड्स की पहली अधिकृत दवा है, जो एड्स रोगियों के जीवन बढ़ाने में मदद करती है। इसे 1964 में डा. जेरोम होरोविट्ज ने कैंसर के संभावित उपचार के रूप में विकसित किया था।

विश्व हिंदी दिवस के प्रणेता डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव

हिंदी के विद्वान डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव का जन्म 1936 में आज ही बिहार के बेतिया में हुआ था। बचपन में ही आरएसएस के संपर्क में आ गए। शिक्षा पूरी कर अध्यापन करने लगे। हिंदी भाषा से लगाव की वजह से अनेक हिंदी सम्मेलनों में भाग लिया। शैलेन्द्रनाथ ने ही तत्कालीन विदेशमंत्री यशवंत सिन्हा को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। संस्कार भारती के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में भी योगदान दिया। 12 फरवरी, 2006 को उनका निधन हो गया।

जल्द तैयार होगा आंधी और ओलावृष्टि सह लेने वाला गेहूं

अखिलेश तिवारी, कानपुर

- बुंदेलखंड, मप्र व राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रख तैयार की गई प्रजाति, पौष्टिक भी अधिक
- सिंचाई नहीं मिलने पर प्रति हेक्टेयर 55 से 60 और वर्षा पर निर्भर रहने पर 40 से 45 क्विंटल तक है उत्पादन

चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में विकसित गेहूं की नई प्रजाति के-1317 कमाल कर रही है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार गेहूं की यह प्रजाति दो वर्ष से ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और अधिक वर्षा के बाद भी बिना किसी नुकसान के भरपूर पैदावार दे रहा है। सिंचाई नहीं मिलने पर भी यह प्रजाति प्रति हेक्टेयर 40 से 45 क्विंटल तक गेहूं की पैदावार में सक्षम है।

इस प्रजाति को बुंदेलखंड, राजस्थान व मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय के शोध कृषि प्रक्षेत्र में फसल को अलग-अलग हिस्से में तैयार किया जा रहा है। एक हिस्से में दो बार सिंचाई की गई और दूसरे हिस्से में प्राकृतिक वर्षा का सहारा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डा. आनंद कुमार सिंह ने फील्ड रिसर्च डे में प्रजाति के गुणों का निरीक्षण किया। कृषि विज्ञानियों ने बताया कि सिंचाई नहीं मिलने पर इस प्रजाति का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 40 से 45 क्विंटल पाया गया, जबकि सिंचाई करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन 55 से 60 क्विंटल है। यह प्रजाति पौष्टिक भी अधिक है।

तैयार होगी गेहूं की नई प्रजाति। फाइल

पोषक तत्वों से भरपूर

सीएसए की के-1317 प्रजाति के गेहूं में भरपूर पोषकता है। गेहूं में 12.5 प्रतिशत प्रोटीन 43.8 पीपीएम आयरन और 38.3 पीपीएम जिंक उपलब्ध है। इससे यह गेहूं एनीमिया रोग के निदान में सहायक है और बच्चों के विकास में भी मदद करता है।

ओलावृष्टि से नहीं खराब हुई फसल

विश्वविद्यालय के फील्ड रिसर्च डे पर फसल को देखने पहुंचे कुलपति डा. आनंद कुमार सिंह ने पाया कि ओलावृष्टि का फसल की बालियों पर कोई असर नहीं है। इसके बारे में पूछने पर विज्ञानियों ने बताया कि पिछले वर्ष भी ओलावृष्टि में यह फसल खराब नहीं हुई। एक भी पौधा जमीन पर नहीं गिरा और उत्पादन भी पूरा मिला है। इस पर कुलपति ने निदेशक प्रसार डा. आरके यादव को प्रजाति को अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।

कुलपति डा. सिंह ने बताया कि प्रतिकूल मौसम से गेहूं की फसल इस वर्ष भी खराब हुई है। खेत पर निरीक्षण के दौरान पाया कि के-1317 फसल पर कोई असर नहीं हुआ। अब किसानों तक इस प्रजाति का बीज पहुंचाया जाएगा जिससे मौसम की प्रतिकूलता में भी उनको नुकसान न हो। सिंचाई कम होने से पानी की खपत कम होती है।

प्रजाति विकसित करने में इन विज्ञानियों की है भूमिका : सीएसए के चार ब्रीडर पूर्व प्रो. एलपी तिवारी, वरिष्ठ ब्रीडर प्रो. विजय कुमार यादव, प्रो. आरके यादव और डा. सोमवीर ने प्रजाति के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

मौतों की त्रासदी

इटली की राजधानी रोम में मंगलवार को पियाजा डेल पापोलो स्थल पर गत्तों के लगभग 1040 ताबूत। इटालियन लेबर यूनियन द्वारा आयोजित 'जीरो डेड एट वर्क' अभियान के दौरान इन ताबूतों को गत एक वर्ष में कार्यस्थल पर जान गंवाने वालों के प्रतीक के रूप में यहां रखा गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर मौतों की त्रासदी पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। रायटर

इधर-उधर की

घर की सफाई कर रही महिला को मिला जिंदा ग्रेनेड

ओटावा, एजेंसी : घर की साफ सफाई के दौरान अक्सर पुरानी चीजे मिल जाती हैं लेकिन कनाडा में केड्रिन ब्राचमैन को अपने पिता के घर की सफाई के दौरान ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल यह एक जिंदा ग्रेनेड था। केड्रिन के पिता की मृत्यु पिछले वर्ष अक्टूबर में हो गई थी। ग्रेनेड की सूचना तुरंत केड्रिन ने पुलिस को दी जिसके बाद कनाडाई सशस्त्र बलों के जवान ग्रेनेड को अपने साथ ले गए। केड्रिन ने बताया कि उनके पिता घर में मौजूद टूल बाक्स को किसी को छूने नहीं देते थे। इसी टूलबाक्स को खोलने पर उन्हें ग्रेनेड मिला। उन्होंने बताया कि लगभग 30 वर्ष पहले मेरे पिता इसे दादाजी से लेकर आए थे।

सशस्त्र बल के जवान ग्रेनेड को अपने साथ ले गए • इंटरनेट मीडिया

माइक्रोप्लास्टिक मैदानी इलाकों के लिए खतरा

गोवा स्थित सीएसआइआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का गंगा व यमुना पर अध्ययन

माइक्रोप्लास्टिक की सबसे अधिक प्रचुरता हरिद्वार में पाई गई और सबसे कम पटना में

पणजी, प्रेट्र : गोवा स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआइओ) द्वारा गंगा व यमुना नदियों पर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि माइक्रोप्लास्टिक में मौजूद पालिमर सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्षों को संबंधित नगर निगमों से भी साझा किया है, ताकि वह इन माइक्रोप्लास्टिक को जलस्रोतों तक पहुंचने से रोका जा सके। साथ ही हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाने के सुझाव भी दिए हैं।

हाल में यह शोध गंगा और यमुना नदियों से मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक का एक व्यापक मूल्यांकनः मौसमी, स्थानिक और जोखिम कारकों का अनावरण' शीर्षक से 'जर्नल आफ हैजर्डस मैटेरियल्स' में प्रकाशित हुआ है।

सीएसआइआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआइओ) के प्रमुख विज्ञानी डा. महुआ साहा के नेतृत्व में टीम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, हरिद्वार से पटना तक गंगा में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला। इसमें शुष्क मौसम की तुलना में बारिश के दिनों में प्रदूषण की सांद्रता अधिक थी। इसमें कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक में उच्च जोखिम वाले पालिमर सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की सबसे अधिक प्रचुरता हरिद्वार में पाई गई और सबसे कम पटना में देखी गई। शोध के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक में ऐसे गुण होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से रेत के प्रवाह की तुलना में उसमें वृद्धि कर सकती है।

नदियों के किनारे मिलने वाला माइक्रोप्लास्टिक। फाइल

छोटे-छोटे टुकड़े हैं माइक्रोप्लास्टिक

माइक्रोप्लास्टिक उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक कचरे के निपटान और टूटने के परिणामस्वरूप पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक मलबे के बेहद छोटे-छोटे टुकड़े हैं।

सिंधु गंगा मैदानी इलाका

सिन्धु-गंगा का मैदान, जिसे उत्तरी मैदानी क्षेत्र तथा उत्तर भारतीय नदी क्षेत्र भी कहा जाता है, एक विशाल एवं उपजाऊ मैदानी इलाका है। इसमें उत्तरी तथा पूर्वी भारत का अधिकांश भाग, पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले भू-भाग, दक्षिणी नेपाल के कुछ भू-भाग तथा लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है।

सिंधु-गंगा का मैदानी इलाका। फाइल

सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का रिसाव आगरा में

शोधकर्ताओं ने जीआईएस अनुप्रयोगों व क्षेत्र सर्वेक्षणों का उपयोग कर प्लास्टिक रिसाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की भी पहचान की। गंगा व यमुना नदियों के सतही जल, जल स्तंभों व तलछट में माइक्रोप्लास्टिक की प्रचुरता गीले और सूखे मौसम के दौरान स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार शुष्क मौसम के दौरान आगरा में माइक्रोप्लास्टिक की प्रचुरता सबसे अधिक थी, जबकि पटना व हरिद्वार में सबसे कम सांद्रता थी। आगरा में सबसे अधिक प्लास्टिक रिसाव दर्ज किया गया, इसके बाद प्रयागराज, पटना और हरिद्वार का स्थान रहा। यह भी देखा गया कि शुष्क मौसम में ऊपर के शहरों से नदी द्वारा अपशिष्ट लाया गया था व बाढ़ क्षेत्र में जमा किया गया था। ये अपशिष्ट बारिश में बह जाते हैं। समय के साथ ये मैक्रोप्लास्टिक छोटे टुकड़ों में विघटित गए होंगे और बाद में शहरी प्रवाह के माध्यम से निकटवर्ती नदी प्रणालियों में पहुंच गए होंगे।

अधिक नमक व कम प्रोटीन के सेवन से हृदय और किडनी रोग का जोखिम

अनुसंधान

एक हालिया अध्ययन में लोगों के आहार में अत्यधिक नमक, कम प्रोटीन व अपर्याप्त पोटैशियम के सेवन का रुझान सामने आया है। शोधकर्ताओं ने इस पर चेताया कि इससे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और गंभीर किडनी रोगों के विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक पोषक तत्व का सेवन करते हैं।

फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में 400 से अधिक वयस्क प्रतिभागियों को शामिल किया गया। ये प्रारंभिक चरण की क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) से पीड़ित थे। अध्ययन में पोषक तत्वों के सेवन का आकलन करने के लिए 24 घंटे के मूत्र उत्सर्जन विश्लेषण का उपयोग किया गया। इस विधि को आहार स्मरण की तुलना में अधिक सटीक माना जाता है। विश्लेषण के लिए मूत्र के नमूनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई। यह अध्ययन चंडीगढ़ में पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआइएमईआर) के सहयोग से द जार्ज इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ इंडिया के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। उत्तर भारतीय आबादी की आहार संबंधी आदतों पर व्यापक अध्ययन सोडियम, पोटैशियम, फास्फोरस और प्रोटीन के सेवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया गया, जो हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी जैसे गैर-संचारी रोगों के विकास के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं। द जार्ज इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ, भारत के कार्यकारी निदेशक और अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रोफेसर विवेकानंद झा ने कहा बताया कि अध्ययन में कुछ चिंताजनक आहार रुझान सामने आए। जिसमें अनुशंसित स्तर से अधिक नमक, अपर्याप्त पोटैशियम और कम प्रोटीन का सेवन शामिल है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

राजामौली के लिए जापानी महिला से मिले उपहार अमूल्य

जापानी प्रशंसक से मिले उपहार के साथ राजामौली। X(ssrajamouli)

राष्ट्र और भाषा की सीमाओं से परे, कुछ फिल्मकारों की कहानियां दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आ जाती हैं कि वह उनके फैन बन जाते हैं। हाल ही में बाहुबली फेम फिल्मकार एस एस राजामौली के साथ कुछ ऐसा ही देखा गया। दरअसल, गत सोमवार को साल 2022 में प्रदर्शित फिल्म आरआरआर की जापान की राजधानी टोक्यो में विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान स्वयं राजामौली ने दर्शकों संग बैठकर फिल्म देखी।

इस स्क्रीनिंग के बाद राजामौली दर्शकों से मिले और उनसे बातें भी की। इस दौरान उनकी फिल्म जापान की एक 83 वर्षीय महिला दर्शक को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने राजामौली को उपहार में 1000 ओरिगामी क्रेन (कागज से बने पक्षी) दे दिया। राजामौली इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने उस महिला और उससे मिले उपहार के साथ तस्वीरें एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, 'जापान में वे ओरिगामी क्रेन बनाते हैं और प्रियजनों को अच्छी किस्मत और सेहत के लिए उपहार में देते हैं। इस 83 वर्षीय महिला ने हमें आशीर्वाद देने के लिए 1000 ओरिगामी क्रेन बनाया क्योंकि आरआरआर ने उन्हें खुश कर दिया। उन्होंने सिर्फ गिफ्ट भेज दिया और बाहर ठंड में इतजार कर रही थी। यह अमूल्य है।' बता दें कि 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली आरआरआर अक्टूबर 2022 में जापान में भी प्रदर्शित की गई थी। तब भी राजामौली जापान गए थे। हालांकि उस दौरान कोराना प्रतिबंधों के कारण वह लोगों से मिल व बात नहीं कर पाए थे।

...तो इसलिए वरुण ने छुए करण के पांव

करण जौहर को अपना गुरू मानते हैं वरुण धवन • एएफपी

फिल्म स्टूडेंट आफ द ईयर से फिल्मकार करण जौहर ने वरुण धवन को लांच किया था। उसके बाद करण निर्मित फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में वरुण ने रंग जमाया। करण को वरुण अपना गुरु मानते हैं। सार्वजनिक तौर पर यह जताने में वह पीछे नहीं रहते। मंगलवार को मुंबई में अमेजन प्राइम वीडियो ने आगामी दो वर्षों के लिए कंटेंट की सूची जारी की। इसमें विभिन्न भाषाओं में लगभग 70 वेब सीरीज और फिल्में शामिल हैं। समारोह की मेजबानी करण जौहर के हाथों में रही। समारोह में अमेरिकन शो सिटाडेल के भारतीय संस्करण सिटाडेट हनी बनी की घोषणा के दौरान शो के क्रिएटर्स राज एंड डीके (राज निदिमोरु और कृष्णा डीके) के साथ कलाकार वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु मौजूद रहे। इस शो से डिजिटल प्लेटफार्म पर डेब्यू करने वाले वरुण ने स्टेज पर आते ही करण के पैर छुए। वरुण ने कहा, 'हर किसी को करण के पैर छूने चाहिए।' करण ने इस पर कहा, 'नहीं, मुझे यहां पर उम्रदराज नहीं लगना है। मैं पहले से ही मिड लाइफ क्राइसेस से गुजर रहा हूं। मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है।' इस पर वरुण ने कहा, 'आपको अहसास नहीं होगा कि करण की उम्र कितनी है, क्योंकि वो डर्मेटोलाजिस्ट के पास जाकर चेहरे पर काम करवा लेते हैं।' इस पर करण ने कहा कि 'मैं उनमें से नहीं हूं।' आगे वरुण ने कहा, 'द फैमिली मैन 2 देखने के बाद मैंने डीके को फोन किया था। मैंने कहा कि आपके काम का फैन हूं, आपके साथ कैसे काम कर सकता हूं। इस पर डीके ने कहा कि अभी सीक्रेट है, लेकिन हम रूसो ब्रदर्स (फिल्म एवेंजर्स : एंड गेम के निर्देशक) के साथ काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि सुपरहीरो या एवेंजर्स जैसा कुछ बना रहे हो क्या? डीके ने कहा कि मैं बता नहीं सकता।' बाद में दोनों साथ में जुड़े। इस शो में सामंथा ने कहा, 'मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं एक्शन कर पाऊंगी।' खास बात यह रही कि करण के प्रोडक्शन हाउस तले बने चार प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, जिसमें ऐ वतन मेरे वतन फिल्म और वेब सीरीज काली मी बे, द ट्राइब और डेयरिंग पार्टनर्स शामिल हैं।

अभिनेत्री कृति सैनन को लेकर वरुण ने छेड़ा टाइगर को

निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इस मौके पर अपनी चार फिल्मों चंदू चैंपियन, सनकी, हाउसफुल 5 और बागी 4 की घोषणा की। जब बागी 4 के कलाकार टाइगर श्राफ से वरुण ने पूछा कि उनके दिल में लड़कियां कैसे जगह बना लेती हैं और क्या वह सिंगल हैं? इस पर टाइगर ने हंसते हुए कहा, 'मैं अपनी पूरी जिंदगी शर्मीला और अंतर्मुखी रहा हूं। जब मैं 25 साल का हुआ, तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी। वह मेरी डेब्यू फिल्म के दौरान मुझे मिली थी। साजिद सर को ही इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। उनकी ही फिल्म थी।' इस पर वरुण ने हंस कर पूछा क्या वो कृति सैनन हैं। फिर खुद ही कह दिया कि यह मजाक था। बागी 4 के एक्शन पर बात करते हुए आगे टाइगर ने कहा, 'बागी फ्रेंचाइज की खास बात यही है कि इसमें लाइव और रा एक्शन होता है। हम एक्शन के लिए किसी हथियार पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसमें किरदार ही हथियार होता है। यही हमारे फ्रेंचाइज के एक्शन को अलग बनाता है।'

करण जौहर ने रणवीर सिंह पर ली चुटकी

रणवीर सिंह

दक्षिण भारतीय अभिनेता राणा दग्गुबाती इस प्लेटफार्म पर अपना चैट शो द राणा कनेक्शन भी लेकर आ रहे हैं। करण जौहर अपने शो काफी विद करण के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हैं। शो के प्रमोशन के लिए राणा ने करण के अंदाज में उनके साथ रैपिड फायर राउंड खेला। हालांकि सवाल-जवाब में अभिनेता रणवीर सिंह फंस गए। राणा ने पूछा कि एक सेलिब्रिटी का नाम बताइए, जो फैशन के मामले में आपसे बेहतर हैं? इस पर करण ने रणवीर पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह रणवीर सिंह हैं, लेकिन तब जब वह अपने सारे कपड़े पहनते हैं।

जी ले जरा में फिर आएगी जान

इन दिनों प्रियंका चोपड़ा हैं मुंबई में। फाइल

कुछ फिल्में घोषणा के बाद सुर्खियां बटोर लेती हैं, लेकिन बाद में किन्ही कारणों से वह ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म जी ले जरा ने सुर्खियां बटोरी थीं। वजह थी फिल्म में पहली बार प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट व कट्रीना कैफ एकसाथ नजर आने वाली थीं। फिल्म की लोकेशन भी फरहान ने देखना आरंभ कर दिया था। फिर तारीखों की समस्या और अन्य कारणों से फिल्म आरंभ नहीं हो पाई। मुंबई आई देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को सोमवार को फरहान के घर जाते हुए देखा गया। उस दौरान उनके पति निक जोनास भी उनके साथ थे। फरहान के घर पर बिजनेस पार्टनर रितेश सिधवानी भी मौजूद थे। वहां से इन कयासों को बल मिला कि जी ले जरा फिल्म को दोबारा शुरू किया जा सकता है। फरहान, फिलहाल रणवीर सिंह के साथ डान 3 बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हालीवुड में हड़ताल के चलते कलाकारों की तारीख मिलने में समस्या आ रही थी, तो मैंने फिल्म को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। जब इसे बनना होगा, तो बनेगी। फिलहाल 22 मार्च को फरहान और रितेश के प्रोडक्शन की फिल्म मडगांव एक्सप्रेस सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म से कुणाल खेमू निर्देशन में कदम रख रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने अगले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट द ब्लफ की घोषणा की है।

इसलिए अपना हर प्रोजेक्ट आखिरी समझ के बनाते हैं रिची

फिल्मकार और कलाकारों के पास विकल्प होता है कि वह अपने किसी एक प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद, उसका फायदा उठाते हुए उसी तरह के कुछ और प्रोजेक्ट भी हासिल कर सकते हैं। वेब सीरीज डेल्ही क्राइम की सफलता के बाद निर्देशक रिची मेहता के पास भी यह विकल्प था। वह फिर क्राइम ड्रामा शो बनाकर नाम और पैसे कमा सकते थे। हालांकि, ऐसा न करते हुए उन्होंने हाथियों के शिकार पर आधारित अपना अगला शो पोचर बनाया। उनका कहना है, 'डेल्ही क्राइम के बाद मुझे कुछ लोग जानने लगे थे, मेरा थोड़ा नाम बन चुका था। मैं आसानी से किसी निर्माता को फोन कर सकता था या किसी डिजिटल प्लेटफार्म को वैसी ही कहानी पिच कर सकता था। फिर मैंने यह सोचा कि अगर यह मेरा आखिरी अवसर हुआ तब भी पोचर ही बनाऊंगा। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है तो मुझे उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैं हर प्रोजेक्ट पर कुछ इस तरह से काम करता हूं जैसे कि वह मेरा आखिरी प्रोजेक्ट हो।' इसके आगे रिची कुछ अन्य शो और डाक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं।

पोचर और डेल्ही क्राइम शो के निर्देशक हैं रिची।

शादी के सवाल पर श्रुति का करारा जवाब

सालार 2 : शौर्यांग पर्वम में फिर नजर आएंगी श्रुति। Instagram(@shrutzhaasan)

इन दिनों बालीवुड में कई सितारे शादी के बंधन में बंध रहे हैं। वहीं कई कलाकार हैं, जो फिलहाल शादी के बंधन से दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन प्रशंसक तो प्रशंसक हैं, उन्हें अपने सितारों से सवाल-जवाब करने से भला कौन रोक पाया है। अभिनेत्री श्रुति हासन मंगलवार को इंस्टाग्राम पर नए म्यूजिक वीडियो पर बातचीत को लेकर लाइव आईं। उनके एक प्रशंसक ने लिखा, 'प्लीज मुझसे अगले जन्म में शादी कर लेना, क्योंकि इस जन्म में तो संभव नहीं है।' इस पर श्रुति ने जवाब देते हुए कहा कि क्यों तुमने यह सोच लिया कि मैं इस लाइफ में शादी कर ही लूंगी। श्रुति इस सवाल से निकलकर कुछ और बोलने ही जा रही थीं कि फिर किसी ने कमेंट कर दिया कि आप शादी करेंगी मैम। इस पर श्रुति ने अंचभित होकर पूछा क्यों? फिर किसी ने पूछ लिया कि विवाहित या अविवाहित आपको क्या होना पसंद है? इस पर श्रुति ने कहा कि फिलहाल तो अविवाहित हूं, तो ठीक ही है। खैर, आगे श्रुति ने नए म्यूजिक वीडियो इनिमल पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि पोस्टर पर रिमोट कंट्रोल क्यों है? इस श्रुति ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि प्यार एक खेल है। इस खेल को हम पूरे दिल से खेलते हैं, इसलिए रिमोट कंट्रोल पोस्टर पर है। श्रुति फिलहाल अपनी दो फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रही हैं। आगामी दिनों में उनकी और प्रभास अभिनीत फिल्म सालार 2 : शौर्यांग पर्वम आएगी।

वार 2 में दिखेगा रितिक का जापानी एक्शन

रितिक रोशन और टाइगर श्राफ अभिनीत फिल्म वार साल 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसकी सीक्वल वार 2 का निर्माण जारी है। वार 2 में रितिक के साथ तेलुगु अभिनेता जूनियर एनटीआर और अभिनेत्री कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में होंगी। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने एक्शन में कुछ नया दिखाने के लिए फिल्म में जापानी शैली का एक्शन शामिल किया है। ऐसे में अब वार 2 में रितिक जापानी एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इसकी कहानी कुछ यूं है कि जासूसी करते हुए फिल्म के नायक कबीर को जापान जाना पड़ता है। जहां उनका सामना जापानी मार्शल आर्ट्स में पारंगत एक व्यक्ति से होगा। इस एक्शन सीक्वेंस में वह जापानी तलवार कटाना के साथ भी कई एक्शन सीन किया है।

वार 2 में जासूसी करते दिखेंगे रितिक रोशन • जागरण आर्काइव

भूल भुलैया 3 में माधुरी की कास्टिंग पर बोले अनीस...

निर्देशक अनीस बज्मी ने हाल ही में भूल भूलैया फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू की है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और राजपाल यादव एक बार फिर अपनी पुरानी भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं फिल्म में अभिनेत्री तृप्ति डिमरी की नई एंट्री हो रही है। वहीं अभिनेत्री विद्या बालन इस फ्रेंचाइजी से दोबारा जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों से यह भी चर्चा थी कि फिल्म से अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी जुड़ सकती हैं। अब इस पर निर्देशक अनीस बज्मी का बयान सामने आया है। अनीस ने फिल्म से माधुरी के जुड़ने या न जुड़ने के संशय को बरकरार रखा। उन्होंने कहा, 'जो भी होगा हम उसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। तृप्ति और विद्या के नाम की घोषणा की गई थी, अभी कई और घोषणाएं बाकी हैं। कुछ को साइन कर लिया गया है तथा कुछ से बातचीत चल रही है। इसके बारे में हम जल्द ही आधिकारिक घोषणा करेंगे।'

अब प्रायोगिक भूमिकाओं को प्राथमिकता दे रही हैं माधुरी • जागरण आर्काइव

****